



Drishti IAS Presents...

PT **SPRINT** 2024

शासन व्यवस्था तथा सामाजिक न्याय

(मार्च 2023 – मार्च 2024)

MCQs

MCQs

MCQs

MCQs

MCQs

MCQs

MCQs

MCQs

MCQs

MCQs

MCQs

Multiple
Choice
Questions
and
Answers

MCQs

MCQs

MCQs

MCQs

MCQs

MCQs

MCQs

MCQs

MCQs

MCQs

MCQs

MCQs

MCQs

MCQs

MCQs

MCQs

MCQs

MCQs

MCQs

Drishti IAS, 641, Mukherjee Nagar,
Opp. Signature View Apartment,
New Delhi

Drishti IAS, 21
Pusa Road, Karol Bagh
New Delhi - 05

Drishti IAS, Tashkent Marg,
Civil Lines, Prayagraj,
Uttar Pradesh

Drishti IAS, Tonk Road,
Vasundhara Colony,
Jaipur, Rajasthan

e-mail: englishsupport@groupdrishti.com, Website: www.drishtias.com

Contact: Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501

प्रश्न और उत्तर

1. पौध किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. प्रजनकों के पास संरक्षित किस्मों का उत्पादन, बिक्री, विपणन, वितरण, आयात या निर्यात करने का विशेष अधिकार नहीं है।
2. शोधकर्ता प्रयोग या अनुसंधान उद्देश्यों के लिये पंजीकृत किस्मों का उपयोग कर सकते हैं।
3. किसानों को संबंधित अधिकारियों या न्यायालयों के समक्ष अधिनियम के तहत कार्यवाही में शुल्क का भुगतान करने से छूट दी गई है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं ?

- A. केवल एक
- B. केवल दो
- C. सभी तीन
- D. इनमें से कोई भी नहीं

उत्तर: B

व्याख्या:

● पौध किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 के तहत अधिकार:

◆ प्रजनकों के अधिकार:

- प्रजनकों को संरक्षित किस्मों का उत्पादन, बिक्री, विपणन, वितरण, आयात या निर्यात करने का विशेष अधिकार दिया जाता है। अतः कथन 1 सही नहीं है।
- ब्रीडर के अधिकारों में एजेंटों अथवा लाइसेंसधारियों को नियुक्त करने और उल्लंघन के लिये नागरिक उपचार प्राप्त करने की क्षमता शामिल है।

◆ शोधकर्ताओं के अधिकार:

- शोधकर्ता प्रयोग या अनुसंधान उद्देश्यों के लिये पंजीकृत किस्मों का उपयोग कर सकते हैं। अतः कथन 2 सही है।
- किसी अन्य किस्म को विकसित करने के लिये किसी किस्म के प्रारंभिक प्रयोग की अनुमति है, लेकिन बार-बार प्रयोग के लिये पंजीकृत ब्रीडर से पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है।

◆ किसानों के अधिकार:

- जिन किसानों ने नई किस्में विकसित की हैं, वे प्रजनकों के समान पंजीकरण और सुरक्षा के हकदार हैं।
- किसान कुछ शर्तों के अधीन संरक्षित किस्मों के माध्यम से कृषि उपज को बचा सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं,

विनियम कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं या बेच सकते हैं।

- पादप आनुवंशिक संसाधनों से संबंधित किसानों के संरक्षण प्रयासों के लिये मान्यता और पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं।
- संरक्षित किस्मों के गैर-प्रदर्शन के मामलों में किसानों के लिये मुआवजे के प्रावधान मौजूद हैं।
- किसानों को संबंधित अधिकारियों या न्यायालयों के समक्ष अधिनियम के तहत कार्यवाही में शुल्क का भुगतान करने से छूट दी गई है। अतः कथन 3 सही है।

2. सिनेमैटोग्राफ (प्रमाणन) नियम, 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. सभी लेन-देन संबंधी विलंब को खत्म करने हेतु पूर्ण डिजिटल प्रक्रियाओं को अपनाने के साथ फिल्म प्रमाणन प्रसंस्करण के लिये समय-सीमा कम कर दी गई है।
2. फिल्मों और फीचर फिल्मों में प्रमाणन के लिये पहुँच सुविधाओं को शामिल किया जाना चाहिये जिससे उन्हें निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार दिव्यांगजनों के लिये भी उपलब्ध किया जा सके।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?

- A. केवल 1
- B. केवल 2
- C. 1 और 2 दोनों
- D. न तो 1 और न ही 2

उत्तर: C

व्याख्या:

सिनेमैटोग्राफ (प्रमाणन) नियम, 2024:

- सभी लेन-देन संबंधी विलंब को खत्म करने हेतु पूर्ण डिजिटल प्रक्रियाओं को अपनाने के साथ, फिल्म प्रमाणन प्रसंस्करण के लिये समय-सीमा कम कर दी गई है। अतः कथन 1 सही है।
 - फिल्मों और फीचर फिल्मों में प्रमाणन के लिये पहुँच सुविधाओं को शामिल किया जाना चाहिये जिससे उन्हें निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार दिव्यांग जनों के लिये भी उपलब्ध किया जा सके। अतः कथन 2 सही है।
3. बँधुआ हाथी (स्थानांतरण या परिवहन) नियम, 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
 1. वर्तमान और संभावित दोनों आवासों की उपयुक्तता को अधिकृत पशुचिकित्सक द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिये।

2. मुख्य वन्यजीव वार्डन के पास अपने विवेक से हाथियों के स्थानांतरण को मंजूरी या अस्वीकार करने का अधिकार है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं ?

- केवल 1
- केवल 2
- 1 और 2 दोनों
- न तो 1 और न ही 2

उत्तर: B

व्याख्या:

बँधुआ हाथी (स्थानांतरण या परिवहन) नियम, 2024 का परिचय:

● बँधुआ हाथियों के स्थानांतरण की परिस्थितियाँ: स्थानांतरण तब हो सकता है, जब:

- ◆ हाथी का मालिक अब हाथी के कल्याण को पर्याप्त रूप से बनाए रखने में सक्षम नहीं है।
- ◆ यदि यह निर्धारित हो जाए, कि हाथी को उसकी वर्तमान स्थिति की तुलना में नई परिस्थितियों में बेहतर देखभाल की जा सकेगी।
- ◆ मुख्य वन्यजीव वार्डन मामले की विशिष्ट परिस्थितियों के आधार पर हाथी के संरक्षण के लिये इसे आवश्यक मान सकते हैं।

● राज्य के अंदर प्रक्रिया:

- ◆ किसी राज्य के अंदर स्थानांतरण से पहले, पशुचिकित्सक द्वारा हाथी के स्वास्थ्य की पुष्टि की जानी चाहिये।
- ◆ वर्तमान और संभावित दोनों आवासों की उपयुक्तता को उप वन संरक्षक द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिये। अतः कथन 1 सही नहीं है।
- ◆ इन आकलनों के आधार पर स्थानांतरण की स्वीकृति या अस्वीकृति मुख्य वन्यजीव वार्डन के विवेक पर निर्भर करती है। अतः कथन 2 सही है।

● राज्य के बाहर की प्रक्रिया:

- ◆ किसी राज्य के बाहर हाथियों को स्थानांतरित करने के लिये भी इसी तरह की शर्तें लागू होती हैं।
- ◆ इसके अतिरिक्त, स्थानांतरण से पहले हाथी की आनुवंशिक प्रोफाइल को MoEF&CC के साथ पंजीकृत किया जाना चाहिये।

4. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

- औषधि और चमत्कारिक उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) अधिनियम, 1954, औषधि विज्ञापनों को नियंत्रित करता है लेकिन चमत्कारिक उपचारों के प्रचार पर प्रतिबंध नहीं लगाता है।

2. अधिनियम के अनुसार तावीज़, मंत्र, कवच और किसी भी अन्य समान वस्तुओं के इस्तेमाल से व्याधियों के उपचार के लिये अलौकिक अथवा चमत्कारिक गुणों का दावा करना "चमत्कारिक उपचार" है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?

- केवल 1
- केवल 2
- 1 और 2 दोनों
- न तो 1 और न ही 2

उत्तर: B

व्याख्या:

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने लोकप्रिय आयुर्वेदिक उत्पाद कंपनी पतंजलि आयुर्वेद को अपने विज्ञापनों में व्याधियों के उपचार के संबंध में झूठे दावे करने के खिलाफ चेतावनी दी।

● औषधि और चमत्कारिक उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) अधिनियम, 1954, औषधि विज्ञापनों को नियंत्रित करता है और कुछ चमत्कारिक उपचारों के प्रोत्साहन पर प्रतिबंध लगाता है। अतः कथन 1 सही नहीं है।

● यह अधिनियम में सूचीबद्ध विशिष्ट व्याधियों के लिये औषधियों के उपयोग का प्रोत्साहन करने वाले और औषधि की प्रकृति अथवा प्रभावशीलता का अनुचित प्रतिनिधित्व करने वाले विज्ञापनों को प्रतिबंधित करता है।

● इसके अतिरिक्त यह उन्हीं व्याधियों के उपचार का दावा करने वाले चमत्कारिक उपचारों के विज्ञापन पर रोक लगाता है।

◆ अधिनियम के अनुसार तावीज़, मंत्र, कवच और किसी भी अन्य समान वस्तुओं के इस्तेमाल से व्याधियों के उपचार के लिये अलौकिक अथवा चमत्कारिक गुणों का दावा करना "चमत्कारिक उपचार" है। अतः कथन 2 सही है।

5. आदर्श आचार संहिता (MCC) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

- MCC मतदान की तारीख से परिणाम की घोषणा तक चालू रहता है।
- MCC के पास कोई वैधानिक समर्थन नहीं है।
- गुजरात चुनाव के लिये आचार संहिता अपनाते वाला पहला राज्य था।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं ?

- केवल एक
- केवल दो
- सभी तीन
- इनमें से कोई भी नहीं

उत्तर: A

व्याख्या:

- आदर्श आचार संहिता (MCC):
 - ◆ MCC एक सर्वसम्मत दस्तावेज़ है। राजनीतिक दल स्वयं चुनाव के दौरान अपने आचरण को नियंत्रित रखने और संहिता के भीतर काम करने पर सहमत हुए हैं।
 - ◆ MCC चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की तारीख से परिणाम की घोषणा की तारीख तक चालू रहता है। अतः कथन 1 सही नहीं है।
 - ◆ संहिता लागू रहने के दौरान सरकार किसी वित्तीय अनुदान की घोषणा नहीं कर सकती, सड़कों या अन्य सुविधाओं के निर्माण का वादा नहीं कर सकती और न ही सरकारी या सार्वजनिक उपक्रम में कोई तदर्थ नियुक्ति कर सकती है।
 - ◆ हालाँकि MCC के पास कोई वैधानिक समर्थन नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग द्वारा इसके सख्त कार्यान्वयन के कारण पिछले दशक में इसे ताकत मिली है। अतः कथन 2 सही है।
 - MCC के कुछ प्रावधानों को भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 जैसे अन्य कानूनों में संबंधित प्रावधानों को लागू करके लागू किया जा सकता है।
 - ◆ केरल चुनाव के लिये आचार संहिता अपनाने वाला पहला राज्य था। वर्ष 1960 में राज्य में विधान सभा चुनावों से पहले, प्रशासन ने जुलूस, राजनीतिक रैलियों और भाषणों जैसे चुनाव प्रचार के महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल करते हुए एक मसौदा संहिता तैयार की। अतः कथन 3 सही नहीं है।
- 6. नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
 1. यह नीति 5 वर्षों के लिये 35,000 अमेरिकी डॉलर या उससे अधिक मूल्य के EV के लिये सीमा शुल्क दर को घटाकर 35% कर देती है।
 2. नीति में आयातित EV की संख्या प्रति वर्ष 10,000 तय की गई है।
 3. स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिये कंपनियों को 5 वर्ष के भीतर परिचालन सुविधाएँ स्थापित करनी होंगी।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं ?

 - A. केवल एक
 - B. केवल दो
 - C. सभी तीन
 - D. इनमें से कोई नहीं

उत्तर: D

व्याख्या:

केंद्र की नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति:

- नीति के मुख्य तथ्य:
 - ◆ EV आयात के लिये शुल्क में कटौती:
 - इस नीति में सीमा शुल्क दर को घटाकर 15% कर दिया गया है (पूरी तरह से नॉकड डाउन- CKD इकाइयों पर लागू) 5 वर्ष की कुल अवधि के लिये 35,000 अमेरिकी डॉलर या उससे अधिक के न्यूनतम CIF (लागत, बीमा और माल ढुलाई) मूल्य वाले EV पर लगाया जाएगा। अतः कथन 1 सही नहीं है।
 - ◆ आयात सीमा और निवेश आवश्यकताएँ:
 - कम शुल्क वाले आयात की अनुमति देते हुए, यह नीति आयातित EV की संख्या प्रति वर्ष 8,000 तक सीमित करती है। अतः कथन 2 सही नहीं है।
 - शुल्क रियायतों का लाभ उठाने के लिये निर्माताओं को न्यूनतम 4,150 करोड़ रुपए (~USD 500 मिलियन) का निवेश करना होगा।
 - अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है, जिससे क्षेत्र में पर्याप्त पूंजी निवेश को प्रोत्साहन मिलता है।
 - ◆ विनिर्माण और मूल्य संवर्द्धन आवश्यकताएँ:
 - स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिये कंपनियों को 3 वर्ष के भीतर परिचालन सुविधाएँ स्थापित करनी होंगी और उसी अवधि के भीतर 25% का न्यूनतम घरेलू मूल्यवर्द्धन (DVA) हासिल करना होगा, जो भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा अनुमोदन-पत्र जारी होने की तारीख से 5 वर्ष के भीतर 50% तक बढ़ जाएगा। अतः कथन 3 सही नहीं है।
 - DVA मूल्य का एक प्रतिशत हिस्सा है जो उस मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है जो एक अर्थव्यवस्था निर्यात के लिये उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं में जोड़ती है।
- 7. उत्तरी अटलांटिक के लिये रक्षा नवाचार त्वरक (DIANA) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
 1. DIANA एक उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) द्वारा स्थापित संगठन है, जिसका उद्देश्य पूरे गठबंधन में दोहरे उपयोग वाली नवाचार क्षमता को विकसित करना है।
 2. इसने हाल ही में नागरिक और रक्षा दोनों उद्देश्यों के लिये प्रौद्योगिकी, नवाचार तथा व्यवसाय विकास को बढ़ावा देने के लिये फिनलैंड में एक त्वरक एवं दो परीक्षण केंद्र स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं ?

- A. केवल 1
- B. केवल 2
- C. 1 और 2 दोनों
- D. न तो 1 और न ही 2

उत्तर: C

व्याख्या:

- DIANA एक उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन द्वारा स्थापित संगठन है, जिसका उद्देश्य संपूर्ण गठबंधन में दोहरे उपयोग वाली नवाचार क्षमता में तीव्रता लाना है। यह कंपनियों को महत्वपूर्ण सुरक्षा चुनौतियों के लिये गहन तकनीक विकसित करने हेतु संसाधन, नेटवर्क और मार्गदर्शन प्रदान करता है। अतः कथन 1 सही है।
- हाल ही में डिफेंस इनोवेशन एक्सेलेरेटर फॉर द नॉर्थ अटलांटिक (DIANA) पहल बोर्ड ने नागरिक और रक्षा दोनों उद्देश्यों हेतु प्रौद्योगिकी, नवाचार तथा व्यवसाय विकास को बढ़ावा देने के मिशन के साथ फिनलैंड में एक एक्सेलेरेटर एवं दो परीक्षण केंद्र स्थापित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। अतः कथन 2 सही है।

सभी नाटो देश DIANA के सदस्य हैं। DIANA निदेशक मंडल शासन के लिये जिम्मेदार है और इसमें प्रत्येक सहयोगी देश के प्रतिनिधि शामिल हैं।

8. उत्तर-पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगीकरण योजना (उन्नति), 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. योजना की कुल लागत 10,037 करोड़ रुपए है, जिसमें प्रतिबद्ध देनदारियों के लिये अतिरिक्त 8 वर्षों के साथ 10 वर्ष की अवधि शामिल है।
 2. जनजातीय कार्य मंत्रालय राज्यों के साथ मिलकर इस योजना को लागू करेगा।
- उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?
- A. केवल 1
 - B. केवल 2
 - C. 1 और 2 दोनों
 - D. न तो 1 और न ही 2

उत्तर: A

व्याख्या:

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर-पूर्व क्षेत्र के राज्यों में उद्योगों के विकास और रोजगार सृजन के लिये उत्तर-पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगीकरण योजना (Uttar Purva Transformative Industrialization Scheme- UNNATI), 2024 को मंजूरी दी।

● उद्देश्य:

- ◆ इसका उद्देश्य उत्तर-पूर्व क्षेत्र के राज्यों में उद्योगों का विकास और रोजगार सृजन करना है।
- ◆ यह सीमेंट और प्लास्टिक जैसे पर्यावरणीय रूप से हानिकारक क्षेत्रों को प्रतिबंधित करते हुए निवेश को आकर्षित करने, मौजूदा निवेशों का पोषण करने तथा नवीकरणीय/अक्षय ऊर्जा एवं इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों जैसे उद्योगों को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
- ◆ योजना की पूरी लागत रुपए 10,037 करोड़ जिसे प्रतिबद्ध देनदारियों के लिये दस वर्षों एवं अतिरिक्त आठ वर्षों में विभाजित किया गया है। अतः कथन 1 सही है।
- ◆ उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग राष्ट्रीय और राज्य-स्तरीय समितियों की देखरेख में राज्यों के सहयोग से योजना को लागू करेगा। अतः कथन 2 सही नहीं है।

9. भारत में स्वयं सहायता समूहों (SHG) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. भारत में SHG मॉडल वर्ष 1994 में वर्गीस कुरियन से प्रेरित होकर प्रस्तुत किया गया था।
2. SHG-बैंक लिंकेज प्रोग्राम (SHG-BLP) वर्ष 1989 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा शुरू किया गया था।
3. लखपति दीदी एक सरकारी पहल है जिसका उद्देश्य SHG में महिलाओं को स्थायी आजीविका प्रथाओं के माध्यम से प्रति वर्ष कम-से-कम 3,00,000 रुपए कमाने के लिये सशक्त बनाना है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं ?

- A. केवल एक
- B. केवल दो
- C. सभी तीन
- D. इनमें से कोई भी नहीं

उत्तर: A

व्याख्या:

● स्वयं सहायता समूह (SHG):

- ◆ स्वयं सहायता समूह (SHG) समान सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों के अनौपचारिक संघ हैं जिनका लक्ष्य निर्धनता, अशिक्षा और कौशल की कमी जैसे सामान्य मुद्दों का सामूहिक रूप से समाधान करना है।
- ◆ ये समूह हाशिये पर जीवन यापन करने वाले समुदायों के भीतर स्व-रोजगार और निर्धनता उन्मूलन को बढ़ावा देते हुए स्व-शासन तथा सहकर्मी समर्थन को प्रोत्साहन देते हैं।

- ◆ भारत में SHG मॉडल प्रोफेसर यूनुस के ग्रामीण बैंक मॉडल से प्रेरित होकर वर्ष 1984 में प्रस्तुत किया गया था। अतः कथन 1 सही नहीं है।
- ◆ केरल में कुटुंबश्री, महाराष्ट्र में महिला आर्थिक विकास महामंडल और लूमस ऑफ लदाख सफल SHG के कुछ उदाहरण हैं।
 - लूमस ऑफ लदाख एक 427 महिला SHG सदस्यों वाला एक पश्मीना ब्रांड है जिसका बिक्री वित्त वर्ष 2022-23 में 34 लाख रुपए और वर्ष 2023-24 के प्रारंभिक 10 माह में 42 लाख रुपए रही जो इसके विक्रय में हुई तीव्र वृद्धि को दर्शाता है।
- SHG-बैंक लिंकेज प्रोग्राम (SHG-BLP)
 - ◆ वर्ष 1989 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा शुरू किया गया SHG-BLP, वर्ष 1992 तक एक एक्शन रिसर्च से एक पायलट प्रोजेक्ट में बदल गया। अतः कथन 2 सही है।
 - भारतीय रिज़र्व बैंक और नाबार्ड के समर्थन से SHG, बैंकों तथा गैर सरकारी संगठनों के बीच इस सहयोगात्मक प्रयास का उद्देश्य वंचित गरीब परिवारों को वित्तीय सेवाएँ प्रदान करना है।
 - समय के साथ यह विश्व की सबसे बड़ी माइक्रोफाइनेंस परियोजना बन गई है जो लगभग 16.19 करोड़ परिवारों, मुख्य रूप से महिला समूहों लाभान्वित कर समग्र देश में महिलाओं को सशक्त बनाता है।
 - नाबार्ड के प्रयासों में नीति समर्थन, प्रशिक्षण कार्यक्रम और सभी हितधारकों के लिये क्षमता निर्माण शामिल हैं जो इस बचत-आधारित माइक्रोफाइनेंस मॉडल की सफलता में योगदान दे रहे हैं।
- SHG और लखपति दीदी का उदय:

भारत में स्वयं सहायता समूह, जिनकी संख्या लगभग 8.5 मिलियन है और जिनमें लगभग 92.1 मिलियन सदस्य हैं, एक परिवर्तनकारी क्रांति का नेतृत्व कर रहे हैं।

 - इस गति का एक उल्लेखनीय परिणाम लखपति दीदियों का बढ़ता अनुपात है।
 - लखपति दीदी एक सरकारी पहल है जिसका उद्देश्य SHG में महिलाओं को स्थायी आजीविका प्रथाओं के माध्यम से प्रति वर्ष कम-से-कम 1,00,000 रुपए कमाने के लिये सशक्त बनाना है। अतः कथन 3 सही नहीं है।

- यह कार्यक्रम वर्ष 2023 में 2 करोड़ महिलाओं के प्रारंभिक लक्ष्य के साथ शुरू किया गया था, लेकिन सत्र 2024-25 में लक्ष्य को बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया गया है।

10. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. CDSCO औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अंतर्गत केंद्र सरकार को सौंपे गए कार्यों के निर्वहन के लिये केंद्रीय औषधि प्राधिकरण है।
2. CDSCO के अनुसार नई दवाओं का निर्माण अब केंद्रीय लाइसेंस अनुमोदन प्राधिकरण की मंजूरी के बिना बिक्री के लिये किया जा सकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?

- A. केवल 1
- B. केवल 2
- C. 1 और 2 दोनों
- D. न तो 1 और न ही 2

उत्तर: A

व्याख्या:

केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन द्वारा अस्वीकृत दवाओं के निर्माण एवं बिक्री, विशेष रूप से "नई दवाओं" के उपयोग, के संबंध में एक चेतावनी जारी की है।

- विशेष रूप से मेरोपेनेम, एक जीवाणुरोधी एजेंट तथा डिसोडियम EDTA जैसी दवाएँ जो कैल्शियम की अधिकता का उपचार करने के लिये उपयोग की जाती हैं, को ऐसी अस्वीकृत दवाओं के उदाहरण के रूप में उजागर किया गया था।
- CDSCO ने इस बात पर जोर दिया कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी की मंजूरी के बिना बिक्री के लिये किसी भी नई दवा का निर्माण नहीं किया जाना चाहिये। अतः कथन 2 सही नहीं है।
- CDSCO **औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940** के अंतर्गत केंद्र सरकार को सौंपे गए कार्यों के निर्वहन के लिये केंद्रीय औषधि प्राधिकरण है। अतः कथन 1 सही है।
- CDSCO के प्रमुख कार्यों में दवाओं के आयात पर नियामक नियंत्रण, नई दवाओं एवं नैदानिक परीक्षणों की मंजूरी के साथ-साथ केंद्रीय लाइसेंस अनुमोदन प्राधिकरण के रूप में कुछ लाइसेंसों की मंजूरी भी शामिल है।

11. जन औषधि केंद्रों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. यह रसायन और उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्युटिकल्स विभाग की प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (PMBJP) योजना के तहत संचालित होता है।

2. यह ब्रांडेड दवाओं की तुलना में काफी कम कीमत पर जेनेरिक दवाएँ प्रदान करता है, जिससे स्वास्थ्य देखभाल पर आपकी जेब से कम खर्च सुनिश्चित होता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही नहीं है/हैं ?

- A. केवल 1
B. केवल 2
C. 1 और 2 दोनों
D. न तो 1 और न ही 2

उत्तर: D

व्याख्या:

- जन औषधि केंद्र (JAKs) जनता को सस्ती एवं गुणवत्तापूर्ण दवाएँ उपलब्ध कराने के लिये शुरू की गई एक सरकारी पहल है।
- ◆ ये रसायन और उर्वरक मंत्रालय के औषधि विभाग की प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (PMBJP) योजना के तहत काम करते हैं। अतः कथन 1 सही है।
- ◆ जन औषधि योजना, जिसे सितंबर 2015 में प्रधानमंत्री जन औषधि योजना (PMJAY) के रूप में नवीनीकृत किया गया, का उद्देश्य विशेष रूप से निर्धनों तथा वंचितों के लिये किफायती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण दवाएँ उपलब्ध कराना है।
- ◆ नवंबर 2016 में, इस योजना में और सुधार किया गया तथा इसके प्रभाव को मजबूत करने के लिये इसका नाम बदलकर PMBJP कर दिया गया।
- ◆ PMBJP, जन औषधि केंद्रों के नाम से जाने जाने वाले विशेष आउटलेट के माध्यम से जेनेरिक दवाएँ उपलब्ध कराने पर केंद्रित है।
- ◆ ये स्टेर ब्रांडेड दवाओं की तुलना में काफी कम कीमत पर जेनेरिक दवाएँ उपलब्ध कराते हैं, जिससे स्वास्थ्य देखभाल पर आपकी जेब से होने वाला खर्च कम हो जाता है। अतः कथन 2 सही है।

12. निम्नलिखित पहलों पर विचार कीजिये:

1. आकांक्षी जिला कार्यक्रम
2. समग्र जल प्रबंधन सूचकांक
3. SDG भारत सूचकांक

उपर्युक्त में से कितने का नेतृत्व नीति आयोग द्वारा किया जाता है ?

- A. केवल एक
B. केवल दो
C. सभी तीन
D. इनमें से कोई भी नहीं

उत्तर: C

व्याख्या:

नीति आयोग की सभी राज्यों में विकास को बढ़ावा देने वाली पहल:

- **राज्यों के लिये विकास सहायता सेवाएँ:** नीति आयोग सफल बुनियादी ढाँचे के निर्माण को सुनिश्चित करने के लिये योजना निर्माण, वित्तपोषण और कार्यान्वयन में सहायता करता है।
 - ◆ इसका उद्देश्य बड़े विकास एजेंडे का समर्थन करने वाले शासन उपकरण के रूप में **सार्वजनिक-निजी भागीदारी** स्थापित करना भी है।
 - **आकांक्षी जिला कार्यक्रम:** इसका लक्ष्य देश भर के 112 सबसे अविक्सित जिलों को शीघ्र एवं प्रभावी रूप से परिवर्तित करना है।
 - नीति आयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और बुनियादी ढाँचे में मुख्य मेट्रिक्स में सुधार के लिये उनके साथ कार्य करता है।
 - **समग्र जल प्रबंधन सूचकांक:** यह भारत में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों (UT) के जल क्षेत्र की स्थिति तथा जल प्रबंधन प्रदर्शन का वार्षिक स्लैपशॉट (आशुचित्र) प्रदान करता है।
 - **SDG भारत सूचकांक:** यह सूचकांक संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में भारत की प्रगति को ट्रैक करता है।
 - ◆ यह राज्यों को उन क्षेत्रों की पहचान करने के लिये मूल्यवान डेटा प्रदान करता है जिन पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है और सहयोगात्मक कार्रवाई को बढ़ावा देता है।
 - **मानव पूंजी परिवर्तन के लिये सतत कार्रवाई:** इसे स्कूली शिक्षा क्षेत्र के लिये तीन 'रोल मॉडल' राज्यों की पहचान करने और निर्माण करने के लिये वर्ष 2017 में लॉन्च किया गया था।
 - ◆ इसके लिये झारखंड, ओडिशा और मध्य प्रदेश को चुना गया।
 - **अटल इनोवेशन मिशन:** इसका उद्देश्य समग्र देश में स्कूल, विश्वविद्यालय, अनुसंधान संस्थानों, MSME और उद्योग स्तरों पर नवाचार और उद्यमिता का एक पारितंत्र विकसित करना तथा प्रोत्साहन प्रदा करना है।
- अतः विकल्प C सही है।
13. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
- कथन-I: गुरुमुखी लिपि को शारदा लिपि से विकसित किया गया था, जिसे दसवें सिख गुरु, गुरु गोविंद सिंह द्वारा मानकीकृत और उपयोग किया गया था।
- कथन-II: प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (PM VI-KAS) योजना रोजगार-उन्मुख नौकरी भूमिकाओं में आधुनिक कौशल प्रशिक्षण के लिये 10,000 सिख युवाओं और महिलाओं को लक्षित करती है।

उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा सही है ?

- कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं तथा कथन-II कथन-I की सही व्याख्या है।
- कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं तथा कथन-II कथन-I की सही व्याख्या नहीं है।
- कथन-I सही है, किंतु कथन-II गलत है।
- कथन-I गलत है, किंतु कथन-II सही है।

उत्तर: D

व्याख्या:

- गुरुमुखी लिपि का विकास शारदा (Śāradā) लिपि से हुआ था जिसका उपयोग और मानकीकरण दूसरे सिख गुरु, गुरु अंगद द्वारा किया गया था। शारदा लिपि ब्राह्मी परिवार की लिपियों से संबंधित है। अतः कथन-I सही नहीं है।
- इस कार्यक्रम का उद्देश्य सिख समुदाय के भीतर सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों की सहायता करना और सांप्रदायिक एवं सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देना है। इस कार्यक्रम के तहत सिख समुदाय की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं को संरक्षित तथा प्रोत्साहन प्रदान करने के लिये दिल्ली विश्वविद्यालय के खालसा महाविद्यालयों में अत्याधुनिक गुरुमुखी लिपि शिक्षण केंद्र स्थापित किये जाएंगे।
- यह कार्यक्रम सिख समुदाय के कल्याण के लिये स्थापित एक वैधानिक निकाय, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति (DSGMC) के माध्यम से प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (PM विकास) योजना के अंतर्गत "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास" पहल का हिस्सा है।
 - यह कार्यक्रम 10,000 युवाओं और महिलाओं को ध्यान में रखकर शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य रोजगार प्रदान करने वाली भूमिकाओं में आधुनिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना, सिख कारीगरों को प्रोत्साहन देना, महिला नेतृत्व और उद्यमिता को बढ़ावा देना तथा स्कूल छोड़ने वाली छात्राओं को शिक्षा के लिये प्रोत्साहन प्रदान करना है। अतः कथन-II सही नहीं है।

अतः कथन-I गलत है, लेकिन कथन-II सही है।

14. FASTag के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

- यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संचार परिषद् (NCSTC) द्वारा संचालित है।

- यह एक उपकरण है जो वाहन के चलते समय सीधे टोल भुगतान करने के लिये रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) तकनीक का उपयोग करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?

- केवल 1
- केवल 2
- 1 और 2 दोनों
- न तो 1 और न ही 2

उत्तर: B

व्याख्या:

- FASTag एक उपकरण है जो वाहन के चलते समय सीधे टोल भुगतान करने के लिये रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक का उपयोग करता है। अतः कथन 2 सही है।
- फास्टैग (RFID टैग) वाहन की विंडस्क्रीन पर चिपकाया जाता है और ग्राहक को फास्टैग से जुड़े खाते से सीधे टोल भुगतान करने में सक्षम बनाता है।
 - इसका संचालन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की देखरेख में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। अतः कथन 1 सही नहीं है।

15. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

- फेयर ट्रायल प्रोग्राम (FTP) दिल्ली में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय पर आधारित एक आपराधिक न्याय पहल है। FTP का लक्ष्य विचाराधीन कैदियों के लिये निष्पक्ष परीक्षण सुनिश्चित करना है।
- FTP राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के साथ सहयोग करने हेतु वकीलों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं जैसे युवा पेशेवरों को प्रशिक्षण एवं सलाह देता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?

- केवल 1
- केवल 2
- 1 और 2 दोनों
- न तो 1 और न ही 2

उत्तर: C

व्याख्या:

- सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जाँच ब्यूरो, 2022 के मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति, भारत की जमानत प्रणाली की अक्षमता और विचाराधीन कैदियों के संकट को बढ़ाने में इसकी भूमिका पर प्रकाश डालती है।
 - यह मान्यता आपराधिक न्याय प्रणाली के भीतर प्रणालीगत चुनौतियों का समाधान करने के लिये जमानत कानूनों में सुधार की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करती है।

- फेयर ट्रायल प्रोग्राम (FTP) दिल्ली में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय पर आधारित एक आपराधिक न्याय पहल है। FTP का लक्ष्य विचाराधीन कैदियों के लिये निष्पक्ष परीक्षण सुनिश्चित करना है। अतः कथन 1 सही है।
- FTP राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के साथ सहयोग करने हेतु वकीलों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं जैसे युवा पेशेवरों को प्रशिक्षण एवं सलाह देता है। अतः कथन 2 सही है।

16. हाल ही में लॉन्च किये गए डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (DIP) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. यह एक सुरक्षित मंच है जो दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, कानून प्रवर्तन एजेंसियों (LEA) आदि जैसे हितधारकों के बीच खुफिया जानकारी साझा करने और सूचना विनियम की सुविधा प्रदान करता है।
2. यह "दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (TSP), LEA, बैंकों और वित्तीय संस्थानों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों, पहचान दस्तावेज जारी करने वाले प्राधिकरणों आदि के लिये एक गैर-सार्वजनिक डेटा-साझाकरण संसाधन होगा।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?

- A. केवल 1
- B. केवल 2
- C. 1 और 2 दोनों
- D. न तो 1 और न ही 2

उत्तर: C

व्याख्या:

डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (Digital Intelligence Platform - DIP):

- DIP दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, कानून प्रवर्तन एजेंसियों (LEA), बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के व्यापक स्पेक्ट्रम को कवर करने वाले हितधारकों के बीच खुफिया जानकारी साझा करने के साथ-साथ सूचना विनियम के माध्यम से दूरसंचार संसाधनों तथा डेटा के दुरुपयोग को रोकने के लिये DoT द्वारा बनाया गया एक सुरक्षित और एकीकृत मंच है। अतः कथन 1 सही है।
 - यह "दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (TSP), LEA, बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों, पहचान दस्तावेज जारी करने वाले प्राधिकरणों आदि के लिये एक गैर-सार्वजनिक डेटा-साझाकरण संसाधन होगा। अतः कथन 2 सही है।
17. भांडागारण विकास और नियामक प्राधिकरण (WDRA) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. यह खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के तहत एक वैधानिक प्राधिकरण है।
2. किसानों के भंडारण रसद को आसान बनाने और उनकी उपज के लिये उचित मूल्य सुनिश्चित करने की दिशा में प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिये WDRA की ई-किसान उपज निधि (डिजिटल गेटवे) लॉन्च की गई।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?

- A. केवल 1
- B. केवल 2
- C. 1 और 2 दोनों
- D. न तो 1 और न ही 2

उत्तर: C

व्याख्या:

- उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री ने किसानों के भंडारण रसद को आसान बनाने तथा उनकी उपज हेतु उचित मूल्य सुनिश्चित करने की दिशा में प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिये भांडागारण विकास और नियामक प्राधिकरण की 'ई-किसान उपज निधि' (डिजिटल गेटवे) लॉन्च किया। अतः कथन 2 सही है।
- WDRA की स्थापना अक्टूबर 2010 में भांडागारण (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2007 के तहत की गई थी, जिसका उद्देश्य गोदामों को विकसित और विनियमित करना, गोदाम रसीदों की परक्राम्यता को बढ़ावा देना एवं भारत में भंडारण व्यवसाय के व्यवस्थित विकास को सुविधाजनक बनाना था।
- WDRA खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के तहत एक वैधानिक प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।
- ◆ यह भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के अंतर्गत एक वैधानिक प्राधिकरण है। अतः कथन 1 सही है।

18. भारत टेक्स 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. यह भारत के प्रधानमंत्री के 5F विजन से प्रेरित भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम है।
2. यह 'इनोवेटिव बिजनेस प्रैक्टिस एंड इकोनॉमिक मॉडल इन द टेक्सटाइल वैल्यू चेन इन इंडिया' (IndiaTex) और टेक्सटाइल ग्रैंड इनोवेशन चैलेंज जैसी पहल के लिये लॉन्चपैड के रूप में कार्य करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?

- A. केवल 1
- B. केवल 2
- C. 1 और 2 दोनों
- D. न तो 1 और न ही 2

उत्तर: C

व्याख्या:

- प्रधानमंत्री के 5F विज्ञान से प्रेरित भारत में सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम **भारत टेक्स- 2024** भारत मंडपम, नई दिल्ली में संपन्न हुआ। अतः कथन 1 सही है।
- ◆ '5F' फॉर्मूला में फार्म टू फाइबर; फाइबर टू फैक्ट्री; फैक्ट्री टू फैशन; फैशन टू फॉरेन शामिल हैं।
- भारत टेक्स ने 'इनोवेटिव बिज़नेस प्रैक्टिस एंड इकोनॉमिक मॉडल इन द टेक्सटाइल वैल्यू चेन इन इंडिया' (**IndiaTex**) और टेक्सटाइल ग्रैंड इनोवेशन चैलेंज जैसी पहल के लिये लॉन्चपैड के रूप में काम किया, जिसका लक्ष्य वस्त्र उद्योग में नवाचार तथा स्थिरता को बढ़ावा देना है। अतः कथन 2 सही है।
- ◆ इंडियाटेक्स एक चार-वर्षीय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम परियोजना है जिसका उद्देश्य भारतीय वस्त्र क्षेत्र को सर्कुलरिटी की ओर ले जाने में तेजी लाना है।

19. राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. इसकी स्थापना राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, 2010 के तहत की गई थी।
2. वर्तमान में NGT की बैठक के लिये नई दिल्ली प्रमुख स्थान है, भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई को ट्रिब्यूनल की बैठक के अन्य चार स्थानों के रूप में नामित किया गया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?

- A. केवल 1
- B. केवल 2
- C. 1 और 2 दोनों
- D. न तो 1 और न ही 2

उत्तर: C

व्याख्या:

राष्ट्रीय हरित अधिकरण:

- स्थापना: राष्ट्रीय हरित अधिकरण (**National Green Tribunal- NGT**) की स्थापना अक्टूबर, 2010 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के तहत की गई थी। अतः कथन 1 सही है।
- ◆ इसका प्राथमिक उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, वनों के संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के त्वरित एवं कुशल समाधान की सुविधा प्रदान करना है।
- ◆ वर्तमान में NGT की बैठक के लिये नई दिल्ली प्रमुख स्थान है, भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई को ट्रिब्यूनल की बैठक के अन्य चार स्थानों के रूप में नामित किया गया है। अतः कथन 2 सही है।

● संरचना:

- ◆ अधिकरण का अध्यक्ष इसका प्रमुख होता है जो प्रधान पीठ का पद धारण करता है और इसमें न्यूनतम 10 किंतु 20 से अधिक न्यायिक सदस्य तथा विशेषज्ञ सदस्य होते हैं।
- ◆ अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा की जाती है।
- ◆ न्यायिक सदस्यों और विशेषज्ञ सदस्यों की नियुक्ति के लिये केंद्र सरकार द्वारा एक चयन समिति का गठन किया जाता है।

20. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

कथन-I: प्रसार भारती भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक प्रसारण एजेंसी है। यह प्रसार भारती अधिनियम, 1997 द्वारा स्थापित एक वैधानिक स्वायत्त निकाय है।

कथन-II: सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रसार भारती - प्रसारण तथा प्रसार के लिये साझा ऑडियो विजुअल (**PB-SHABD**) को प्रारंभ किया, जो प्रसार भारती की एक समाचार-साझाकरण सेवा है, जिसका उद्देश्य भारत में समाचार प्रसार में बदलाव लाना है।

उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा सही है ?

- A. कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं, तथा कथन-II, कथन-I के लिये सही व्याख्या है।
- B. कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं, तथा कथन-II, कथन-I के लिये सही नहीं व्याख्या है।
- C. कथन-I सही है, किंतु कथन-II गलत है।
- D. कथन-I गलत है, किंतु कथन-II सही है।

उत्तर: B

व्याख्या:

- प्रसार भारती भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक प्रसारण एजेंसी है। यह प्रसार भारती अधिनियम, 1997 द्वारा स्थापित एक वैधानिक स्वायत्त निकाय है। अतः कथन I सही है।
- प्रसार भारती निगम का मुख्य उद्देश्य जनता को शिक्षित करने के साथ-साथ मनोरंजन करने के लिये दूरदर्शन एवं आकाशवाणी को स्वायत्तता प्रदान करना है।
- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रसार भारती - प्रसारण तथा प्रसार के लिये साझा ऑडियो विजुअल (**PB-SHABD**) को प्रारंभ किया, जो प्रसार भारती की एक समाचार-साझाकरण सेवा है, जिसका उद्देश्य भारत में समाचार प्रसार में बदलाव लाना है। अतः कथन II सही है।

- ◆ PB-SHABD व्यापक नेटवर्क की कमी वाले छोटे समाचार संगठनों के लिये समाचार सामग्री के एकल-बिंदु स्रोत के रूप में कार्य करेगा।
- इसलिये, विकल्प B सही है क्योंकि कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं, तथा कथन-II कथन-I के लिये सही व्याख्या नहीं है।

21. इकोसाइड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. इसे इस प्रकार परिभाषित किया गया है, कि "इस ज्ञान के साथ किये गए गैरकानूनी या अनियंत्रित कृत्य कि उन कृत्यों के कारण पर्यावरण को गंभीर और व्यापक या दीर्घकालिक क्षति होने की पर्याप्त संभावना है।"

2. बेल्जियम यूरोपीय महाद्वीप का पहला देश है, जिसने 'इकोसाइड' को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अपराध के रूप में मान्यता दी है।

उपर्युक्त में से कौन-सा कथन सही नहीं है/हैं ?

- A. केवल 1
- B. केवल 2
- C. 1 और 2 दोनों
- D. न तो 1 और न ही 2

उत्तर: D

व्याख्या:

● इकोसाइड:

◆ इकोसाइड को "गैरकानूनी या अनियंत्रित कृत्यों के रूप में परिभाषित किया गया है, जो इस जानकारी के साथ किये गए हैं कि उन कृत्यों के कारण पर्यावरण को गंभीर और व्यापक या दीर्घकालिक क्षति होने की पर्याप्त संभावना है। अतः कथन 1 सही है।

■ यह परिभाषा स्टॉप इकोसाइड फाउंडेशन द्वारा गठित इकोसाइड की कानूनी व्याख्या करने वाले स्वतंत्र विशेषज्ञ पैनल द्वारा प्रदान की गई थी।

◆ इकोसाइड को पर्यावरणीय अपराध का एक रूप माना जाता है और यह प्रायः जैवविविधता, पारिस्थितिकी तंत्र तथा मानव कल्याण पर महत्वपूर्ण नकारात्मक प्रभावों से संबंधित है।

■ पारिस्थितिकी-संहार को एक अपराध के रूप में मान्यता प्रदान करने का उद्देश्य व्यक्तियों और निगमों को उनके कार्यों के लिये जवाबदेह बनाना तथा आगे के पर्यावरणीय क्षरण को रोकना है।

◆ 12 देशों में पारिस्थितिकी-संहार एक अपराध है और देश ऐसे कानूनों पर विचार कर रहे हैं, जो जान-बूझकर की गई पर्यावरणीय

क्षति को अपराध की श्रेणी में रखते हैं, जो मनुष्यों, जानवरों तथा पौधों की प्रजातियों को नुकसान पहुँचाती है।

■ बेल्जियम की संघीय संसद ने 'इकोसाइड' को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अपराध के रूप में मान्यता प्रदान की है, जिसके कारण यह यूरोपीय महाद्वीप का पहला देश बन गया है। अतः कथन 2 सही है।

■ यह कानून निर्णय लेने वाली शक्तियों और निगमों में बैठे व्यक्तियों को लक्षित करता है, जिसका उद्देश्य व्यापक तेल रिसाव जैसे गंभीर पर्यावरणीय क्षरण को रोकना तथा दंडित करना है।

22. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. SWAYAM बहुभाषी विषय वस्तु, AI मार्गदर्शन, क्रेडिट रिकग्निशन जैसी सुविधाओं के साथ रोजगार क्षमता को बढ़ावा देने के लिये उद्योग-प्रासंगिक पाठ्यक्रम प्रदान करता है।

2. SWAYAM शिक्षार्थियों के लिये शैक्षिक अवसर प्रदान करने वाला व्यापक ओपन ऑनलाइन कोर्स (MOOC) प्लेटफॉर्म है, जिसे वर्ष 2017 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था।

3. स्वयं-प्लस को राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के साथ जोड़ा गया है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही नहीं है/हैं ?

- A. केवल एक
- B. केवल दो
- C. सभी तीन
- D. इनमें से कोई भी नहीं

उत्तर: D

व्याख्या:

● SWAYAM प्लस अब रोजगार क्षमता को बढ़ावा देने के लिये उद्योग-प्रासंगिक पाठ्यक्रम प्रदान करता है, जिसमें बहुभाषी विषय वस्तु, AI मार्गदर्शन, क्रेडिट रिकग्निशन और रोजगार के मार्ग जैसी सुविधाएँ शामिल हैं, जो L&T, माइक्रोसॉफ्ट, CISCO जैसी और भी अन्य कंपनियों के सहयोग से विकसित की गई हैं। अतः कथन 1 सही है।

● बड़ी संख्या में शिक्षार्थियों के लिये शैक्षिक अवसर प्रदान करने वाला व्यापक ओपन ऑनलाइन कोर्स (Massive Open Online Course- MOOC) प्लेटफॉर्म SWAYAM वर्ष 2017 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। अतः कथन 2 सही है।

● स्वयं-प्लस (Swayam-Plus) को राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के साथ संरेखित किया गया है। अतः कथन 3 सही है।

23. 'गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM)' के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. GeM विभिन्न सरकारी विभागों/संगठनों/PSU द्वारा आवश्यक सामान्य उपयोग की वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद की सुविधा प्रदान करता है।
2. यह सरकारी उपयोगकर्ताओं और निजी क्षेत्रों की सुविधा के लिये ई-बोली, रिवर्स ई-नीलामी व मांग एकत्रीकरण के टूल्स प्रदान करता है।
3. GeM ने विभिन्न श्रेणियों जैसे SARAS, ट्राइब्स इंडिया, स्टार्टअप रनवे, खादी इंडिया, इंडिया हैंडीक्राफ्ट आदि के लिये आउटलेट स्टोर लॉन्च किये हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं ?

- A. केवल एक
- B. केवल दो
- C. सभी तीन
- D. इनमें से कोई भी नहीं

उत्तर: B

व्याख्या:

● सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM):

- ◆ GeM विभिन्न सरकारी विभागों/संगठनों/PSU द्वारा आवश्यक सामान्य उपयोग की वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद की सुविधा प्रदान करता है। अतः कथन 1 सही है।
- ◆ यह सरकारी उपयोगकर्ताओं की सुविधा के लिये ई-बोली, रिवर्स ई-नीलामी और मांग एकत्रीकरण के टूल्स प्रदान करता है। अतः कथन 2 सही नहीं है।
- ◆ GeM ने विभिन्न श्रेणियों के उत्पादों जैसे SARAS, आजीविका, ट्राइब्स इंडिया, स्टार्टअप रनवे, खादी इंडिया, इंडिया हैंडलूम, इंडिया हैंडीक्राफ्ट, दिव्यांगजन आदि के लिये बिक्री केंद्र लॉन्च किये हैं। अतः कथन 3 सही है।

24. विधिविरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम (UAPA), 1967 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. UAPA द्वारा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को देश भर में मामलों की जाँच करने और मुकदमा चलाने का अधिकार दिया गया है।
2. UAPA के तहत गिरफ्तार व्यक्तियों की सजा दर 20% से अधिक है।
3. यह अधिनियम सरकार को बिना किसी न्यायिक समीक्षा के व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित करने का अधिकार देता है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं ?

- A. केवल एक
- B. केवल दो
- C. सभी तीन
- D. इनमें से कोई भी नहीं

उत्तर: A

व्याख्या:

● विधिविरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम (UAPA), 1967:

- ◆ UAPA एक कानून है जिसका उद्देश्य अवैध गतिविधियों को रोकना और आतंकवाद से निपटना है। इसे "आतंकवाद विरोधी कानून" के नाम से भी जाना जाता है।
- ◆ राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) को देशभर में मामलों की जाँच करने और मुकदमा चलाने का अधिकार UAPA द्वारा दिया गया है। अतः कथन 1 सही नहीं है।
- ◆ UAPA के तहत वर्ष 2018 और 2020 के बीच 4,690 लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन केवल 3% को दोषी ठहराया गया। अतः कथन 2 सही नहीं है।
- ◆ इसमें वर्ष 2004, 2008, 2012 और हाल ही में वर्ष 2019 में कई संशोधन हुए, जिसमें आतंकवादी वित्तपोषण, साइबर-आतंकवाद, व्यक्तिगत पदनाम तथा संपत्ति ज़बती से संबंधित प्रावधानों का विस्तार किया गया।
 - वर्ष 2019 का संशोधन सरकार को बिना किसी न्यायिक समीक्षा के व्यक्तियों को आतंकवादी के रूप में नामित करने का अधिकार देता है, जिससे कानून की उचित प्रक्रिया और मनमाने ढंग से पदनाम की संभावना के बारे में चिंताएँ बढ़ जाती हैं। अतः कथन 3 सही है।

25. लोक लेखा समिति (PAC) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. यह समिति तीन वित्तीय संसदीय समितियों में से एक है, अन्य दो प्राक्कलन समिति एवं सार्वजनिक उपक्रम समिति हैं।
2. इसका गठन भारत के संविधान के अनुच्छेद 308 के तहत प्रतिवर्ष किया जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?

- A. केवल 1
- B. केवल 2
- C. 1 और 2 दोनों
- D. न तो 1 और न ही 2

उत्तर: A

व्याख्या:

लोक लेखा समिति (PAC):

- यह तीन वित्तीय संसदीय समितियों में से एक है, अन्य दो प्राक्कलन समिति एवं सार्वजनिक उपक्रम समिति हैं। अतः कथन 1 सही है।
 - अनुच्छेद 105 (संसद सदस्यों के विशेषाधिकारों के संबंध में) एवं अनुच्छेद 118 (प्रक्रिया और व्यावसायिक आचरण को नियंत्रित करने वाले नियम स्थापित करने हेतु संसद के अधिकार के संबंध में) संसदीय समितियों के लिये अधिकार के स्रोत हैं।
 - लोक लेखा समिति की शुरुआत वर्ष 1921 में भारत सरकार अधिनियम, 1919 में पहली बार उल्लेख के बाद की गई थी, जिसे मॉटफोर्ड सुधार भी कहा जाता है।
 - लोक सभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम-308 के तहत वर्तमान में प्रतिवर्ष लोक लेखा समिति का गठन किया जाता है। अतः कथन 2 सही नहीं है।
26. निर्भया फंड के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिये:
1. इसका उद्देश्य विशेष रूप से महिलाओं के बचाव और सुरक्षा में सुधार के लिये परियोजनाएँ हैं।
 2. यह एक नॉन-लैप्सेबल कॉर्पस फंड है।
 3. इसका संचालन मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।
- उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं ?
- A. केवल एक
 - B. केवल दो
 - C. सभी तीन
 - D. इनमें से कोई भी नहीं

उत्तर: B

व्याख्या:

निर्भया फंड:

- इसका उद्देश्य विशेष रूप से महिलाओं के बचाव और सुरक्षा में सुधार के लिये परियोजनाएँ हैं। अतः कथन 1 सही है।
 - यह एक नॉन-लैप्सेबल कॉर्पस फंड है। अतः कथन 2 सही है।
 - निर्भया फंड का संचालन केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। अतः कथन 3 सही नहीं है।
27. 'भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
1. यह सर्वोच्च न्यायालय को उसके समक्ष लंबित किसी मामले अथवा वाद में पूर्ण न्याय करने के लिये आवश्यक कोई भी डिक्ली अथवा आदेश पारित करने का अधिकार देता है।

2. यह संविधान के अनुच्छेद 32 सहित कई अन्य प्रावधानों द्वारा समर्थित है।
3. यह सर्वोच्च न्यायालय को जनहित, मानवाधिकार, संवैधानिक मूल्यों या मौलिक अधिकारों से जुड़े मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार देता है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही नहीं हैं ?

- A. केवल एक
- B. केवल दो
- C. सभी तीन
- D. इनमें से कोई भी नहीं

उत्तर: D

व्याख्या:

- अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को उसके समक्ष लंबित किसी मामले अथवा वाद में पूर्ण न्याय करने के लिये आवश्यक कोई भी डिक्ली अथवा आदेश पारित करने का अधिकार देता है। अतः कथन 1 सही है।
 - ◆ ये डिक्ली अथवा आदेश न्यायिक हस्तक्षेप के लिये महत्वपूर्ण साधन हैं क्योंकि इन्हें भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में कार्यान्वित किया जा सकता है।
 - कई अन्य कानून जैसे कि अनुच्छेद 32 (जो संवैधानिक उपचारों के अधिकार की गारंटी देता है), अनुच्छेद 141 (जिसके लिये सभी भारतीय न्यायालयों को सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का पालन करना आवश्यक है) तथा अनुच्छेद 136 (जो विशेष अनुमति याचिका की अनुमति देता है), अनुच्छेद 142 को समर्थन प्रदान करते हैं। अतः कथन 2 सही है।
 - यह प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय को सार्वजनिक हित, मानवाधिकार, संवैधानिक मूल्यों अथवा मौलिक अधिकारों से जुड़े मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार देता है। अतः कथन 3 सही है।
 - ◆ यह संविधान के संरक्षक के रूप में न्यायालय की भूमिका को सुदृढ़ करता है और साथ ही उल्लंघनों के विरुद्ध सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
28. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
- कथन-I: भारतीय बार काउंसिल को विनियमित करने और प्रतिनिधित्व करने के लिये अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के तहत संसद द्वारा बनाई गई एक वैधानिक संस्था है।
- कथन-II: वर्ष 2023 में, BCI ने विदेशी वकीलों और कानून फर्मों को बिना शर्त भारत में प्रैक्टिस करने की अनुमति दी।

उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा सही है ?

- कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं तथा कथन-II कथन-I की सही व्याख्या है।
- कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं तथा कथन-II कथन-I की सही व्याख्या नहीं है।
- कथन-I सही है, लेकिन कथन-II गलत है।
- कथन-I गलत है, लेकिन कथन-II सही है।

उत्तर: C

व्याख्या:

- भारतीय बार काउंसिल को विनियमित करने और प्रतिनिधित्व करने के लिये अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के तहत संसद द्वारा बनाई गई एक वैधानिक संस्था है। अतः कथन I सही है।
- वर्ष 2023 में BCI ने विदेशी वकीलों और विधि संस्थाओं को भारत में गैर-मुकदमा संबंधी गतिविधियों जैसे कॉर्पोरेट कानून तथा बौद्धिक संपदा मामलों में विधि-व्यवसाय करने की अनुमति प्रदान दी। अतः कथन II सही नहीं है।
- ◆ उन्हें संपत्ति अंतरण अथवा स्वामित्व अन्वेषण संबंधी कार्यों से प्रतिबंधित किया गया।
- ◆ विदेशी फर्मों में भारतीय वकीलों को समान प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है।
- अतः विकल्प C सही है क्योंकि कथन-I सही है, लेकिन कथन-II गलत है।

29. इंटरपोल नोटिस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

- ब्लू नोटिस एक "पूछताछ नोटिस" है, जो सदस्य राज्यों में पुलिस बलों को महत्वपूर्ण अपराध-संबंधी जानकारी का आदान-प्रदान करने में सक्षम बनाता है।
- ब्लू कॉर्नर नोटिस आपराधिक आरोप दायर करने से पहले जारी किये जाते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?

- केवल 1
- केवल 2
- 1 और 2 दोनों
- न तो 1 और न ही 2

उत्तर: C

व्याख्या:

इंटरपोल नोटिस:

- इंटरपोल अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से निपटने के लिये राष्ट्रीय पुलिस बलों के लिये एक महत्वपूर्ण सूचना-साझाकरण नेटवर्क के रूप में कार्य करता है।
- नोटिस के प्रकार: लाल, पीला, नीला, काला, हरा, नारंगी, बैंगनी और इंटरपोल-संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद विशेष सूचना।
- ब्लू नोटिस: "पूछताछ नोटिस" के रूप में संदर्भित, सदस्य राज्यों में पुलिस बलों को अन्य विवरणों के साथ-साथ किसी व्यक्ति के आपराधिक रिकॉर्ड एवं स्थान की पुष्टि करने सहित महत्वपूर्ण अपराध-संबंधी जानकारी का आदान-प्रदान करने में सक्षम बनाता है। अतः कथन 1 सही है।
- ◆ ब्लू कॉर्नर नोटिस आपराधिक आरोप दायर करने से पहले जारी किये जाते हैं। अतः कथन 2 सही है।
- रेड नोटिस: किसी वांछित अपराधी को प्रत्यर्पण या अन्य कानूनी तरीकों से गिरफ्तार के लिये किसी सदस्य राज्य द्वारा जारी किया जाता है, गिरफ्तारी वारंट या न्यायालय के निर्णय के बाद अभियोजन अथवा सजा देने के लिये राष्ट्रीय न्यायालयों द्वारा मांगे गए व्यक्तियों को लक्षित किया जाता है।

30. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

- स्वच्छ सर्वेक्षण आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) द्वारा आयोजित विश्व का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता और सफाई सर्वेक्षण है।
- स्वच्छ सर्वेक्षण के प्रमुख पैरामीटर हैं डोर-टू-डोर अपशिष्ट संग्रहण, स्रोत पृथक्करण, सार्वजनिक क्षेत्रों की सफाई, स्वच्छ जल निकाय और शहर की सफाई पर नागरिकों की प्रतिक्रिया।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?

- केवल 1
- केवल 2
- 1 और 2 दोनों
- न तो 1 और न ही 2

उत्तर: C

व्याख्या:

स्वच्छ सर्वेक्षण:

- MoHUA द्वारा वर्ष 2016 से आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण, विश्व का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता और सफाई सर्वेक्षण है। अतः कथन 1 सही है।

- यह नागरिकों को सेवा वितरण में सुधार लाने और शहर को स्वच्छ बनाने की दिशा में कस्बों तथा शहरों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देने में सहायक रहा है।
- ◆ इंदौर ने लगातार 7वें वर्ष अपना शीर्ष स्वच्छ शहर का खिताब बरकरार रखा है। हाल के वर्षों में इंदौर के बाद लगातार दूसरे स्थान पर रहने वाले सूरत ने पहली बार शीर्ष स्थान का पुरस्कार प्राप्त किया है।
- ◆ दोनों शहरों ने 100% डोर-टू-डोर अपशिष्ट संग्रहण, 98% स्रोत पृथक्करण और 100% अपशिष्ट निपटान का लक्ष्य प्राप्त किया।
- **मूल्यांकन में प्रमुख मापदंड:**
 - ◆ डोर-टू-डोर अपशिष्ट संग्रहण
 - ◆ स्रोत पृथक्करण
 - ◆ सार्वजनिक क्षेत्रों की स्वच्छता
 - ◆ स्वच्छ जल निकास
 - ◆ शहर की स्वच्छता पर नागरिकों की प्रतिक्रिया
 - ◆ अतः कथन 2 सही है।

31. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. भारत का परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 'परमाणु ऊर्जा' के विषय को नियंत्रित करता है, जिसमें भारत सरकार परमाणु सुविधाओं के विकास, संचालन और सेवा मुक्ति में केंद्रीय भूमिका निभाती है।
2. भारत की समेकित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) नीति, परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में 75% तक विदेशी निवेश की अनुमति देती है।

ऊपर दिये गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?

- A. केवल 1
- B. केवल 2
- C. 1 और 2 दोनों
- D. न तो 1 और न ही 2

उत्तर: A

व्याख्या:

- भारत का परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 'परमाणु ऊर्जा' के विषय को नियंत्रित करता है, जिसमें भारत सरकार परमाणु सुविधाओं के विकास, संचालन एवं सेवा मुक्ति में केंद्रीय भूमिका निभाती है। अतः कथन 1 सही है।
- भारत की समेकित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) नीति परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में विदेशी निवेश पर रोक लगाती है। अतः कथन 2 सही नहीं है।

- इसके विपरीत, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों और अन्य संबंधित सुविधाओं के लिये परमाणु उपकरण एवं भागों के निर्माण के लिये उद्योग में FDI पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

- हाल ही में नीति आयोग (नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया) पैनल ने भारत सरकार को भारत के परमाणु क्षेत्र में FDI की अनुमति देने की सिफारिश की।

32. 'सी-केयर्स वेब पोर्टल' के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. इसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (C-DAC) द्वारा विकसित किया गया है, जो MeitY के अंतर्गत एक अनुसंधान और विकास संगठन है।
2. यह भावी निधि ग्राहकों और कोयला कंपनियों को दावों के ऑनलाइन निपटान सहित विभिन्न कार्य करने में सक्षम बनाएगा। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही नहीं है/हैं ?

- A. केवल 1
- B. केवल 2
- C. 1 और 2 दोनों
- D. न तो 1 और न ही 2

उत्तर: D

व्याख्या:

हाल ही में कोयला मंत्रालय (MoC) ने कोयला खदान भविष्य निधि संगठन (CMPFO) का C-CARES वेब पोर्टल लॉन्च किया।

- C-CARES वेब पोर्टल को सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (C-DAC) द्वारा विकसित किया गया है, जो MeitY के अंतर्गत एक अनुसंधान और विकास संगठन है, यह पोर्टल CMPFO ग्राहकों तथा पेंशनभोगियों के अभिलेखों के रखरखाव के साथ ही सुव्यवस्थित प्रक्रियाओं के लिये प्रतिबद्ध है।
- CMPFO कोयला क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा के लिये भविष्य निधि एवं पेंशन योजनाओं के प्रशासन के लिये MoC के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन है। अतः कथन 1 सही है।
- ◆ संगठन वर्तमान में कोयला क्षेत्र के लगभग 3.3 लाख भविष्य निधि ग्राहकों और 6.1 लाख पेंशनभोगियों को सेवाएँ प्रदान कर रहा है।
- सी-केयर्स CMPF ग्राहकों और कोयला कंपनियों को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न कार्य करने में सक्षम बनाएगा, जिसमें दावों का ऑनलाइन निपटान, कागज रहित कामकाज, दावों का समय पर तथा सटीक निपटान, प्रसंस्करण समय में कमी एवं शिकायत निवारण शामिल है।
- यह डिजिटल परिवर्तन डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण के अनुरूप है। अतः कथन 2 सही है।

33. 'राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (NCGG)' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. एनसीजीजी अप्रकी क्षेत्र के सिविल सेवकों के लिये सार्वजनिक नीति और शासन पर एक उन्नत नेतृत्व विकास कार्यक्रम आयोजित करता है।
2. इसकी स्थापना वर्ष 2014 में सरकार द्वारा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत एक शीर्ष स्तर की स्वायत्त संस्था के रूप में की गई थी।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही नहीं है/हैं ?

- A. केवल 1
- B. केवल 2
- C. 1 और 2 दोनों
- D. न तो 1 और न ही 2

उत्तर: D

व्याख्या:

- राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (NCGG) ने हाल ही में अप्रकी क्षेत्र के सिविल सेवकों के लिये सार्वजनिक नीति और शासन पर अपना उन्नत नेतृत्व विकास कार्यक्रम संपन्न किया। अतः कथन 1 सही है।
- ◆ यह भूमि प्रशासन, सतत् विकास और सार्वजनिक नीति प्रथाओं पर केंद्रित था तथा इसमें इरिट्रिया, केन्या, इथियोपिया, तंज़ानिया एवं गाम्बिया के अधिकारियों ने भाग लिया, इस कार्यक्रम का उद्देश्य सहयोग के साथ ज्ञान के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना था।
- NCGG की स्थापना वर्ष 2014 में सरकार द्वारा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत एक शीर्ष स्तरीय स्वायत्त संस्थान के रूप में की गई थी। अतः कथन 2 सही है।

34. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

कथन-I: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत कार्य करते हुए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) भारत में खाद्य सुरक्षा तथा गुणवत्ता का विनियमन व पर्यवेक्षण करके सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा एवं प्रोत्साहन के लिये उत्तरदायी है।

कथन- II: वर्ष 2006 के अधिनियम में खाद्य पदार्थों से संबंधित विभिन्न कानून शामिल हैं, जैसे कि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954, फल उत्पाद आदेश, 1955, मांस खाद्य उत्पाद आदेश, 1973 और विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा प्रबंधित अन्य अधिनियम।

उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा सही है ?

- A. कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं, और कथन-II कथन-I की सही व्याख्या है।
- B. कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं, और कथन-II कथन-I की सही व्याख्या नहीं है।
- C. कथन-I सही है, लेकिन कथन-II गलत है।
- D. कथन-I गलत है, लेकिन कथन-II सही है।

उत्तर: B

व्याख्या:

- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत कार्य करते हुए FSSAI भारत में खाद्य सुरक्षा तथा गुणवत्ता का विनियमन व पर्यवेक्षण करके सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा एवं प्रोत्साहन के लिये उत्तरदायी है। अतः कथन 1 सही है।
- वर्ष 2006 के अधिनियम में खाद्य पदार्थों से संबंधित विभिन्न कानून शामिल हैं, जैसे कि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954, फल उत्पाद आदेश, 1955, मांस खाद्य उत्पाद आदेश, 1973 और विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा प्रबंधित अन्य अधिनियम। अतः कथन 2 सही है।
- कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। कथन 2 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के संबंध में है न कि FSSAI के कार्य के बारे में।

अतः विकल्प B सही है।

35. जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) संशोधन विधेयक, 2024 के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. यह जल प्रदूषण से संबंधित छोटे-मोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने, तकनीकी अथवा प्रक्रियात्मक खामियों के लिये कारावास की आशंकाओं को कम करने पर केंद्रित है।
2. यह केंद्र सरकार को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के अध्यक्षों के नामांकन के लिये दिशा-निर्देश निर्धारित करने का अधिकार देता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?

- A. केवल 1
- B. केवल 2
- C. 1 और 2 दोनों
- D. न तो 1 और न ही 2

उत्तर: C

व्याख्या:

जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) संशोधन विधेयक, 2024:

- प्रमुख संशोधित उपबंध:
 - ◆ छोटे अपराधों का गैर-अपराधीकरण करना: इसका उद्देश्य तकनीकी अथवा प्रक्रियात्मक खामियों के लिये कारावास की आशंकाओं को समाप्त करते हुए जल प्रदूषण से संबंधित छोटे अपराधों का गैर-अपराधीकरण (Decriminalization) करना है।

■ यह सुनिश्चित करता है कि दंड अपराधों की गंभीरता के अनुरूप हों तथा हितधारकों को अत्यधिक प्रभावित किये बिना अनुपालन को बढ़ावा दिया जाए।

■ अतः कथन 1 सही है।

◆ विशेष औद्योगिक संयंत्रों के लिये छूट: यह संशोधित विधेयक केंद्र सरकार को विशेष प्रकार के औद्योगिक संयंत्रों के लिये अतिरिक्त बिक्री केंद्र और निर्वहन के संबंध में धारा 25 में सूचीबद्ध कुछ वैधानिक प्रतिबंधों से छूट प्रदान करने का अधिकार देता है।

■ इस प्रावधान का उद्देश्य नियामक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना और निगरानी प्रयासों के दोहराव को कम करना तथा दक्षता को बढ़ावा देते हुए नियामक एजेंसियों पर अनावश्यक बोझ को कम करना है।

◆ उन्नत नियामक निरीक्षण: इसमें राज्यों में नियामक निरीक्षण तथा मानकीकरण को बढ़ाने के उपाय शामिल किये गए हैं।

■ यह केंद्र सरकार को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के अध्यक्षों के नामांकन के लिये दिशा-निर्देश निर्धारित करने और उद्योग से संबंधित सहमति देने, इनकार करने या रद्द करने के निर्देश जारी करने का अधिकार देता है। अतः कथन 2 सही है।

■ यह अध्यक्षों की निष्पक्ष नियुक्ति सुनिश्चित करने के लिये कुछ अनिवार्य योग्यताएँ, अनुभव और प्रक्रियाएँ प्रदान करता है।

36. नज़ूल भूमि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. नज़ूल भूमि पर सरकार का स्वामित्व होता है किंतु अमूमन इसे प्रत्यक्ष रूप से राज्य संपत्ति के रूप में प्रशासित नहीं किया जाता है।
2. राज्य आम तौर पर ऐसी भूमि को 1 से 9 वर्ष तक की संक्षिप्त अवधि के लिये पट्टे पर आवंटित करता है।
3. नज़ूल भूमि (हस्तांतरण) नियम, 1956 वह कानून है जिसका उपयोग अधिकतर नज़ूल भूमि निर्णय के लिये किया जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं ?

- A. केवल एक
- B. केवल दो
- C. सभी तीन
- D. इनमें से कोई भी नहीं

उत्तर: B

व्याख्या:

● नज़ूल भूमि:

◆ नज़ूल भूमि पर सरकार का स्वामित्व होता है किंतु अमूमन इसे प्रत्यक्ष रूप से राज्य संपत्ति के रूप में प्रशासित नहीं किया जाता है। अतः कथन 1 सही है।

◆ राज्य आम तौर पर ऐसी भूमि को किसी भी इकाई को 15 से 99 वर्ष के बीच एक निश्चित अवधि के लिये पट्टे पर आवंटित करता है। अतः कथन 2 सही नहीं है।

◆ कई राज्यों ने नज़ूल भूमि के लिये नियम बनाने के उद्देश्य से सरकारी आदेश जारी किये हैं किंतु नज़ूल भूमि (स्थानांतरण) नियम, 1956 वह कानून है जिसका उपयोग ज्यादातर नज़ूल भूमि निर्णय के लिये किया जाता है। अतः कथन 3 सही है।

37. भारत के एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉम्पिक्स तथा एक्सटेंडेड रियलिटी (AVGC-XR) क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. वर्तमान में, भारत वैश्विक AVGC-XR क्षेत्र के कुल उत्पादन का 7% हिस्सा साझा करता है।
2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 AVGC-XR उद्योग में प्रतिभा को निखारने के लिये एक अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?

- A. केवल 1
- B. केवल 2
- C. 1 और 2 दोनों
- D. न तो 1 और न ही 2

उत्तर: B

व्याख्या:

भारत के AVGC-XR क्षेत्र:

● AVGC-XR क्षेत्र, वर्तमान में 2.6 लाख व्यक्तियों को रोजगार देता है, वर्ष 2032 तक 23 लाख प्रत्यक्ष नौकरियाँ पैदा करने का अनुमान है, साथ ही राजस्व वर्ष 2030 तक मौजूदा 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 26 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक होने की उम्मीद है।

● सरकारी आँकड़ों के अनुसार, वैश्विक AVGC-XR क्षेत्र में भारत का योगदान मात्र 0.5% है, भारत में लगभग 25-30% की वार्षिक वृद्धि और सालाना 1,60,000 से अधिक नई

नौकरियाँ सृजित करने के साथ, वर्ष 2025 तक वैश्विक बाज़ार हिस्सेदारी का 5% (USD 40 बिलियन) हासिल करने की क्षमता है। अतः कथन 1 सही नहीं है।

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 में कक्षा 6 से स्कूल के पाठ्यक्रम में रचनात्मक कला, डिज़ाइन और खेल को एकीकृत किया गया है जिससे AVGC-XR के क्षेत्र में प्रतिभा के विकास के लिये अनुकूल वातावरण को बढ़ावा मिलेगा। अतः कथन 2 सही है।

38. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (FMBAP) एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे वर्ष 2015-16 से वर्ष 2025-26 की अवधि के लिये कार्यान्वित किया जा रहा है।
2. जबकि बाढ़ प्रबंधन मुख्य रूप से राज्य सरकारों की ज़िम्मेदारी है, केंद्र सरकार भी उनके प्रयासों में सहायता करती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही नहीं है/हैं ?

- A. केवल 1
- B. केवल 2
- C. 1 और 2 दोनों
- D. न तो 1 और न ही 2

उत्तर: A

व्याख्या:

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग (DoWR, RD & GR) द्वारा प्रस्तावित केंद्र प्रायोजित योजना "बाढ़ प्रबंधन एवं सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (FMBAP)" को कुल 4,100 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ वर्ष 2021-22 से लेकर 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। अतः कथन 1 सही नहीं है।
- 1160 करोड़ रुपए (100% केंद्रीय सहायता) के परिव्यय के साथ RMBA घटक जल विज्ञान (हाइड्रोलॉजिकल) संबंधी अवलोकन, बाढ़ नियंत्रण, क्षरण-रोधी कार्यों और पड़ोसी देशों के साथ संयुक्त जल परियोजनाओं सहित सीमावर्ती नदियों पर जाँच व निर्माण-पूर्व गतिविधियों, सुरक्षा एजेंसियों के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों तथा सीमा चौकियों की सुरक्षा पर केंद्रित है।
- ◆ यह योजना राज्यों को बाढ़ मैदान का क्षेत्रीकरण (Flood Plain Zoning) को लागू करने के लिये प्रोत्साहित करती है, जो एक प्रभावी बाढ़ प्रबंधन उपाय है।
 - बाढ़ मैदान का क्षेत्रीकरण बाढ़ की संभावना वाले क्षेत्रों को निर्दिष्ट करता है और बाढ़ के दौरान क्षति को कम करने के लिये अनुमेय विकास को निर्दिष्ट करता है।

- ◆ बाढ़ प्रबंधन मुख्य रूप से राज्य सरकारों की ज़िम्मेदारी है, वहीं केंद्र सरकार का लक्ष्य आधुनिक प्रौद्योगिकी और नवीन दृष्टिकोण को बढ़ावा देकर उनके प्रयासों को पूरा करना है। अतः कथन 2 सही है।

39. 'ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड (REC लिमिटेड)' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. यह वाणिज्य मंत्रालय के अधीन एक मिनीरल केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है।
2. यह भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के साथ एक गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी (NBFC) और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कंपनी (IFC) के रूप में पंजीकृत है।
3. इसे पुनरोत्थान वितरण क्षेत्र योजना (RDSS) के लिये कुछ राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की नोडल एजेंसी भी बनाई गई है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही नहीं है/हैं ?

- A. केवल एक
- B. केवल दो
- C. सभी तीन
- D. इनमें से कोई भी नहीं

उत्तर: A

व्याख्या:

- विद्युत मंत्रालय के अधीन एक महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम REC लिमिटेड (पूर्व में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड) ने सशस्त्र बल झंडा दिवस कोष (AFFDF) में महत्वपूर्ण योगदान देकर सशस्त्र बल कर्मियों के कल्याण के लिये अपनी अटूट प्रतिबद्धता प्रदर्शित की। अतः कथन 1 सही नहीं है।
- REC, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) में गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी (Non-Banking Finance Company- NBFC) व इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (IFC) के रूप में पंजीकृत है जो विद्युत बुनियादी ढाँचे, नवीकरणीय ऊर्जा तथा उभरती प्रौद्योगिकियों सहित विभिन्न क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। अतः कथन 2 सही है।
- REC लिमिटेड प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य), दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (DDUGJY), राष्ट्रीय विद्युत निधि (NEF) योजना जैसी सरकारी प्रमुख योजनाओं में एक प्रमुख भूमिका निभाता है जिसके परिणामस्वरूप देश के सभी भाग में विद्युतीकरण, शत-प्रतिशत गाँव का विद्युतीकरण सक्षम हुआ है एवं घर-घर बिजली की सुविधा मिली है।

- ◆ REC लिमिटेड, पुनरोत्थान वितरण क्षेत्र योजना (RDSS) के लिये कुछ राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की नोडल एजेंसी भी बनाई गई है। अतः कथन 3 सही है।

40. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. देश के पहले कौशल भारत केंद्र (SIC) का उद्घाटन मध्य प्रदेश के इंदौर में किया गया है।
2. राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) के तहत कार्य करने वाला एक अद्वितीय सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) उद्यम है।
3. NSDC ने कुशल व्यावसायिक प्रशिक्षण पहल पर ध्यान केंद्रित करते हुए कौशल भारत मिशन को लागू करने के लिये निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी की है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं ?

- A. केवल एक
- B. केवल दो
- C. सभी तीन
- D. इनमें से कोई भी नहीं

उत्तर: B

व्याख्या:

- केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री ने ओडिशा के संबलपुर में देश के पहले कौशल भारत केंद्र (SIC) का उद्घाटन किया जो भारत के युवाओं के कौशल में वृद्धि करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अतः कथन 1 सही नहीं है।
- ◆ संबलपुर, ओडिशा में स्थित SIC का लक्ष्य विशेष रूप से नए युग में नौकरी की भूमिकाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सहायता से युवाओं के कौशल में वृद्धि करना है।
 - यह मांग-संचालित उद्योगों में कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से 1200 से अधिक छात्रों को सशक्त बनाएगा।
- ◆ SIC मीडिया और मनोरंजन, चमड़ा, पर्यटन तथा आतिथ्य एवं IT-ITeS जैसे अधिक मांग वाले व्यवसायों के लिये पाठ्यक्रम के माध्यम से रोजगार योग्य कौशल विकसित करेगा।
- राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) गुणवत्ता मानकों का अनुपालन और केंद्र की समग्र कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का अनुवीक्षण करेगा।
- ◆ NSDC कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) के तहत कार्य करने वाला एक अद्वितीय सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) उद्यम है। अतः कथन 2 सही है।

- इसकी स्थापना कौशल इकोसिस्टम को विकसित करने के लिये की गई थी, NSDC कुशल व्यावसायिक प्रशिक्षण पहल पर ध्यान केंद्रित करते हुए कौशल भारत मिशन के रणनीतिक कार्यान्वयन के लिये निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी करता है। यह कौशल पहल को बढ़ाने के लिये पात्र संस्थाओं को वित्तीय सहायता, उम्मीदवारों को रियायती ऋण और नवीन वित्तीय उत्पाद प्रदान करके उद्यमों, स्टार्टअप तथा संगठनों का समर्थन करता है। अतः कथन 3 सही है।

41. 'राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली (NAFIS)' के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. यह राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) द्वारा संकल्पित और प्रबंधित, यह अपराध तथा आपराधिक-संबंधित फिंगरप्रिंट का एक देशव्यापी खोज योग्य डेटाबेस है।
2. यह किसी अपराध के लिये गिरफ्तार किये गए प्रत्येक व्यक्ति को एक अद्वितीय 10-अंकीय राष्ट्रीय फिंगरप्रिंट नंबर (NFN) प्रदान करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही नहीं है/हैं ?

- A. केवल 1
- B. केवल 2
- C. 1 और 2 दोनों
- D. न तो 1 और न ही 2

उत्तर: D

व्याख्या:

राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली (NAFIS):

- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) द्वारा संकल्पित और प्रबंधित, यह अपराध तथा आपराधिक-संबंधित फिंगरप्रिंट का एक देशव्यापी खोज योग्य डेटाबेस है। अतः कथन 1 सही है।
- ◆ वेब आधारित यह एप्लिकेशन सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से फिंगरप्रिंट डेटा को समेकित करके एक केंद्रीय सूचना भंडार के रूप में कार्य करता है।
- NAFIS किसी अपराध के लिये गिरफ्तार किये गए प्रत्येक व्यक्ति को एक अद्वितीय 10-अंकीय राष्ट्रीय फिंगरप्रिंट नंबर (NFN) प्रदान करता है। अतः कथन 2 सही है।
- ◆ इस विशिष्ट ID का उपयोग व्यक्ति के जीवनकाल तक किया जा सकता है और विभिन्न FIR के तहत दर्ज विभिन्न अपराधों को एक ही NFN से जोड़ा जाएगा।

42. प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस (PoPs) विनियम 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. यह विनियमन रजिस्ट्रीकरण प्रक्रिया का सरलीकरण कर लोगों के लिये राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) से जुड़ना आसान बनाता है।
2. लोगों को NPS से जोड़ने में मदद करने के लिये केवल बैंक ही प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस (PoPs) के रूप में कार्य कर सकते हैं।
3. रजिस्ट्रीकरण के लिये पूर्व में विभिन्न आवश्यकताओं के विपरीत, लोग अब केवल एक NPS रजिस्ट्रीकरण और एक ही शाखा के साथ व्यापक डिजिटल सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं ?

- A. केवल एक
- B. केवल दो
- C. सभी तीन
- D. इनमें से कोई भी नहीं

उत्तर: B

व्याख्या:

प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस (PoPs) विनियम 2023:

- पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस (PoP) विनियम 2023 को अधिसूचित किया।
- यह विनियमन पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाकर लोगों के लिये राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) में शामिल होना सरल बनाता है। अतः कथन 1 सही है।
- लोगों को NPS में शामिल होने में मदद करने के लिये बैंक और गैर-बैंक प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस (PoP) के रूप में काम कर सकते हैं। अतः कथन 2 सही नहीं है।
- रजिस्ट्रीकरण के लिये पूर्व में विभिन्न आवश्यकताओं के विपरीत, लोग अब केवल एक NPS रजिस्ट्रीकरण और एक ही शाखा के साथ व्यापक डिजिटल सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं। अतः कथन 3 सही है।

43. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 भ्रष्टाचार के लिये लोक सेवकों पर जुर्माने का प्रावधान करता है किंतु इसका संबंध भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले व्यक्तियों से नहीं है।
2. कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत रिश्वतखोरी तथा धोखाधड़ी जैसे मामलों का प्रावधान किया जाता है जिसमें आपराधिक विश्वासघात तथा छल से संबंधित अपराध भी शामिल हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही नहीं है/हैं ?

- A. केवल 1
- B. केवल 2
- C. 1 और 2 दोनों
- D. न तो 1 और न ही 2

उत्तर: C

व्याख्या:

- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Prevention of Corruption Act), 1988 में लोक सेवकों द्वारा किये जाने वाले भ्रष्टाचार और साथ ही भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में शामिल लोगों के लिये भी दंड का प्रावधान है। अतः कथन 1 सही नहीं है।
- कंपनी अधिनियम, 2013 कॉर्पोरेट प्रशासन और कॉर्पोरेट क्षेत्र में भ्रष्टाचार एवं धोखाधड़ी की रोकथाम में सहायता प्रदान करता है। 'धोखाधड़ी' शब्द की एक व्यापक परिभाषा है, इसे कंपनी अधिनियम के अंतर्गत दंडिक अपराध (Criminal Offence) माना गया है। अतः कथन 2 सही नहीं है।
- ◆ भारतीय दंड संहिता, 1860 के अंतर्गत रिश्वतखोरी तथा धोखाधड़ी जैसे मामलों का प्रावधान किया जाता है जिसमें आपराधिक विश्वासघात तथा छल से संबंधित अपराध भी शामिल हैं।

44. भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. भारत वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा उड्डयन बाजार है।
2. अनियंत्रित यात्रियों को विमान नियम, 1937 के तहत नियंत्रित किया जाता था।
3. नागरिक उड्डयन महानिदेशालय प्रमुख नियामक संस्था है जो मुख्य रूप से भारत में नागरिक उड्डयन को नियंत्रित करती है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं ?

- A. केवल एक
- B. केवल दो
- C. सभी तीन
- D. इनमें से कोई भी नहीं

उत्तर: B

व्याख्या:

भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र के बारे में :

- संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद भारत वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा उड्डयन बाजार है। अतः कथन 1 सही नहीं है।
- अनियंत्रित यात्रियों को विमान नियम, 1937 के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता, 1860 के तहत नियंत्रित किया जाता था। अतः कथन 2 सही है।

- नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) प्रमुख नियामक संस्था है जो मुख्य रूप से भारत में नागरिक उड्डयन को नियंत्रित करती है। यह सुरक्षा मुद्दों से निपटने, हवाई परिवहन सेवाओं के विनियमन, नागरिक हवाई नियमों और विनियमों को लागू करने तथा ऐसे अन्य कार्यों के लिये जिम्मेदार है। अतः कथन 3 सही है।

45. निम्नलिखित में से किसने सार्वजनिक उद्यमों के स्थायी सम्मेलन (SCOPE's) का 'प्रशंसा प्रमाणपत्र' प्राप्त किया है?

- A. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
- B. कोल इंडिया लिमिटेड
- C. नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
- D. इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड

उत्तर: C

व्याख्या:

भारत की अग्रणी जलविद्युत कंपनी और एक मिनी रत्न श्रेणी-I सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (PSU) के रूप में नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन (NHPC) लिमिटेड ने हाल ही में महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की, जब (स्कोप) सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 के सफल कार्यान्वयन के लिये इसे सार्वजनिक उद्यमों के स्थायी सम्मेलन द्वारा 'प्रशंसा प्रमाणपत्र' से सम्मानित किया गया। अतः विकल्प C सही है।

- यह पुरस्कार पारदर्शिता के प्रति NHPC की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालता है।
- वर्ष 1973 में स्थापित SCOPE सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (PSEs) के लिये शीर्ष निकाय है, जो अपनी परिचालन क्षमताओं एवं दक्षताओं को बढ़ाने के लिये नीतियों और रणनीतियों को लागू करके अपने सदस्य PSEs में प्रतिस्पर्धात्मकता के साथ उत्कृष्टता को भी बढ़ावा देने का प्रयास करता है।

46. भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री (BHISHM) क्यूब के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. भीष्म क्यूब अयोध्या में स्थित एक अत्याधुनिक स्वदेशी मोबाइल अस्पताल है।
2. यह प्रभावी समन्वय और वास्तविक समय की निगरानी तथा कुशल प्रबंधन को सुगम बनाने के लिये कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं डेटा एनालिटिक्स को एकीकृत करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही नहीं है/हैं?

- A. केवल 1
- B. केवल 2
- C. 1 और 2 दोनों
- D. न तो 1 और न ही 2

उत्तर: D

व्याख्या:

- भीष्म (भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री- BHISHM) प्रोजेक्ट आरोग्य मैत्री का क्यूब, अयोध्या में स्थित एक अत्याधुनिक स्वदेशी मोबाइल अस्पताल, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन के दौरान एक चिकित्सा आपातकाल की स्थिति में एक जीवनरक्षक के रूप में उभरकर आया। अतः कथन 1 सही है।

◆ आरोग्य मैत्री परियोजना में भारत प्राकृतिक आपदाओं या मानवीय संकटों के प्रभाव का सामना करने वाले किसी भी विकासशील देश को महत्त्वपूर्ण चिकित्सा संसाधनों की आपूर्ति करना शामिल है।

◆ BHISHM क्यूब को त्वरित प्रतिक्रिया और समग्र देखभाल पर बल देते हुए 200 हताहतों तक के उपचार के लिये तैयार किया गया है। यह एड क्यूब (Aid Cube) आपात स्थितियों के दौरान आपदा प्रतिक्रिया और चिकित्सा सहायता वृद्धि करने हेतु निर्मित कई नवोन्मेषी उपकरणों से युक्त है।

- यह क्षेत्र में चिकित्सा सेवाओं के प्रभावी समन्वय, वास्तविक समय की निगरानी और कुशल प्रबंधन को सुगम बनाने के लिये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence- AI) तथा डेटा एनालिटिक्स को एकीकृत करता है। अतः कथन 2 सही है।

◆ BHISHM क्यूब की सफलता आपात स्थिति के दौरान तत्काल और प्रभावी चिकित्सा सहायता प्रदान करने में मोबाइल अस्पताल इकाइयों के महत्त्व को रेखांकित करती है।

47. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. NGO कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत ट्रस्ट, सोसायटी या कंपनी के रूप में पंजीकरण कर सकते हैं, प्रत्येक के पंजीकरण एवं प्रशासन के लिये विशिष्ट नियम और विनियम मौजूद हैं।
2. विदेशी दान प्राप्त करने के इच्छुक संघों, समूहों और गैर-सरकारी संगठनों (NGO) को एक बार FCRA 2010 के तहत पंजीकरण कराना होगा, साथ ही यह पंजीकरण आजीवन वैध है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

- A. केवल 1
- B. केवल 2
- C. 1 और 2 दोनों
- D. न तो 1 और न ही 2

उत्तर: A

व्याख्या:

- मुख्य रूप से, NGO कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत ट्रस्ट, सोसायटी या कंपनी के रूप में पंजीकरण कर सकते हैं। प्रत्येक फॉर्म में पंजीकरण और प्रशासन के लिये नियमों एवं विनियमों का अपना सेट होता है। अतः कथन 1 सही है।
- विदेशी दान मांगने वाले संघों, समूहों और गैर सरकारी संगठनों के लिये विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम, 2010 (FCRA) के तहत पंजीकरण आवश्यक है, जो शुरू में 5 वर्ष के लिये वैध होता है तथा निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करने पर नवीकरणीय होता है। अतः कथन 2 सही नहीं है।

48. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) गृह मंत्रालय के अधिकार के तहत भारत में सात सुरक्षा बलों को संदर्भित करता है।
2. असम राइफल्स गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करती है लेकिन इसका परिचालन नियंत्रण रक्षा मंत्रालय के पास है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?

- A. केवल 1
- B. केवल 2
- C. 1 और 2 दोनों
- D. न तो 1 और न ही 2

उत्तर: C

व्याख्या:

- केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) गृह मंत्रालय के अधिकार के तहत भारत में सात सुरक्षा बलों को संदर्भित करता है। अतः कथन 1 सही है।
- असम राइफल्स गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करती है लेकिन इसका परिचालन नियंत्रण रक्षा मंत्रालय के पास है। अतः कथन 2 सही है।

49. धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. यह अधिनियम मनी लॉन्ड्रिंग के खतरे से निपटने के लिये वियना कन्वेंशन के प्रति भारत की वैश्विक प्रतिबद्धता के अनुरूप तैयार किया गया था।
2. इसमें मनी लॉन्ड्रिंग में अवैध रूप से प्राप्त धन को वित्तीय प्रणाली में एकीकृत करके विधि सम्मत या "वैध" दिखाना शामिल है।

3. सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय सुनाया है कि प्रवर्तन निदेशालय PMLA के तहत किसी को केवल उनके सवालों और समन का प्रत्युत्तर न देने पर गिरफ्तार नहीं कर सकता है।

उपर्युक्त कथनों में कितने सही नहीं हैं ?

- A. केवल एक
- B. केवल दो
- C. सभी तीन
- D. इनमें से कोई भी नहीं

उत्तर: D

व्याख्या:

- मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA), 2002 धन-शोधन और संबंधित अपराधों की रोकथाम हेतु वर्ष 2002 में अधिनियमित एक भारतीय कानून है।
- ◆ धन-शोधन में विधि-विरुद्ध रूप से प्राप्त धन को वित्तीय प्रणाली में एकीकृत करके विधि सम्मत अथवा "वैध" दिखाना शामिल है। अतः कथन 2 सही है।
- इसे वर्ष 2002 में धन-शोधन के खतरे से निपटने के लिये भारत की वैश्विक प्रतिबद्धता (वियना अभिसमय) की प्रतिक्रिया में अधिनियमित किया गया था। अतः कथन 1 सही है।
- प्रवर्तन निदेशालय (ED) मनी लॉन्ड्रिंग की जाँच और मुकदमा चलाने के लिये जिम्मेदार प्राथमिक प्राधिकरण है।
- ◆ यह वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत कार्य करता है।
- ◆ हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय सुनाया है कि ED PMLA के तहत किसी को केवल उनके सवालों और समन का प्रत्युत्तर नहीं देने के लिये गिरफ्तार नहीं कर सकता है। अतः कथन 3 सही है।

50. निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिये:

1. शिक्षा मंत्रालय ने शैक्षणिक संस्थानों के लिये भारत के नए एकीकृत वेब पोर्टल ERNET का अनावरण किया है।
2. पोर्टल में एक सेवा के रूप में वेबसाइट (WaaS) और एक सेवा के रूप में लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट (LMaaS) शामिल हैं, जो उपयोगकर्ताओं को अनुकूलित वेबसाइट बनाने की अनुमति देता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?

- A. केवल 1
- B. केवल 2
- C. 1 और 2 दोनों
- D. न तो 1 और न ही 2

उत्तर: B

व्याख्या:

- इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय ने हाल ही में शैक्षणिक संस्थानों के लिये भारत के नए एकीकृत वेब पोर्टल ERNET का अनावरण किया है, जो डोमेन पंजीकरण, डोमेन नेम सिस्टम (DNS) और मूल्य वर्द्धित सेवाएँ प्रदान करता है। अतः कथन 1 सही नहीं है।
- पोर्टल में एक सेवा के रूप में वेबसाइट (WaaS) और एक सेवा के रूप में लर्निंग मैनेजमेंट (LMaaS) शामिल हैं, जो उपयोगकर्ताओं को विभिन्न टेम्पलेट्स का उपयोग करके अनुकूलित वेबसाइट तथा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बनाने की अनुमति देता है। अतः कथन 2 सही है।
- ◆ ERNET इंडिया MeitY के तहत एक गैर-लाभकारी वैज्ञानिक सोसायटी है। यह सभी शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थानों के लिये विशिष्ट डोमेन रजिस्ट्रार है, जिसका डोमेन नाम 'ac.in', 'edu.in' और 'res.in' होता है।

51. अनैतिक दुर्व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. इसका उद्देश्य बुराइयों के व्यावसायीकरण और महिलाओं की तस्करी को रोकना है।
2. यह अधिनियम यौन कार्य को अवैध घोषित करता है और वेश्यालय चलाने पर रोक लगाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?

- A. केवल 1
- B. केवल 2
- C. 1 और 2 दोनों
- D. न तो 1 और न ही 2

उत्तर: A

व्याख्या:

अनैतिक दुर्व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956:

- अनैतिक दुर्व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 {Immoral Traffic (Prevention) Act (ITP), 1956} का उद्देश्य बुराइयों के व्यावसायीकरण और महिलाओं की तस्करी को रोकना है। अतः कथन 1 सही है।
- यह यौन कार्य के आसपास के कानूनी ढाँचे को चित्रित करता है। हालाँकि यह अधिनियम स्वयं यौन कार्य को अवैध घोषित नहीं करता है, लेकिन यह वेश्यालय चलाने पर रोक लगाता है। अतः कथन 2 सही नहीं है।
- वेश्यावृत्ति में संलग्न होना कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त है, लेकिन लोगों को लुभाना और उन्हें यौन गतिविधियों में शामिल करना अवैध माना जाता है।

- अधिनियम की धारा 2 वेश्यालय को किसी अन्य व्यक्ति के लाभ के लिये या दो या दो से अधिक वेश्याओं के पारस्परिक लाभ के लिये यौन शोषण या दुर्व्यवहार के लिये उपयोग की जाने वाली जगह के रूप में परिभाषित करती है।

52. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 132 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. यह कर अधिकारियों को उस स्थिति में बिना वारंट के तलाशी और ज़ब्ती करने की अनुमति देती है यदि "संदेह करने का कोई कारण" है कि किसी व्यक्ति ने आय छिपाई है या उससे बचा है।
2. इस प्रावधान की सांविधानिकता को पूरन मल बनाम निरीक्षण निदेशक (1973) मामले में चुनौती दी गई थी।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही नहीं है/हैं ?

- A. केवल 1
- B. केवल 2
- C. 1 और 2 दोनों
- D. न तो 1 और न ही 2

उत्तर: D

व्याख्या:

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 132:

- आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 132, कर अधिकारियों को बिना किसी पूर्व न्यायिक वारंट के व्यक्तियों तथा संपत्तियों की खोज/तलाशी एवं ज़ब्ती करने का अधिकार देती है यदि उनके पास "संदेह करने का कारण" है कि व्यक्ति ने आय छुपाई है अथवा चोरी की है। अतः कथन 1 सही है।
- ◆ यह अधिकारियों को वित्तीय संपत्ति छिपाने के संदेह के आधार पर भवन, स्थानों, वाहनों अथवा विमानों की तलाशी लेने की शक्ति प्रदान करता है।
- पूरन मल बनाम निरीक्षण निदेशक (1973):
 - ◆ धारा 132 की सांविधानिकता को पूरन मल बनाम निरीक्षण निदेशक (1973) मामले में चुनौती दी गई थी। अतः कथन 2 सही है।
 - ◆ सर्वोच्च न्यायालय ने एम.पी. शर्मा बनाम सतीश चंद्रा (1954) में अपने निर्णय का हवाला देते हुए कानून को बरकरार रखा और तर्क दिया कि खोज व ज़ब्ती की शक्ति सामाजिक सुरक्षा के बचाव के लिये आवश्यक है एवं विधि द्वारा विनियमित है।

53. बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिये नीतिगत हस्तक्षेप के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 के अनुसार, पश्चिम बंगाल में बाल विवाह की संख्या में काफी गिरावट आई है।
2. कन्याश्री प्रकल्प योजना 13 से 18 वर्ष की आयु की किशोर लड़कियों को स्कूली शिक्षा के लिये प्रोत्साहित करती है।
3. रूपश्री प्रकल्प योजना लड़कियों के विवाह के लिये नकद राशि का प्रोत्साहन प्रदान करती है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं ?

- A. केवल एक
- B. केवल दो
- C. सभी तीन
- D. इनमें से कोई नहीं

उत्तर: B

व्याख्या:

- बाल विवाह पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से पश्चिम बंगाल में कई नीतिगत हस्तक्षेपों के कार्यान्वयन के बावजूद, इस क्षेत्र में बाल विवाह की घटनाओं में 32.3% की पर्याप्त वृद्धि देखी गई है। यह वृद्धि 5,00,000 से अधिक अतिरिक्त लड़कियों की बचपन में ही शादी के अनुरूप है।
- ◆ राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 इंगित करता है कि 18 वर्ष से पहले शादी करने वाली 20-24 वर्ष की महिलाओं की व्यापकता पश्चिम बंगाल में 41.6% के उच्च स्तर पर बनी हुई है, जबकि राष्ट्रीय आँकड़ा 23.3% है। अतः कथन 1 सही नहीं है।
- कन्याश्री प्रकल्प योजना:
 - ◆ वर्ष 2013 में लॉन्च किया गया, कन्याश्री प्रकल्प 13 से 18 वर्ष की किशोर लड़कियों की स्कूली शिक्षा को प्रोत्साहित करता है और साथ ही बाल विवाह को हतोत्साहित करता है। वर्ष 2023-24 के पश्चिम बंगाल बजट के अनुसार, इस योजना में 81 लाख लड़कियों को शामिल किया गया है। अतः कथन 2 सही है।
- रूपश्री प्रकल्प:
 - ◆ कन्याश्री के अलावा, राज्य सरकार रूपश्री प्रकल्प चलाती है, जो लड़कियों की शादी के लिये नकद प्रोत्साहन प्रदान करती है। अतः कथन 3 सही है।

54. मध्यवर्ती दिशा-निर्देश एवं डिजिटल मीडिया आचार संहिता (2021) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने ओवर द टॉप (OTT) प्लेटफॉर्मों को विनियमित करने के लिये इन दिशा-निर्देशों को अधिसूचित किया था।
2. ये नियम OTT प्लेटफॉर्मों के लिये त्रिस्तरीय शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करते हैं।
3. वे केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की भागीदारी के बिना सामग्री के स्व-वर्गीकरण की सुविधा प्रदान करते हैं।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं ?

- A. केवल 1 और 2
- B. केवल 2 और 3
- C. केवल 1 और 3
- D. 1, 2 और 3

उत्तर: B

व्याख्या:

- ओटीटी प्लेटफॉर्मों को विनियमित करने के लिये, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Electronics and Information Technology-MeitY) द्वारा वर्ष 2022 में सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम 2021 जारी किया। अतः कथन 1 सही नहीं है।
- ओटीटी प्लेटफॉर्मों के लिये दिशा-निर्देश एक साफ्ट-टच स्व-नियामक वास्तुकला स्थापित करते हैं, जिसमें आचार संहिता और तीन स्तरीय शिकायत निवारण प्रक्रिया शामिल है। अतः कथन 2 सही है।
- वे केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की भागीदारी के बिना सामग्री के स्व-वर्गीकरण की सुविधा प्रदान करते हैं। अतः कथन 3 सही है।

55. भारत टेक्स 2024 क्या है ?

- A. कार्बन कर हेतु अंतर्राष्ट्रीय तंत्र।
- B. प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रौद्योगिकी सम्मेलन।
- C. वस्त्र मंत्रालय द्वारा आयोजित वस्त्र कार्यक्रम।
- D. वार्षिक चाय उत्सव।

उत्तर: C

व्याख्या:

- भारत टेक्स, 2024:
 - ◆ भारत टेक्स, 2024 वर्ष 2024 का सबसे बड़ा वस्त्र कार्यक्रम है जो वस्त्र मंत्रालय और भारत के 11 वस्त्र निर्यात संबद्धन परिषदों द्वारा आयोजित किया जाता है। इसका आयोजन 26 से 29 फरवरी, 2024 तक नई दिल्ली में किया जाएगा।

- भारत टेक्स 2024 भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और वस्त्र परंपराओं से लेकर नवीनतम तकनीकी नवाचारों तक **संपूर्ण वस्त्र उद्योग मूल्य श्रृंखला** का एक व्यापक प्रदर्शन होगा।
- भारत टेक्स 2024 का लक्ष्य भारत को वस्त्र क्षेत्र में एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करना तथा विश्व भर से निवेश, व्यापार एवं साझेदारी को आकर्षित करना है।

● अतः विकल्प C सही है।

56. सामाजिक अंकेक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. सामाजिक अंकेक्षण किसी संगठन या कार्यक्रम के सामाजिक प्रभाव का नियमित अंतर-सरकारी मूल्यांकन है।
2. महात्मा गांधी ने वर्ष 1920 में "सोशल ऑडिट/सामाजिक अंकेक्षण" शब्द का प्रस्ताव रखा।
3. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), 2005 के तहत प्रत्येक राज्य में स्वतंत्र सामाजिक लेखा परीक्षा इकाइयाँ अनिवार्य हैं।

उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं ?

- A. केवल एक
- B. केवल दो
- C. सभी तीन
- D. इनमें से कोई भी नहीं

उत्तर: A

व्याख्या:

- सामाजिक अंकेक्षण एक संगठन के सामाजिक और नैतिक प्रदर्शन को मापने, समझने, प्रेषित करने तथा अंततः सुधारने का एक तरीका है। अतः कथन 1 सही नहीं है।
- हॉवर्ड बोवेन ने वर्ष 1953 में लिखी गई अपनी पुस्तक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द बिज़नेसमैन में "सोशल ऑडिट/सामाजिक अंकेक्षण" शब्द का प्रस्ताव रखा। अतः कथन 2 सही नहीं है।
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) 2005: अधिनियम की धारा 17 में कहा गया है कि ग्राम सभा कार्य निष्पादन की निगरानी के लिये जिम्मेदार है।
- ◆ प्रत्येक राज्य में स्वतंत्र सामाजिक लेखापरीक्षा इकाइयों को कार्यक्रम कार्यान्वयन के समुदाय-संचालित सत्यापन पर जोर देते हुए कार्यान्वयन अधिकारियों से स्वतंत्र रूप से काम करना अनिवार्य है। अतः कथन 3 सही है।

57. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

कथन-I: स्कूल और उच्च शिक्षा के अंतर्गत सभी पाठ्यक्रमों के लिये अध्ययन सामग्री संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भारतीय भाषाओं में डिजिटल रूप से उपलब्ध कराई जाएगी।
कथन-II: यह निर्णय हर स्तर पर शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिये राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP-2020) की सिफारिशों के अनुरूप है।

उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा सही है ?

- A. कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं तथा कथन-II कथन-I की सही व्याख्या करता है।
- B. कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं, किंतु कथन-II कथन-I की सही व्याख्या नहीं करता है।
- C. कथन-I सही है, किंतु कथन-II गलत है।
- D. कथन-I गलत है, किंतु कथन-II सही है।

उत्तर: A

व्याख्या:

भारत सरकार ने सभी विद्यालयों तथा उच्च शिक्षण नियामकों और शैक्षणिक संस्थानों के प्रमुखों को अगले तीन वर्षों के भीतर भारतीय भाषाओं में प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिये अध्ययन सामग्री डिजिटल रूप में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।

- विद्यालय और उच्च शिक्षा के अंतर्गत सभी पाठ्यक्रमों के लिये अध्ययन सामग्री संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भारतीय भाषाओं में डिजिटल रूप से उपलब्ध कराई जाएगी। अतः कथन I सही है।
 - यह निर्णय हर स्तर पर शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिये राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Education Policy- NEP), 2020 की सिफारिशों के अनुरूप है। अतः कथन II सही है।
- कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं तथा कथन-II कथन-I की सही व्याख्या करता है।

58. भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 के तहत हिट-एंड-रन कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. BNS, 2023 में दुर्घटनास्थल से भागने पर 10 वर्ष तक की जेल की सजा का प्रावधान है।
2. यदि ड्राइवर दुर्घटना के तुरंत बाद घटना की सूचना देता है, तो पाँच वर्ष तक की सजा का प्रावधान है।
3. यह किसी पुलिस अधिकारी/मजिस्ट्रेट को घटना की रिपोर्ट न करने पर 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं/हैं ?

- A. केवल एक
- B. केवल दो
- C. सभी तीन
- D. इनमें से कोई भी नहीं

उत्तर: D

व्याख्या:

भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 के तहत हिट-एंड-रन कानून:

- हिट-एंड-रन उपबंध भारतीय न्याय संहिता (BNS) का हिस्सा है जिसका उद्देश्य औपनिवेशिक युग के भारतीय दंड संहिता, 1860 को प्रतिस्थापित करना है।
 - ◆ BNS, 2023 की धारा 106 (2) में दुर्घटना स्थल से भागने तथा किसी पुलिस अधिकारी अथवा मजिस्ट्रेट को घटना की रिपोर्ट करने में विफल रहने पर 10 वर्ष तक की कारावास तथा जुर्माने का प्रावधान है। अतः कथन 1 सही है।
- हालाँकि यदि ड्राइवर दुर्घटना के तुरंत बाद घटना की रिपोर्ट करता है तो उन पर धारा 106(2) के स्थान पर धारा 106(1) के तहत आरोप सिद्ध किया जाएगा। धारा 106(1) में गैर-इरादतन हत्या की श्रेणी में नहीं आने वाली मौत (लापरवाही के कारण होने वाली मौत) के लिये पाँच वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। अतः कथन 2 सही है।
- BNS की धारा 106 (2) में दुर्घटना स्थल से भागने और पुलिस अधिकारी/मजिस्ट्रेट को घटना की रिपोर्ट करने में विफल रहने पर 10 वर्ष तक की कारावास तथा 7 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। अतः कथन 3 सही है।

59. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

कथन-I: भारतीय मानक ब्यूरो (Bureau of Indian Standards - BIS) मानकीकरण की गतिविधियों के सामंजस्यपूर्ण विकास के लिये बीआईएस अधिनियम, 2016 के तहत स्थापित भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय है।

कथन-II: BIS भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन एक निकाय है।

उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा सही है ?

- A. कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं तथा कथन-II कथन-I की सही व्याख्या करता है।
- B. कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं, किंतु कथन-II कथन-I की सही व्याख्या नहीं करता है।
- C. कथन-I सही है, किंतु कथन-II गलत है।
- D. कथन-I गलत है, किंतु कथन-II सही है।

उत्तर: C

व्याख्या:

- भारतीय मानक ब्यूरो (Bureau of Indian Standards- BIS) वस्तुओं के मानकीकरण, अंकन और गुणवत्ता प्रमाणन की गतिविधियों के सामंजस्यपूर्ण विकास के लिये BIS अधिनियम 2016 के तहत स्थापित भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय है। BIS का मुख्यालय नई दिल्ली में है। अतः कथन 1 सही है।
- भारतीय मानक ब्यूरो भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत एक निकाय है, जिसने 6 जनवरी 2024 को अपना 77वाँ स्थापना दिवस मनाया। अतः कथन 2 सही नहीं है।
- अतः विकल्प C सही है।

60. प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (PMNRF) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. PMNRF की स्थापना वर्ष 1948 में तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्तियों की सहायता के लिये की गई थी।
2. इस फंड में पूरी तरह से सार्वजनिक योगदान शामिल है और इसे कोई बजटीय सहायता नहीं मिलती है।
3. PMNRF के लिये सभी दान को कर योग्य आय से 100% कटौती के लिये अधिसूचित किया गया है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही नहीं हैं ?

- A. केवल एक
- B. केवल दो
- C. सभी तीन
- D. इनमें से कोई भी नहीं

उत्तर: D

व्याख्या:

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (Prime Minister's National Relief Fund- PMNRF):

- PMNRF की स्थापना वर्ष 1948 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्तियों की सहायता के लिये की गई थी। अतः कथन 1 सही है।
- इस कोष का उपयोग वर्तमान में प्राकृतिक और मानव जनित आपदाओं से प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान करने हेतु किया जाता है।
 - ◆ इसमें बाढ़, चक्रवात और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएँ एवं प्रमुख दुर्घटनाएँ, एसिड हमले व दंगे जैसी मानव निर्मित आपदाएँ शामिल हैं।

- इस कोष में पूरी तरह से सार्वजनिक योगदान शामिल है और इसे कोई बजटीय सहायता नहीं मिलती है। अतः कथन 2 सही है।
- कोष की निधि का निवेश बैंकों में सावधि जमा के रूप में किया जाता है। इसका संवितरण प्रधानमंत्री की मंजूरी से किया जाता है।
- PMNRF के लिये सभी दान को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80G के तहत कर योग्य आय से 100% कटौती हेतु अधिसूचित किया गया है। अतः कथन 3 सही है।

61. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष 10 अक्टूबर को मनाया जाता है।
2. मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 प्रत्येक प्रभावित व्यक्ति को सरकार द्वारा संचालित या वित्त पोषित सेवाओं से मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और उपचार तक पहुँच की गारंटी देता है।
3. मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे लोगों को सहायता प्रदान करने के लिये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किरण हेल्पलाइन शुरू की गई थी।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं ?

- A. केवल 1 और 2
- B. केवल 2
- C. केवल 3
- D. 1, 2 और 3

उत्तर: A

व्याख्या:

- विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है, यह एक वैश्विक पहल है जिसका उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और दुनिया भर में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के लिये समर्थन जुटाना है। अतः कथन 1 सही है।
- मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 प्रत्येक प्रभावित व्यक्ति को सरकार द्वारा संचालित या वित्त पोषित सेवाओं से मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और उपचार तक पहुँच की गारंटी देता है। अतः कथन 2 सही है।
- इसने IPC की धारा 309 के उपयोग की गुंजाइश को काफी कम कर दिया है और आत्महत्या के प्रयास को केवल अपवाद के रूप में दंडनीय बना दिया है।
- किरण हेल्पलाइन: वर्ष 2020 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने चिंता, तनाव, अवसाद, आत्मघाती विचारों और अन्य मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का सामना करने वाले लोगों को सहायता प्रदान करने के लिये 24/7 टोल-फ्री हेल्पलाइन 'किरण' शुरू की। अतः कथन 3 सही नहीं है।

62. 10. अधिवक्ता संशोधन विधेयक, 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. इसका मुख्य उद्देश्य कानूनी प्रणाली में 'दलालों' को औपचारिक रूप से शामिल करना है।
2. दलाल (टाउट) से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो भुगतान के बदले में कानूनी व्यवसाय में कानूनी व्यवसायी का रोजगार प्राप्त करता है।
3. कोई भी व्यक्ति जो दलाल के रूप में कार्य करता है, जबकि उसका नाम दलालों की सूची में शामिल है, उसे तीन महीने तक की कैद की सजा दी जाएगी।

उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं ?

- A. केवल एक
- B. केवल दो
- C. सभी तीन
- D. इनमें से कोई नहीं

उत्तर: B

व्याख्या:

- हाल ही में अधिवक्ता संशोधन विधेयक, 2023 लोकसभा और राज्यसभा में पारित हो गया। इसका उद्देश्य कानूनी प्रणाली से 'दलाल' को बाहर करना था। अतः कथन 1 सही नहीं है।
- दलाल (Tout) उस व्यक्ति को संदर्भित करता है, जो:
 - ◆ या तो किसी भुगतान के बदले में किसी कानूनी व्यवसाय में किसी कानूनी व्यवसायी का रोजगार प्राप्त करने का प्रस्ताव करता है या प्राप्त करता है। अतः कथन 2 सही है।
- सूचियाँ तैयार करना:
 - ◆ दलालों की सूची तैयार करने और प्रकाशित करने का अधिकार रखने वाले प्राधिकारी अधीनस्थ अदालतों को दलाल होने के कथित या संदिग्ध व्यक्तियों के आचरण की जाँच करने का आदेश दे सकते हैं।
- दंड (Penalty):
- कोई भी व्यक्ति जो दलाल के रूप में कार्य करता है, जबकि उसका नाम दलालों की सूची में शामिल है, उसे तीन महीने तक की कैद, 500 रुपए तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। अतः कथन 3 सही है।

63. वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. भारत में मध्यस्थता माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 द्वारा शासित एवं विनियमित होती है, जिसे केवल एक बार संशोधित किया गया है।

2. मध्यस्थता में, एक निष्पक्ष व्यक्ति जिसे "मध्यस्थ" कहा जाता है, पक्षों को विवाद के पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान तक पहुँचने में मदद करता है।
3. समझौता वार्ता वैकल्पिक विवाद समाधान का सबसे आम तरीका है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही नहीं हैं ?

- A. केवल एक
- B. केवल दो
- C. सभी तीन
- D. इनमें से कोई नहीं

उत्तर: A

व्याख्या:

वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) तंत्र:

- भारतीय मध्यस्थता माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 (जिसे वर्ष 2015, 2019 और 2021 में संशोधित किया गया है) द्वारा शासित एवं विनियमित है। अतः कथन 1 सही नहीं है।
- ◆ माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 द्वारा भारतीय माध्यस्थम् परिषद् (ACI) नामक एक स्वतंत्र निकाय स्थापित किया गया।
- मध्यस्थता में, "मध्यस्थ" नामक एक निष्पक्ष व्यक्ति पक्षों को विवाद के पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान तक पहुँचने में मदद करता है। अतः कथन 2 सही है।
- ◆ मध्यस्थ, विवाद का कोई समाधान प्रदान नहीं करता है बल्कि एक अनुकूल वातावरण बनाता है जिसमें विवादित पक्ष अपने सभी विवादों को हल कर सकते हैं।
- यह एक गैर-बाध्यकारी प्रक्रिया है जिसमें एक निष्पक्ष तीसरा पक्ष अर्थात् सुलहकर्ता, विवाद के पारस्परिक रूप से संतोषजनक सहमत समाधान तक पहुँचने में विवाद के पक्षों की सहायता करता है।
- ◆ यह सुलह, माध्यस्थम् का एक अल्प औपचारिक रूप है। अतः कथन 3 सही है।

64. डाकघर विधेयक (2023) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. विधेयक भारतीय डाक के माध्यम से प्रेषित लेखों की रोकथाम के लिये प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों को निर्दिष्ट करता है।
2. विधेयक में डाक सेवाओं में किसी भी चूक के लिये इंडिया पोस्ट को उत्तरदायी बनाने का प्रयास किया गया है।
3. विधेयक एक डाक अधिकारी द्वारा डाक लेखों को अनधिकृत रूप से खोलने के लिये दंड निर्दिष्ट करता है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं ?

- A. केवल एक
- B. केवल दो
- C. सभी तीन
- D. कोई भी नहीं

उत्तर: D

व्याख्या:

डाकघर विधेयक, 2023 की मुख्य विशेषताएँ:

- डाक अधिकारी किसी भी वस्तु को "अंतरुद्ध" कर सकते हैं: यह विधेयक केंद्र को राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, सार्वजनिक व्यवस्था, आपातकाल, सार्वजनिक सुरक्षा अथवा अन्य कानूनों के उल्लंघन के हित में किसी भी अधिकारी को "किसी भी वस्तु को रोकने, खोलने अथवा हिरासत में लेने" का अधिकार देने की अनुमति प्रदान करता है।
- ◆ आलोचना: विधेयक भारतीय डाक के माध्यम से प्रेषित लेखों की रोकथाम के लिये प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों को निर्दिष्ट नहीं करता है। अतः कथन 1 सही नहीं है।
- डाकघर को दायित्व से छूट: बिल डाकघर और उसके अधिकारी को डाकघर द्वारा प्रदान की गई किसी भी सेवा के दौरान किसी भी हानि, गलत वितरण, देरी या क्षति के कारण किसी भी दायित्व से छूट देता है, इसके आलावा ऐसे दायित्व जो निर्धारित किये जा सकते हैं।
- ◆ आलोचना: विधेयक भारतीय डाक को डाक सेवाओं में चूक के लिये दायित्व से छूट देता है। अतः कथन 2 सही नहीं है।
- अपराधों और दंडों को हटाना:
 - ◆ विधेयक 1898 अधिनियम के तहत सभी दंडों और अपराधों को हटाता है। अतः कथन 3 सही नहीं है।

65. बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. इस अधिनियम ने बाल विवाह निरोधक अधिनियम, 1929 का स्थान लिया जो ब्रिटिश काल के दौरान लागू किया गया था।
2. अधिनियम बाल विवाह को रोकने के लिये बाल विवाह निषेध अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?

- A. केवल 1
- B. केवल 2
- C. 1 और 2 दोनों
- D. न तो 1 और न ही 2

उत्तर: C

व्याख्या:

बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006:

- इस अधिनियम ने बाल विवाह निरोधक अधिनियम, 1929 का स्थान लिया जो ब्रिटिश काल के दौरान लागू किया गया था। अतः कथन 1 सही है।
- इसमें बच्चे का मतलब 21 साल से कम उम्र का पुरुष और 18 साल से कम उम्र की महिला है।
- इसमें दो साल के कठोर कारावास और/या 1 लाख रुपए के जमाने की सजा के प्रावधान के साथ बाल विवाह को रोकने की परिकल्पना की गई है।
- यह अधिनियम बाल विवाह निषेध अधिकारी की नियुक्ति का भी प्रावधान करता है जिसका कर्तव्य बाल विवाह को रोकना और इसके बारे में जागरूकता फैलाना है। अतः कथन 2 सही है।

66. पीड़कनाशी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. इनका विनियमन कीटनाशक अधिनियम, 1968 के तहत किया जाता है।
2. भारत सरकार ने डिकोफोल, डिनोकैप और मेथोमाइल को प्रतिबंधित कर दिया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?

- A. केवल 1
- B. केवल 2
- C. 1 और 2 दोनों
- D. न तो 1 और न ही 2

उत्तर: C

व्याख्या:

- पीड़कनाशी के उपयोग को कीटनाशी अधिनियम, 1968 एवं नियमावली, 1971 के तहत विनियमित किया जाता है। अतः कथन 1 सही है।
- ◆ कीटनाशी अधिनियम, 1968 भारत में पीड़कनाशी के पंजीकरण, निर्माण एवं बिक्री को कवर करता है।
- ◆ यह अधिनियम कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाता है।
- भारत सरकार ने डिकोफोल, डिनोकैप और मेथोमाइल को प्रतिबंधित कर दिया है। अतः कथन 2 सही है।

67. प्रसार भारती के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. यह प्रसार भारती अधिनियम, 1997 के तहत स्थापित एक वैधानिक स्वायत्त निकाय है।

2. प्रसार भारती देश की सबसे बड़ी सार्वजनिक प्रसारण एजेंसी है और इसके अंतर्गत दूरदर्शन टेलीविजन नेटवर्क तथा ऑल इंडिया रेडियो शामिल हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?

- A. केवल 1
- B. केवल 2
- C. 1 और 2 दोनों
- D. न तो 1 और न ही 2

उत्तर: C

व्याख्या:

- प्रसार भारती भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक प्रसारण एजेंसी है। यह प्रसार भारती अधिनियम, 1997 के तहत स्थापित एक वैधानिक स्वायत्त निकाय है और इसमें दूरदर्शन टेलीविजन नेटवर्क तथा ऑल इंडिया रेडियो शामिल हैं, जो पहले सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की मीडिया इकाइयाँ थीं। अतः कथन 1 और 2 दोनों सही हैं।

68. "चुनावी बॉण्ड योजना" के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. चुनावी बॉण्ड प्रणाली को वर्ष 2017 में एक वित्त विधेयक के माध्यम से पेश किया गया था और इसे वर्ष 2018 में लागू किया गया था।
2. वित्त अधिनियम, 2017 में संशोधन के माध्यम से केंद्र सरकार ने राजनीतिक दलों को चुनावी बॉण्ड के माध्यम से प्राप्त दान का प्रकटीकरण करने से छूट दी है।
3. इसका अर्थ यह है कि मतदाताओं को यह नहीं पता होगा कि किस व्यक्ति, कंपनी अथवा संगठन ने किस पार्टी को और कितनी मात्रा में फंड दिया है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही नहीं हैं ?

- A. केवल एक
- B. केवल दो
- C. सभी तीन
- D. इनमें से कोई भी नहीं

उत्तर: D

व्याख्या:

चुनावी बॉण्ड योजना:

- चुनावी बॉण्ड प्रणाली को वर्ष 2017 में एक वित्त विधेयक के माध्यम से पेश किया गया था और इसे वर्ष 2018 में लागू किया गया था। अतः कथन 1 सही है।
- वे दाता की गोपनीयता बनाए रखते हुए व्यक्तियों और संस्थाओं के लिये पंजीकृत राजनीतिक दलों को फंडिंग देने के साधन के रूप में कार्य करते हैं।

- ◆ **चुनावी ट्रस्ट योजना, 2013:** इसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा अधिसूचित किया गया था।
 - इलेक्टोरल ट्रस्ट कंपनियों द्वारा स्थापित एक ट्रस्ट है जिसका एकमात्र उद्देश्य अन्य कंपनियों एवं व्यक्तियों से प्राप्त योगदान को राजनीतिक दलों में वितरित करना है।

चुनावी बॉण्ड योजना के अंतर्गत प्रकटीकरण से छूट:

- **वित्त अधिनियम, 2017** में संशोधन के माध्यम से केंद्र सरकार ने राजनीतिक दलों को **चुनावी बॉण्ड** के माध्यम से प्राप्त दान का प्रकटीकरण करने से छूट दी है। अतः **कथन 2 सही है।**
- इसका अर्थ यह है कि मतदाताओं को यह नहीं पता होगा कि किस व्यक्ति, कंपनी अथवा संगठन ने किस पार्टी को और कितनी मात्रा में फंड दिया है। अतः **कथन 3 सही है।**
- हालाँकि एक **प्रतिनिधि लोकतंत्र** में नागरिक अपना वोट उन लोगों के लिये डालते हैं जो संसद में उनका प्रतिनिधित्व करेंगे।

सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ:

- हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने भारत निर्वाचन आयोग (ECI) को चुनावी बॉण्ड के माध्यम से राजनीतिक दलों को प्राप्त धन पर **अद्यतन डेटा प्रदान करने का निर्देश** दिया है।
- भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने लंबे समय से माना है कि "**जानने का अधिकार**", विशेष रूप से चुनावों के संदर्भ में, **भारतीय संविधान** के तहत **अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार (अनुच्छेद 19)** का एक अभिन्न अंग है।

69. आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. यह नीति आयोग के तहत राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन (NSO) द्वारा आयोजित किया जाने वाला एक सर्वेक्षण है।
2. इसे NSO द्वारा अप्रैल 2017 में शुरू किया गया था।
3. इसका उद्देश्य वार्षिक तौर पर ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में 'सामान्य स्थिति' और CWS दोनों में रोजगार एवं बेरोजगारी संकेतकों का अनुमान लगाना है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?

- A. केवल 2 और 3
- B. केवल 2
- C. केवल 3
- D. 1, 2 और 3

उत्तर: A

व्याख्या:

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS):

परिचय:

- ◆ यह भारत में रोजगार और बेरोजगारी की स्थिति को मापने के लिये **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI)** के तहत **NSO** द्वारा आयोजित एक सर्वेक्षण है। अतः **कथन 1 सही नहीं है।**
- ◆ इसे NSO द्वारा अप्रैल 2017 में शुरू किया गया था। अतः **कथन 2 सही है।**

PLFS के उद्देश्य:

- ◆ केवल 'वर्तमान साप्ताहिक स्थिति' (CWS) में शहरी क्षेत्रों के लिये तीन माह के अल्प समय अंतराल में प्रमुख रोजगार और बेरोजगारी संकेतक (जैसे श्रमिक जनसंख्या अनुपात, श्रम बल भागीदारी दर, बेरोजगारी दर) का अनुमान लगाना।
- ◆ वार्षिक रूप से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में 'सामान्य स्थिति' और CWS दोनों में रोजगार तथा बेरोजगारी संकेतकों का अनुमान लगाना। अतः **कथन 3 सही है।**

70. "राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB)" के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. NCRB को वर्ष 1986 में राष्ट्रीय पुलिस आयोग (1977-1981) और गृह मंत्रालय के कार्य बल (1985) की सिफारिशों के आधार पर स्थापित किया गया था।
2. यह भारतीय और विदेशी अपराधियों के फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड करने के लिये "नेशनल वेयरहाउस" के रूप में भी कार्य करता है तथा फिंगरप्रिंट जाँच के माध्यम से अंतर-राज्यीय अपराधियों का पता लगाने में सहायता करता है।
3. 'क्राइम इन इंडिया' और 'आकस्मिक मृत्यु एवं आत्महत्या' NCRB द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही नहीं हैं ?

- A. केवल एक
- B. केवल दो
- C. सभी तीन
- D. इनमें से कोई भी नहीं

उत्तर: D

व्याख्या:

- NCRB की स्थापना केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत वर्ष 1986 में इस उद्देश्य से की गई थी ताकि भारतीय पुलिस में कानून व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिये पुलिस तंत्र को सूचना प्रौद्योगिकी समाधान और आपराधिक गुप्त सूचनाएँ प्रदान कर समर्थ बनाया जा सके। यह **राष्ट्रीय पुलिस आयोग (1977-1981)** और **गृह मंत्रालय के कार्य बल (1985)** की सिफारिशों के आधार पर स्थापित किया गया था। अतः **कथन 1 सही है।**

- ◆ यह गृह मंत्रालय का हिस्सा है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।
- यह भारतीय और विदेशी अपराधियों के फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड करने के लिये "नेशनल वेयरहाउस" के रूप में भी कार्य करता है, और फिंगरप्रिंट खोज के माध्यम से अंतर-राज्यीय अपराधियों का पता लगाने में सहायता करता है। अतः कथन 2 सही है।
- NCRB के चार प्रभाग हैं: अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क एवं सिस्टम (CCTNS), अपराध सांख्यिकी, फिंगरप्रिंट और प्रशिक्षण।
- NCRB के प्रकाशन:
 - ◆ क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट
 - ◆ आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्या
 - ◆ जेल सांख्यिकी
 - ◆ भारत में गुमशुदा महिलाओं और बच्चों पर रिपोर्ट। अतः कथन 3 सही है।
 - ◆ ये प्रकाशन न केवल पुलिस अधिकारियों के लिये बल्कि भारत में ही नहीं विदेशों में भी अपराध विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं, मीडिया तथा नीति निर्माताओं हेतु अपराध आँकड़ों पर प्रमुख संदर्भ बिंदु के रूप में काम करते हैं।

71. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. सार्वजनिक जुआ अधिनियम, 1867 मुख्य रूप से गैर-ऑनलाइन जुआ गतिविधियों से संबंधित है।
2. IT अधिनियम की धारा 66 कंप्यूटर से संबंधित अपराधों से संबंधित है, जो ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े साइबर अपराधों को संबोधित करने के लिये कानूनी आधार प्रदान करती है।
3. भारत में ऑनलाइन जुए की अनुमति है, लेकिन ऑफलाइन जुए की नहीं।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं ?

- A. केवल एक
- B. केवल दो
- C. सभी तीन
- D. इनमें से कोई भी नहीं

उत्तर: B

व्याख्या:

- सार्वजनिक जुआ अधिनियम, 1867
 - ◆ यह अधिनियम मुख्य रूप से गैर-ऑनलाइन जुआ गतिविधियों से संबंधित है। हालाँकि इसकी प्रासंगिकता ऑनलाइन गेमिंग में भी है, जो इसके विनियमन के लिये एक कानूनी ढाँचा प्रदान करता है। अतः कथन 1 सही है।

● सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000:

- ◆ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 गेमिंग सहित ऑनलाइन गतिविधियों को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। IT अधिनियम की धारा 66 कंप्यूटर से संबंधित अपराधों से संबंधित है, जो ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े साइबर अपराधों को संबोधित करने के लिये कानूनी आधार प्रदान करती है। अतः कथन 2 सही है।
- ◆ सार्वजनिक जुआ अधिनियम ने घोषित किया है कि कोई भी जुआ जिसमें पैसा लगाना या पैसे के लिये दाँव लगाना या कोई अन्य समकक्ष कार्य शामिल है, अवैध है। अतः कथन 3 सही नहीं है।

72. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की गई।
2. भारतीय शिक्षा नीति संकल्प वर्ष 1904 में जारी किया गया था।
3. वर्ष 1945 में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) का गठन किया गया था।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं ?

- A. केवल एक
- B. केवल दो
- C. सभी तीन
- D. इनमें से कोई भी नहीं

उत्तर: C

व्याख्या:

- भारतीय विश्वविद्यालय आयोग वर्ष 1902 में भारत के वायसराय लॉर्ड कर्ज़न के निर्देश पर नियुक्त एक निकाय था, जिसका उद्देश्य भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार के लिये सिफारिशें करना था। अतः कथन 1 सही है।
- 11 मार्च, 1904 को जारी की गई शैक्षिक नीति के मुख्य वास्तुकार लॉर्ड कर्ज़न थे। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सरकारी संकल्प था। इसलिये वर्ष 1904 को भारत में शैक्षिक विकास के इतिहास में एक कीर्तिमान माना जा सकता है। अतः कथन 2 सही है।
- तकनीकी शिक्षा के लिये उपलब्ध सुविधाओं पर सर्वेक्षण करने एवं समन्वित व एकीकृत तरीके से देश में विकास को बढ़ावा देने के लिये अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) की स्थापना नवंबर 1945 में एक राष्ट्रीय स्तर की शीर्ष सलाहकार संस्था के रूप में की गई थी। अतः कथन 3 सही है।

73. भारतीय भेषज संहिता आयोग (Indian Pharmacopoeia Commission- IPC) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. IPC, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक स्वायत्त संस्था है।
2. यह इंडियन फार्माकोपिया को अद्यतन करके एवं दवाओं हेतु नए मानक शामिल करते हुए औपचारिक दिशानिर्देश जारी करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही नहीं है/हैं ?

- A. केवल 1
- B. केवल 2
- C. 1 और 2 दोनों
- D. न तो 1 और न ही 2

उत्तर: D

व्याख्या:

भारतीय भेषज संहिता आयोग (IPC):

- IPC, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक स्वायत्त संस्था है। अतः कथन 1 सही है।
- IPC को भारत में दवाओं के मानक तय करने के लिये बनाया गया था। इसका मूल कार्य इस क्षेत्र में प्रचलित बीमारियों के इलाज के लिये आमतौर पर आवश्यक दवाओं के मानकों को नियमित रूप से अद्यतन करना है।
- यह इंडियन फार्माकोपिया (मोनोग्राफ का संग्रह) को अद्यतन करके एवं दवाओं हेतु नए मानक शामिल करते हुए औपचारिक दिशानिर्देश जारी करता है। अतः कथन 2 सही है।
- ◆ यह नेशनल फॉर्मूलरी ऑफ इंडिया को प्रकाशित करके जेनेरिक दवाओं के तर्कसंगत उपयोग को बढ़ावा देता है।
- IPC आईपी रेफरेंस सबस्टेंस (IPRS) भी प्रदान करता है जो परीक्षण के तहत किसी वस्तु की पहचान और IP(Internet Protocol) में निर्धारित उसकी शुद्धता के लिये फिंगरप्रिंट के रूप में कार्य करता है।

74. "सत्य और सुलह आयोग" के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. सत्य और सुलह आयोग सरकारी कर्मचारियों द्वारा किये गए गलत कार्यों को न केवल स्वीकार करने, बल्कि प्रकट करने का एक आधिकारिक तंत्र है।
2. आयोग प्रत्यक्ष और व्यापक रूप से प्रभावित आबादी से जुड़ता है तथा उनके अनुभवों के बारे में जानकारी एकत्र करता है।
3. भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका तथा नेपाल द्वारा सत्य आयोग स्थापित किये गए हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही नहीं हैं ?

- A. केवल एक
- B. केवल दो
- C. सभी तीन
- D. इनमें से कोई भी नहीं

उत्तर: D

व्याख्या:

- सत्य और सुलह आयोग जिसे 'सत्य और न्याय आयोग' या 'सत्य आयोग' के रूप में भी जाना जाता है, यह एक सरकारी तंत्र है जो न केवल स्वीकार करता है, बल्कि सरकार या कभी-कभी गैर-राज्य अभिनेताओं द्वारा किये गए गलत कार्यों को भी प्रकट करता है। अतः कथन 1 सही है।
- सत्य आयोग वह है जो चल रही घटनाओं के बजाय अतीत पर केंद्रित है।
- यह एक समयावधि में घटित घटनाओं के प्रतिरूप की जाँच करता है।
- आयोग प्रत्यक्ष और व्यापक रूप से प्रभावित आबादी से जुड़ता है तथा उनके अनुभवों के बारे में जानकारी एकत्र करता है। अतः कथन 2 सही है।
- यह एक अस्थायी निकाय है, जिसका उद्देश्य अंतिम रिपोर्ट के साथ निष्कर्ष निकालना है।
- आयोग समीक्षाधीन राज्य द्वारा आधिकारिक तौर पर अधिकृत या सशक्त है।
- दो सबसे प्रसिद्ध और सबसे परिणामी आयोग दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में स्थापित माने जाते हैं।
- भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका तथा नेपाल द्वारा सत्य आयोग स्थापित किये गए हैं। अतः कथन 3 सही है।

75. 'ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर' का प्रकाशन कौन करता है ?

- A. ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल
- B. विश्व बैंक
- C. संयुक्त राष्ट्र
- D. ट्रेस इंटरनेशनल

उत्तर: A

व्याख्या:

ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल:

- यह वर्ष 1993 में बर्लिन, जर्मनी में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन है।
- इसका गैर-लाभकारी उद्देश्य नागरिक सामाजिक भ्रष्टाचार विरोधी उपायों के साथ वैश्विक भ्रष्टाचार से निपटने और भ्रष्टाचार से उत्पन्न होने वाली आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिये कार्रवाई करना है।

- इसके सबसे उल्लेखनीय प्रकाशनों में 'ग्लोबल करफ़ान बैरोमीटर' और 'करफ़ान परसेफ़ान इंडेक्स' शामिल हैं। अतः विकल्प A सही है।

76. ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर्स II के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. यह उग्रवादियों के विरुद्ध भारत और म्यांमार सेना का संयुक्त अभियान है।
2. यह ऑपरेशन BIMSTEC आतंकवाद-रोधी ढाँचे का हिस्सा है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?

- A. केवल 1
- B. केवल 2
- C. 1 और 2 दोनों
- D. न तो 1 और न ही 2

उत्तर: D

व्याख्या:

ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर्स II:

- हाल ही में इंटरपोल द्वारा ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर्स II का संचालन किया गया। अतः कथन 1 सही नहीं है।
- इसमें मानव तस्करी के शिकार लोगों का उपयोग करते हुए चलाये जा रहे धोखाधड़ी योजनाओं के बढ़ते नेटवर्क को उजागर किया गया है।
- इसने 27 एशियाई और अन्य देशों में मानव तस्करी तथा प्रवासी तस्करी से निपटने के लिये कानून प्रवर्तन को संगठित किया। अतः कथन 2 सही नहीं है।

77. जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. इस अधिनियम के तहत स्थानीय क्षेत्रों के अधिकार क्षेत्र के भीतर जन्म के रजिस्ट्रीकरण की निगरानी के लिये रजिस्ट्रार नियुक्त किये जाते हैं।
2. चिकित्सालय, स्वास्थ्य केंद्र, प्रसूति अथवा नर्सिंग होम जैसे संस्थान अपने परिसर में होने वाले जन्मों की रिपोर्ट रजिस्ट्रार को देने के लिये उत्तरदायी हैं।
3. यह अधिनियम नागरिकों पर उनके अधिकार क्षेत्र में होने वाली घटना के 30 दिनों के भीतर रजिस्ट्रार को सूचित करने का दायित्व डालता है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं ?

- A. केवल एक
- B. केवल दो
- C. सभी तीन
- D. इनमें से कोई भी नहीं

उत्तर: B

व्याख्या:

भारत में जन्म के पंजीकरण से संबंधित प्रमुख प्रावधान

- जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969:

- ◆ रजिस्ट्रार की नियुक्ति: RBD अधिनियम, 1969 की धारा 7 के तहत स्थानीय क्षेत्रों के अधिकार क्षेत्र के भीतर जन्म के रजिस्ट्रीकरण की निगरानी के लिये रजिस्ट्रार नियुक्त किये जाते हैं। अतः कथन 1 सही है।

- ये रजिस्ट्रार नगर पालिकाओं, पंचायतों, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों अथवा राज्य सरकार द्वारा नामित अन्य स्थानीय प्राधिकरणों जैसी विभिन्न संस्थाओं से संबद्ध व्यक्ति हो सकते हैं।

- ◆ संस्थागत ज़िम्मेदारियाँ: जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के तहत चिकित्सालय, स्वास्थ्य केंद्र, प्रसूति अथवा नर्सिंग होम जैसे संस्थान अपने परिसर में होने वाले जन्मों की रिपोर्ट रजिस्ट्रार को देने के लिये उत्तरदायी हैं। अतः कथन 2 सही है।

- ◆ नागरिकों की बाध्यता: नागरिकों को इसके अधिकार क्षेत्र में होने वाले जन्म के मामलों में 21 दिनों के भीतर रजिस्ट्रार को सूचित करना आवश्यक है। अतः कथन 3 सही नहीं है।

78. असम समझौते के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. यह केंद्र सरकार और असम राज्य सरकार के बीच एक द्विपक्षीय समझौता है।
2. इस समझौते द्वारा विशेष रूप से असम के लिये नागरिकता अधिनियम, 1955 में धारा 6A को शामिल किया गया था।
3. इस समझौते में बांग्लादेश से अवैध प्रवासियों की घुसपैठ को समाप्त करने की मांग की गई थी।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं ?

- A. केवल एक
- B. केवल दो
- C. तीनों
- D. इनमें से कोई भी नहीं

उत्तर: B

व्याख्या:

- असम समझौता केंद्र सरकार, असम राज्य सरकार और असम आंदोलन के नेताओं के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता था। अतः कथन 1 सही नहीं है।

- वर्ष 1985 में हस्ताक्षरित असम समझौते द्वारा विशेष रूप से असम के लिये वर्ष 1955 के नागरिकता अधिनियम में धारा 6A को शामिल किया गया था। अतः कथन 2 सही है।

◆ इसका उद्देश्य बांग्लादेश से अवैध प्रवासियों की घुसपैठ को समाप्त करना था। अतः कथन 3 सही है।

- यह प्रावधान वर्ष 1971 के बांग्लादेश मुक्ति युद्ध से पूर्व बड़े पैमाने पर प्रवासन के मुद्दे का समाधान करता है। विशेष रूप से यह 25 मार्च, 1971 (बांग्लादेश का निर्माण) के बाद असम में प्रवेश करने वाले बाहरी लोगों का पता लगाने तथा उनके निर्वासन को अनिवार्य करता है।

79. डिजिटल विज्ञापन नीति, 2023 के निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिये:

1. पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिये विज्ञापन दरें ग्राहक आधार और दर्शकों की संख्या से जुड़ी होंगी, जिनका निर्धारण प्रतिस्पर्द्धी बोली के माध्यम से किया जाएगा।
2. OTT प्लेटफॉर्मों को न केवल नियमित कॉन्टेंट के दौरान विज्ञापन देने के लिये बल्कि एम्बेडेड/इन-फिल्म विज्ञापनों, प्रचार या ब्रांडिंग गतिविधियों हेतु भी सूचीबद्ध किया जा सकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?

- A. केवल 1
- B. केवल 2
- C. 1 और 2 दोनों
- D. न तो 1 और न ही 2

उत्तर: C

व्याख्या:

डिजिटल विज्ञापन नीति, 2023 के तहत प्रमुख नीतियाँ

- डिजिटल प्लेटफॉर्म तक विस्तार:
 - ◆ CBC सोशल मीडिया, ओवर-द-टॉप (OTT) प्लेटफॉर्म, डिजिटल ऑडियो प्लेटफॉर्म, मोबाइल एप्लीकेशन और वेबसाइट्स के माध्यम से विज्ञापन जारी कर सकता है।
 - ◆ यह अनिवार्य करता है कि योजना के तहत आवेदन करने हेतु पात्रता के लिये वेबसाइट, मोबाइल एप, OTT प्लेटफॉर्म और डिजिटल ऑडियो प्लेटफॉर्म को कम-से-कम एक वर्ष पुराना होना चाहिये।
- विज्ञापन दरें और पारदर्शिता:
 - ◆ पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिये विज्ञापन दरें ग्राहक (Subscriber) आधार और दर्शकों की संख्या से जुड़ी होंगी, जिनका निर्धारण प्रतिस्पर्द्धी बोली के माध्यम से किया जाएगा। अतः कथन 1 सही है।

- ◆ इस प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त की गई दरें तीन वर्षों तक वैध रहेंगी।

● OTT प्लेटफॉर्म की भागीदारी

- ◆ OTT प्लेटफॉर्मों को न केवल नियमित कॉन्टेंट के दौरान विज्ञापन देने के लिये बल्कि CBC के आशय-पत्र के अनुसार एम्बेडेड/इन-फिल्म विज्ञापनों, प्रचार या ब्रांडिंग गतिविधियों के प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध किया जा सकता है। अतः कथन 2 सही है।

● फंडिंग स्रोत:

- ◆ CBC आमतौर पर प्रचार और आउटरीच गतिविधियों के लिये सरकारी योजनाओं के कुल परिव्यय के 2% उपयोग करता है तथा इस फंड का उपयोग विज्ञापनों एवं अभियानों के लिये किया जाता है।

80. IPC की धारा 497 में व्यभिचार को एक आपराधिक कृत्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसके लिये पाँच वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सज़ा हो सकती है। निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वसम्मति से धारा 497 को रद्द कर दिया ?

- A. लिली थॉमस और यूनियन ऑफ इंडिया (2013)
- B. स्वतंत्र विचार बनाम भारत संघ (2017)
- C. जोसेफ शाइन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (2018)
- D. ललित कुमार जैन बनाम भारत संघ एवं अन्य (2019)

उत्तर: C

व्याख्या:

- व्यभिचार एक विवाहित व्यक्ति (पुरुष या महिला) द्वारा अपने जीवनसाथी के अलावा किसी अन्य के साथ शारीरिक संबंध बनाने का स्वैच्छिक कार्य है।
- वर्ष 2018 से पहले भारतीय दंड संहिता में धारा 497 शामिल थी, जो व्यभिचार को एक आपराधिक कृत्य के रूप में वर्गीकृत करती थी, जिसमें पाँच वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सज़ा हो सकती थी।
- ◆ विशेष रूप से धारा 497 के तहत केवल पुरुषों को दंड का सामना करना पड़ सकता था, जबकि महिलाओं को अभियोजन से छूट थी।
- ◆ यह व्यभिचार की व्यापक परिभाषा के विपरीत है, जिसमें वैवाहिक जीवन से बाहर स्वैच्छिक शारीरिक संबंधों में शामिल दोनों लिंगों को शामिल किया गया है।
- जोसेफ शाइन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (2018) के एक ऐतिहासिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वसम्मति से धारा 497 को रद्द कर दिया।

- सरकार ने भेदभाव और संवैधानिक उल्लंघनों पर प्रकाश डाला, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 पर जोर देते हुए क्रमशः समानता, गैर-भेदभाव और जीवन एवं स्वतंत्रता की रक्षा की।

● अतः विकल्प C सही है।

81. हरियाणा के निजी क्षेत्र कोटा कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

- हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों का रोजगार अधिनियम, 2020 निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय उम्मीदवारों के लिये 75% आरक्षण प्रदान करता है।
- इसमें 10 या अधिक कर्मचारियों वाले नियोक्ता शामिल थे, लेकिन केंद्र या राज्य सरकारों और उनके संगठनों को छूट थी।
- हरियाणा राज्य का निवासी "स्थानीय उम्मीदवार" एक निर्दिष्ट ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण करके आरक्षण का लाभ उठा सकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं ?

- केवल एक
- केवल दो
- सभी तीन
- इनमें से कोई भी नहीं

उत्तर: C

व्याख्या:

- हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों का रोजगार अधिनियम, 2020 राज्य सरकार द्वारा मार्च 2021 में अधिनियमित किया गया था।
- कानून में 30,000 रुपए (मूल रूप से 50,000 रुपए) से कम मासिक वेतन वाले निजी क्षेत्र के रोजगार में स्थानीय उम्मीदवारों के लिये 10 वर्षों तक 75% आरक्षण का प्रावधान है। अतः कथन 1 सही है।
- इस अधिनियम में कंपनियों, सोसायटी, ट्रस्ट, साझेदारी फर्म और बड़े व्यक्तिगत नियोक्ताओं सहित विभिन्न संस्थाएँ शामिल थीं।
- इसमें 10 या अधिक कर्मचारियों वाले नियोक्ता शामिल थे, लेकिन केंद्र या राज्य सरकारों और उनके संगठनों को छूट थी। अतः कथन 2 सही है।
- कानून के अनुसार, नियोक्ताओं को अपने कर्मचारियों को सरकारी पोर्टल पर पंजीकृत करना होगा और स्थानीय उम्मीदवारों के लिये अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
- हरियाणा राज्य का निवासी "स्थानीय उम्मीदवार" एक निर्दिष्ट ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण करके आरक्षण का लाभ उठा सकता है। अतः कथन 3 सही है।

- इस कानून का उद्देश्य स्थानीय युवाओं, विशेषकर अकुशल तथा अर्द्ध-कुशल श्रमिकों के लिये रोजगार के अवसर एवं उनका कौशल विकास करना व अन्य राज्यों से आने वाले प्रवासियों की संख्या को कम करना था।

82. जमानत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

- दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) "जमानतीय" और "गैर-जमानतीय" अपराधों के बीच अंतर करती है।
- मनमाने ढंग से उल्लंघन के खिलाफ व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिये 1969 की विधि आयोग की रिपोर्ट के सुझाव के बाद CrPC की धारा 438 के तहत "अग्रिम जमानत" का प्रावधान किया गया था।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं ?

- केवल 1
- केवल 2
- 1 और 2 दोनों
- न तो 1 और न ही 2

उत्तर: C

व्याख्या:

जमानत :

- दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) "जमानतीय" तथा "गैर-जमानतीय" अपराधों के बीच अंतर स्पष्ट करती है। अतः कथन 1 सही है।
- यह तीन प्रकार की जमानत को भी परिभाषित करता है- धारा 437 के तहत नियमित जमानत; अंतरिम जमानत अथवा अल्पकालिक जमानत जो तब दी जाती है, जब नियमित अथवा अग्रिम जमानत आवेदन न्यायालय के समक्ष लंबित हो एवं धारा 439 के तहत अग्रिम अथवा पूर्व-गिरफ्तारी जमानत दी जाती है।
- CrPC की धारा 438 के तहत "अग्रिम जमानत" का प्रावधान तब पेश किया गया था जब वर्ष 1969 में 41वें विधि आयोग की रिपोर्ट में एक ऐसे उपाय की आवश्यकता की सिफारिश की गई थी जो किसी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मनमाने उल्लंघन से बचाता है, जैसे कि जब राजनेता अपने विरोधियों को झूठे मामलों में हिरासत में लेते हैं। अतः कथन 2 सही है।
- धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत तब दी जा सकती है, जब "किसी व्यक्ति के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि उसे गैर-जमानतीय अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार किया जा सकता है"। इस धारा के तहत उच्च न्यायालय अथवा सत्र न्यायालय द्वारा गैर-जमानतीय अपराधों के लिये अनुमति दी जा सकती है, जिसके लिये किसी को गिरफ्तारी की आशंका होती है, भले ही वास्तविक गिरफ्तारी न हुई हो अथवा FIR दर्ज न की गई हो।

83. राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. NIA भारत सरकार की एक संघीय एजेंसी है जो आतंकवाद, उग्रवाद और अन्य राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों से संबंधित अपराधों की जाँच एवं मुकदमा चलाने के लिये जिम्मेदार है।
2. इसकी स्थापना वर्ष 2008 में मुंबई आतंकवादी हमलों के बाद वर्ष 2009 में राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA) अधिनियम, 2008 के तहत की गई थी, यह गृह मंत्रालय के तहत संचालित है।
3. NIA के पास राज्य पुलिस बलों और अन्य एजेंसियों से प्राप्त आतंकवाद से संबंधित मामलों की जाँच करने की शक्ति है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं ?

- A. केवल एक
- B. केवल दो
- C. सभी तीन
- D. इनमें से कोई भी नहीं

उत्तर: C

व्याख्या:

- NIA भारत सरकार की एक संघीय एजेंसी है जो आतंकवाद, उग्रवाद और अन्य राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों से संबंधित अपराधों की जाँच एवं मुकदमा चलाने के लिये जिम्मेदार है। अतः कथन 1 सही है।
 - ◆ किसी देश में संघीय एजेंसियों का आमतौर पर उन मामलों पर अधिकार क्षेत्र होता है जो केवल राज्यों या प्रांतों के बजाय पूरे देश को प्रभावित करते हैं।
 - इसकी स्थापना वर्ष 2008 में मुंबई आतंकवादी हमलों के बाद वर्ष 2009 में राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA) अधिनियम, 2008 के तहत की गई थी, यह गृह मंत्रालय के तहत संचालित है। अतः कथन 2 सही है।
 - ◆ NIA अधिनियम, 2008 में संशोधन करते हुए जुलाई 2019 में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2019 पारित किया गया था।
 - NIA के पास राज्य पुलिस बलों और अन्य एजेंसियों से प्राप्त आतंकवाद से संबंधित मामलों की जाँच करने की शक्ति है। इसके पास सरकारों से पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना राज्य की सीमाओं के मामलों की जाँच करने का भी अधिकार है। अतः कथन 3 सही है।
84. सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. अधिनियम के अनुसार, 35 से 45 वर्ष की आयु के बीच की कोई भी महिला सरोगेसी का विकल्प चुन सकती है यदि उसकी कोई चिकित्सीय स्थिति है जिसके कारण यह आवश्यक है।

2. अधिनियम में ऐसे प्रावधान हैं जो महिलाओं को गर्भावधि सरोगेसी का विकल्प चुनने की अनुमति देते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?

- A. केवल 1
- B. केवल 2
- C. 1 और 2 दोनों
- D. न तो 1 और न ही 2

उत्तर: B

व्याख्या:

सरोगेसी:

- सरोगेसी एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक महिला (सरोगेट) किसी अन्य व्यक्ति या जोड़े (इच्छित माता-पिता) की ओर से बच्चे को जन्म देने के लिये सहमत होती है।
- सरोगेट, जिसे कभी-कभी गर्भकालीन वाहक भी कहा जाता है, वह महिला होती है जो किसी अन्य व्यक्ति या जोड़े (इच्छित माता-पिता) के लिये गर्भ धारण करती है और बच्चे को जन्म देती है।

सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021:

- सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 के अनुसार, 35 से 45 वर्ष के बीच की आयु की विधवा या तलाकशुदा महिला तथा कानूनी रूप से विवाहित महिला और पुरुष के रूप में परिभाषित युगल सरोगेसी का लाभ उठा सकते हैं।
- ◆ सरोगेसी के लिये इच्छित जोड़ा कानूनी रूप से विवाहित भारतीय पुरुष एवं महिला का होगा, पुरुष की आयु 26-55 वर्ष के बीच होगी तथा महिला की आयु 25-50 वर्ष के बीच होगी और उनका पहले से कोई जैविक, गोद लिया हुआ या सरोगेट बच्चा नहीं होगा। अतः कथन 1 सही नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में किये गये बदलाव:

- मार्च 2023 में एक सरकारी अधिसूचना ने प्रदाता युग्मकों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाते हुए कानून में संशोधन किया।
- ◆ इसमें कहा गया है कि "इच्छुक जोड़ों" को सरोगेसी के लिये अपने स्वयं के युग्मकों का उपयोग करना होगा।
- न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जब सरोगेसी नियमों का नियम 14(a) लागू होता है, जो चिकित्सा या जन्मजात स्थितियों को सूचीबद्ध करता है तथा एक महिला को गर्भकालीन/जेस्टेशनल सरोगेसी का विकल्प चुनने की अनुमति देता है, तो बच्चा इच्छित जोड़े, विशेषकर पिता से संबंधित होना चाहिये।

◆ **जेस्टेशनल सरोगेसी** एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक महिला दूसरे व्यक्ति या जोड़े के लिये एक बच्चे को जन्म देती है। इसमें सरोगेट मदर बच्चे की बायोलॉजिकल माँ नहीं होती है, बल्कि वह सिर्फ बच्चे को जन्म देती है। **अतः कथन 2 सही है।**

- सर्वोच्च न्यायालय ने उन महिलाओं के लिये सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 के नियम 7 को प्रतिबंधित किया है जो **मेयर-रोकितांस्की-कुस्टर-हॉसर (MRKH) सिंड्रोम** (एक असामान्य जन्मजात विकार जो महिला प्रजनन प्रणाली को प्रभावित करता है) से पीड़ित हैं, ताकि पीड़ित महिला को प्रदाता डिम्ब/अंडाणु का प्रयोग करके सरोगेसी के क्रियान्वयन की अनुमति दी जा सके।
- ◆ सरोगेसी अधिनियम का नियम 7 प्रक्रिया के लिये प्रदाता डिम्ब/अंडाणु के उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है।

85. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. भारत सड़क सुरक्षा पर दूसरे वैश्विक उच्च-स्तरीय सम्मेलन में हस्ताक्षरित सड़क सुरक्षा पर ब्राजीलिया घोषणा का एक हस्ताक्षरकर्ता है।
2. सतत् विकास लक्ष्य-3 का उद्देश्य सड़क यातायात दुर्घटनाओं से होने वाली वैश्विक मौतों और चोटों को आधा करना है।
3. संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सड़क सुरक्षा के लिये कार्रवाई दशक 2021-2030 को अपनाया है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं ?

- A. केवल एक
- B. केवल दो
- C. सभी तीन
- D. इनमें से कोई भी नहीं

उत्तर: C

व्याख्या:

भारत में सड़क दुर्घटनाएँ, 2022:

हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 'भारत में सड़क दुर्घटनाएँ- 2022' शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, जो सड़क दुर्घटनाओं और इससे होने वाली मृत्यु से संबंधित मामलों पर प्रकाश डालती है।

सड़क सुरक्षा से संबंधित पहल:

- सड़क सुरक्षा पर ब्राजीलिया घोषणा (2015):
 - ◆ इस घोषणा पर ब्राजील में आयोजित सड़क सुरक्षा पर दूसरे वैश्विक उच्च-स्तरीय सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षर किये गए। भारत भी इस घोषणापत्र का एक हस्ताक्षरकर्ता है। **अतः कथन 1 सही है।**

◆ देशों की योजना **सतत् विकास लक्ष्य 3.6** अर्थात् वर्ष 2030 तक सड़क यातायात दुर्घटनाओं से होने वाली वैश्विक मौतों और चोटों की संख्या को आधा करने की है। अतः कथन 2 सही है।

■ **SDG लक्ष्य 3.6:** सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों और आघात को कम करना।

- सड़क सुरक्षा के लिये कार्रवाई का दशक 2021-2030:

◆ **संयुक्त राष्ट्र महासभा** ने वर्ष 2030 तक कम-से-कम 50% सड़क यातायात दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों और चोटों को रोकने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के साथ **"वैश्विक सड़क सुरक्षा में सुधार"** संकल्प को अपनाया। **अतः कथन 2 सही है।**

◆ वैश्विक योजना सड़क सुरक्षा के लिये समग्र दृष्टिकोण के महत्त्व पर बल देते हुए **स्टॉकहोम घोषणा** के अनुरूप है।

86. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. CBI दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (DSPE) अधिनियम, 1946 के तहत कार्य करती है।
2. यह न तो संवैधानिक और न ही वैधानिक निकाय है।
3. इसकी स्थापना गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव द्वारा की गई थी और बाद में इसे कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही नहीं हैं ?

- A. केवल एक
- B. केवल दो
- C. सभी तीन
- D. इनमें से कोई भी नहीं

उत्तर: D

व्याख्या:

केंद्रीय जाँच ब्यूरो (CBI):

- CBI की स्थापना गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव द्वारा की गई थी और बाद में इसे कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय को स्थानांतरित कर दिया गया, जो वर्तमान में एक संलग्न कार्यालय के रूप में कार्य कर रहा है। **अतः कथन 1 सही है।**
- इसकी स्थापना भ्रष्टाचार निवारण पर संथानम समिति के सुझावों पर की गई थी।
- CBI दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (DSPE) अधिनियम, 1946 के तहत कार्य करती है। यह न तो एक संवैधानिक और न ही वैधानिक निकाय है। **अतः कथन 2 और 3 दोनों सही हैं।**
- यह रिश्वतखोरी, सरकारी भ्रष्टाचार, केंद्रीय कानूनों के उल्लंघन, बहु-राज्य संगठित अपराध और बहु-एजेंसी या अंतर्राष्ट्रीय मामलों से संबंधित मामलों की जाँच करती है।

87. भारतीय गुणवत्ता परिषद (QCI) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. QCI खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का एक स्वायत्त संगठन है।
2. IndG.AP, भारत में सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण कृषि उत्पादों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये QCI द्वारा विकसित एक प्रमाणन योजना है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?

- A. केवल 1
- B. केवल 2
- C. 1 और 2 दोनों
- D. न तो 1 और न ही 2

उत्तर: B

व्याख्या:

भारतीय गुणवत्ता परिषद (QCI)

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (DPIIT) के एक स्वायत्त संगठन, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (QCI) ने नई दिल्ली में सतत व्यापार और मानकों (ICSTS) पर तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेज़बानी की। अतः कथन 1 सही नहीं है।

- ICSTS का उद्देश्य स्वैच्छिक स्थिरता मानकों (VSS) की चुनौतियों और अवसरों पर जागरूकता एवं संवाद को बढ़ावा देना है, जो वैश्विक मूल्य शृंखलाओं के पर्यावरणीय व सामाजिक पहलुओं को बेहतर बनाने के उपकरण हैं।

मुख्य बिंदु:

- भारतीय अच्छी कृषि पद्धतियाँ (IndG.AP.):
 - ◆ IndG.AP, भारत में सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण कृषि उत्पादों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये QCI द्वारा विकसित एक प्रमाणन योजना है।
 - ◆ IndG.AP कृषि के विभिन्न पहलुओं जैसे- मृदा, जल, फसल स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण, श्रमिक कल्याण और खाद्य सुरक्षा को कवर करती हैं। अतः कथन 2 सही है।
- वैश्विक अच्छी कृषि पद्धतियाँ (GLOBALG.A.P.):
 - ◆ यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मान्यता प्राप्त मानक है जो बढ़ते पौधों, सब्जियों, कंद, फलों, पोल्ट्री, मवेशियों और जलीय उत्पादों के क्षेत्र में गुणवत्ता प्रबंधन, सुरक्षा तथा ट्रेसबिलिटी सुनिश्चित करती है।

● राष्ट्रीय तकनीकी कार्य समूह (NTWG):

- ◆ NTWG एक ऐसा समूह है जो वैश्विक और स्थानीय मुद्दों के बीच अंतर को पाटता है। वे राष्ट्रीय स्तर पर अनुकूलन और अनुप्रयोग चुनौतियों की पहचान करते हैं तथा राष्ट्रीय व्याख्या दिशा-निर्देश (NIG) विकसित करते हैं। NIG पूरे विश्व में लागत प्रभावी ऑडिट प्रक्रियाओं का समर्थन करते हैं।

भारतीय गुणवत्ता परिषद (QCI):

- QCI वर्ष 1860 के सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम XXI के तहत पंजीकृत एक गैर-लाभकारी संगठन है।
- यह भारत सरकार और भारतीय उद्योग द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया था, जिसका प्रतिनिधित्व तीन प्रमुख उद्योग संघों, एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (ASSOCHAM), भारतीय उद्योग परिषद (CII) और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FICCI) ने वर्ष 1997 में किया था।
- QCI की स्थापना भारत में विभिन्न क्षेत्रों में गुणवत्ता मानकों को बढ़ावा देने लिये की गई थी।
- यह भारत में मान्यता, प्रमाणन और गुणवत्ता संवर्द्धन हेतु जिम्मेदार है।
- DPIIT, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को गुणवत्ता तथा QCI से जुड़े सभी मामलों के लिये कैबिनेट निर्णय की संरचना एवं कार्यान्वयन में सहायता के लिये नोडल बिंदु के रूप में नामित किया गया था।

88. आधार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. आधार पहचान मंच 'डिजिटल इंडिया' के प्रमुख स्तंभों में से एक है, जिसमें देश के प्रत्येक निवासी को एक विशिष्ट पहचान प्रदान की जाती है।
2. आधार संख्या पहचान का प्रमाण है एवं नागरिकता अथवा अधिवास का अधिकार प्रदान करती है।
3. कोई भी व्यक्ति, किसी भी उम्र तथा लिंग का हो, भारत का निवासी है, स्वेच्छा से आधार संख्या प्राप्त करने के लिये नामांकन कर सकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं ?

- A. केवल एक
- B. केवल दो
- C. सभी तीन
- D. इनमें से कोई भी नहीं

उत्तर: B

व्याख्या:

आधार:

- आधार संख्या प्राधिकरण द्वारा निर्धारित सत्यापन प्रक्रिया को पूरा करने के बाद भारत के निवासियों को UIDAI ("प्राधिकरण") द्वारा जारी किया गया एक 12-अंकीय यादृच्छिक संख्या है।
- आधार पहचान मंच 'डिजिटल इंडिया' के प्रमुख स्तंभों में से एक है, जिसमें देश के प्रत्येक निवासी को एक विशिष्ट पहचान प्रदान की जाती है। अतः कथन 1 सही है।
- आधार संख्या पहचान का प्रमाण है, हालाँकि यह आधार संख्या धारक के संबंध में नागरिकता अथवा अधिवास का कोई अधिकार प्रदान नहीं करती है। अतः कथन 2 सही नहीं है।
- कोई भी व्यक्ति, किसी भी उम्र तथा लिंग का जो कि भारत का निवासी है, आधार संख्या प्राप्त करने के लिये स्वेच्छा से नामांकन कर सकता है। अतः कथन 3 सही है।

89. गैर-कानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. UAPA आपराधिक कानून के लिये एक वैकल्पिक संरचना पेश करता है, जिसमें आपराधिक कानून के सामान्य सिद्धांतों को उलट दिया जाता है।
2. UAPA के तहत जमानत से इनकार करने के मानदंड के लिये न्यायालय को आश्वस्त होना होगा कि आरोपी के खिलाफ "प्रथम दृष्टया" मामला है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं:

- A. केवल 1
- B. केवल 2
- C. 1 और 2 दोनों
- D. न तो 1 और न ही 2

उत्तर: C

व्याख्या:

गैर-कानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (UAPA):

- UAPA एक वैकल्पिक आपराधिक कानूनी ढाँचा प्रस्तुत करता है जहाँ आपराधिक कानून के सामान्य सिद्धांत उलट जाते हैं। अतः कथन 1 सही है।
- राज्य को आरोपपत्र दाखिल करने की समय-सीमा और जमानत के लिये कड़ी शर्तों में छूट देकर, UAPA राज्य को भारतीय दंड संहिता (IPC) की तुलना में अधिक शक्तियाँ देता है।

- वर्ष 1967 में अधिनियमित UAPA को वर्ष 2008 और 2012 में सरकार द्वारा मज़बूत किया गया था।
- UAPA के तहत जमानत से इनकार करने की कसौटी यह है कि न्यायालय को संतुष्ट होना चाहिये कि आरोपी के खिलाफ "प्रथम दृष्टया" मामला मौजूद है। अतः कथन 2 सही है।
- वर्ष 2019 में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रथम दृष्टया इसे संकीर्ण रूप से परिभाषित करते हुए कहा कि न्यायालयों को सबूतों या परिस्थितियों का विश्लेषण नहीं करना चाहिये, बल्कि राज्य द्वारा प्रस्तुत "मामले की समग्रता" को देखना चाहिये।
- NIA बनाम ज़हूर अहमद वटाली मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने जमानत प्रावधानों को सख्ती से पढ़ा, यह मानते हुए कि न्यायालयों को केवल इस बात से संतुष्ट होना चाहिये कि जमानत से इनकार करने के लिये प्रथम दृष्टया मामला बनाया जा सकता है और सबूत की प्रमाणिकता या स्वीकार्यता पर विचार नहीं करना चाहिये।

90. राजनीतिक फंडिंग जुटाने के तरीकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. भारत में कॉर्पोरेट निकायों द्वारा फंडिंग को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत नियंत्रित किया जाता है।
2. चुनावी बॉण्ड योजना व्यक्तियों और संस्थाओं के लिये दाता की गुमनामी बनाए रखते हुए पंजीकृत राजनीतिक दलों को दान देने के साधन के रूप में कार्य करती है।
3. चुनावी ट्रस्ट योजना, 2013 के तहत एक चुनावी ट्रस्ट की स्थापना कंपनियों द्वारा की जाती है, जिसका एकमात्र उद्देश्य अन्य कंपनियों तथा व्यक्तियों से प्राप्त योगदान को राजनीतिक दलों में वितरित करना है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही नहीं हैं ?

- A. केवल एक
- B. केवल दो
- C. सभी तीन
- D. इनमें से कोई भी नहीं

उत्तर: A

व्याख्या:

राजनीतिक फंडिंग - राजनीतिक फंडिंग जुटाने के तरीके:

- एकल व्यक्ति: RPA की धारा 29B राजनीतिक दलों को एकल व्यक्तियों से दान प्राप्त करने की अनुमति देती है, जबकि करदाताओं को 100% कटौती का दावा करने की अनुमति देती है।
- राज्य/सार्वजनिक अनुदान: यहाँ सरकार चुनाव संबंधी उद्देश्यों के लिये पार्टियों को धन मुहैया कराती है। राज्य वित्तपोषण दो प्रकार का होता है:

- ◆ **प्रत्यक्ष धन:** सरकार राजनीतिक दलों को सीधे धन प्रदान करती है। हालाँकि भारत में प्रत्यक्ष फंडिंग प्रतिबंधित है।
 - ◆ **अप्रत्यक्ष फंडिंग:** इसमें प्रत्यक्ष फंडिंग को छोड़कर अन्य तरीके शामिल हैं, जैसे मीडिया तक निःशुल्क पहुँच, रैलियों के लिये सार्वजनिक स्थानों पर निःशुल्क पहुँच, निःशुल्क या रियायती परिवहन सुविधाएँ। भारत में इसके विनियमन की अनुमति दी गई है।
 - **कॉर्पोरेट फंडिंग:** भारत में कॉर्पोरेट निकायों द्वारा दान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 182 के तहत नियंत्रित किया जाता है। अतः कथन 1 सही नहीं है।
 - **चुनावी बॉण्ड योजना:** चुनावी बॉण्ड प्रणाली को वर्ष 2017 में एक वित्त विधेयक के माध्यम से पेश किया गया था और इसे वर्ष 2018 में लागू किया गया था।
 - ◆ वे दाता की गोपनीयता बनाए रखते हुए व्यक्तियों और संस्थाओं के लिये पंजीकृत राजनीतिक दलों को फंडिंग देने के साधन के रूप में कार्य करते हैं। अतः कथन 2 सही है।
 - **चुनावी ट्रस्ट योजना, 2013:** इसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा अधिसूचित किया गया था।
 - ◆ इलेक्टोरल ट्रस्ट कंपनियों द्वारा स्थापित एक ट्रस्ट है जिसका एकमात्र उद्देश्य अन्य कंपनियों एवं व्यक्तियों से प्राप्त योगदान को राजनीतिक दलों में वितरित करना है। अतः कथन 3 सही नहीं है।
91. अपशिष्ट बैटरी प्रबंधन नियम, 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
1. नियम सभी प्रकार की बैटरियों को कवर करते हैं, जिनमें इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी, पोर्टेबल बैटरी, ऑटोमोटिव बैटरी और औद्योगिक बैटरी शामिल हैं।
 2. विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व के तहत दायित्वों को पूरा करने के लिये निर्माता अपशिष्ट बैटरियों के संग्रह, पुनर्चक्रण या नवीनीकरण हेतु स्वयं को संलग्न कर सकते हैं या किसी अन्य इकाई को अधिकृत कर सकते हैं।
 3. नियमों में निर्धारित विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व के तहत पर्यावरण संबंधी लक्ष्यों, जिम्मेदारियों तथा कर्तव्यों को पूरा न करने पर जुर्माने का प्रावधान है।
- उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं ?
- A. केवल एक
 - B. केवल दो
 - C. सभी तीन
 - D. इनमें से कोई भी नहीं

उत्तर: C

व्याख्या:

- **कवरेज:**
 - ◆ नियम सभी प्रकार की बैटरियों को कवर करते हैं, जिनमें इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी, पोर्टेबल बैटरी, ऑटोमोटिव बैटरी और औद्योगिक बैटरी शामिल हैं। अतः कथन 1 सही है।
 - **विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR):**
 - ◆ बैटरी निर्माता बेकार बैटरियों के संग्रहण और पुनर्चक्रण/नवीनीकरण तथा अपशिष्ट से प्राप्त सामग्री को नई बैटरियों में उपयोग करने के लिये जिम्मेदार हैं। नियम लैंडफिल एवं भस्मीकरण के रूप में निपटान पर रोक लगाते हैं।
 - विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (Extended Producer Responsibility- EPR) के तहत दायित्वों को पूरा करने के लिये निर्माता अपशिष्ट बैटरियों के संग्रह, पुनर्चक्रण या नवीनीकरण हेतु स्वयं को संलग्न कर सकते हैं या किसी अन्य इकाई को अधिकृत कर सकते हैं। अतः कथन 2 सही है।
 - **EPR प्रमाणपत्रों के आदान-प्रदान हेतु ऑनलाइन पोर्टल:**
 - ◆ यह उत्पादकों के दायित्वों को पूरा करने के लिये उत्पादकों और रिसाइक्लर्स/रीफर्बिशर्स के बीच EPR प्रमाणपत्रों के आदान-प्रदान के लिये एक तंत्र तथा केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल स्थापित करने में सक्षम होगा।
 - **ऑनलाइन पंजीकरण:**
 - ◆ ऑनलाइन पंजीकरण और रिपोर्टिंग, अंकेक्षण (ऑडिटिंग) एवं नियमों पर अमल करने हेतु निगरानी के लिये समिति तथा कठिनाइयों के समाधान हेतु आवश्यक उपाय करना इन नियमों की मुख्य विशेषताएँ हैं, इससे प्रभावकारी कार्यान्वयन और अनुपालन सुनिश्चित किया जा सकेगा।
 - **प्रदूषक भुगतान (Polluter Pays) का सिद्धांत:**
 - ◆ नियमों में निर्धारित विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (Extended Producer Responsibility) के तहत पर्यावरण संबंधी लक्ष्यों, जिम्मेदारियों तथा कर्तव्यों को पूरा न करने पर जुर्माने का प्रावधान है। अतः कथन 3 सही है।
92. भारत में निम्नलिखित में से कौन-सा विधायी ढाँचा शरणार्थियों से निपटने का प्रावधान करता है ?
1. विदेशी अधिनियम, 1946
 2. पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920
 3. विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम, 1939
 4. नागरिकता अधिनियम, 1955

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं/हैं ?

- केवल एक
- केवल दो
- केवल तीन
- सभी चार

उत्तर: D

व्याख्या:

- भारत सभी विदेशियों के साथ अच्छा व्यवहार करता है, चाहे वे अवैध अप्रवासी हों, शरणार्थी या वीजा परमिट से अधिक समय तक रहने वाले हों।
- ◆ विदेशी अधिनियम, 1946: धारा 3 के तहत केंद्र सरकार को अवैध विदेशी नागरिकों का पता लगाने, हिरासत में लेने और निर्वासित करने का अधिकार है। अतः कथन 1 सही है।
- ◆ पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920: धारा 5 के तहत अधिकारी भारत के संविधान के अनुच्छेद 258(1) के तहत किसी अवैध विदेशी को बलपूर्वक हटा सकते हैं। अतः कथन 2 सही है।
- ◆ विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम 1939: इसके तहत एक अनिवार्य आवश्यकता है जिसके तहत दीर्घकालिक वीजा (180 दिनों से अधिक) पर भारत आने वाले सभी विदेशी नागरिकों (भारत के विदेशी नागरिकों को छोड़कर) को भारत पहुँचने के 14 दिनों के भीतर खुद को जीकरण अधिकारी के साथ पंजीकृत करना आवश्यक है। अतः कथन 3 सही है।
- ◆ नागरिकता अधिनियम, 1955: इसमें नागरिकता के त्याग, समाप्ति और वंचित करने के प्रावधान प्रदान किये गए।
 - इसके अलावा नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 (CAA) बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सताए गए हिंदू, ईसाई, जैन, पारसी, सिख तथा बौद्ध प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करना चाहता है। अतः कथन 4 सही है।

93. धोखाधड़ी वाले ऋण एप्स और डिजिटल ऋण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

- नकली ऋण एप्स अनधिकृत और अवैध डिजिटल ऋण प्रदाता प्लेटफॉर्म हैं जो कम आय और कमजोर वित्तीय स्थिति वाले व्यक्तियों को लक्षित करते हुए 1,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करते हैं।
- धोखाधड़ी वाले ऋण एप्स पूरी तरह से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित होते हैं और कोई अन्य संस्था इसे विनियमित करने के लिये अधिकृत नहीं है।

- आरबीआई ने डिजिटल ऋण को विनियमित करने के लिये अब तक कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं किया है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं ?

- केवल एक
- केवल दो
- सभी तीन
- इनमें से कोई भी नहीं

उत्तर: A

व्याख्या:

- धोखाधड़ी वाले ऋण एप्स अनधिकृत और अवैध डिजिटल ऋण देने वाले प्लेटफॉर्म हैं जो कम आय और कमजोर वित्तीय स्थिति वाले लोगों को लक्षित कर 1,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करते हैं।
 - ◆ वे बिना किसी क्रेडिट जाँच, दस्तावेज या संपार्श्विक के तत्काल और बिना किसी परेशानी के ऋण प्रदान करने का दावा करते हैं। अतः कथन 1 सही है।
 - हितधारक, सरकार और नियामक मानदंडों की अनुपस्थिति की कमी को उजागर करते हैं, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को अपेक्षित प्रयास (Minimal due Diligence) की अनुमति देता है।
 - ◆ भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY), भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) एवं राज्य सरकारों जैसे विभिन्न नियामकों के बीच समन्वय एवं पर्यवेक्षण का अभाव है। अतः कथन 2 सही नहीं है।
 - हालाँकि RBI ने सितंबर 2022 में डिजिटल ऋण देने हेतु दिशा-निर्देश जारी किये लेकिन ये दिशा-निर्देश केवल बैंकों और NBFC जैसी विनियमित संस्थाओं पर लागू होते हैं। कारणवश धोखाधड़ी करने वाले एप्स पर नियंत्रण लगाना मुश्किल हो जाता है। अतः कथन 3 सही नहीं है।
94. नई शिक्षा नीति (NEP), 2020 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
- केंद्र सरकार ने सभी राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों में कक्षा 1 के लिये प्रवेश की न्यूनतम आयु छह वर्ष करने का आदेश दिया है।
 - नई नई शिक्षा नीति 3-10 वर्ष (मूलभूत चरण), 10-14 वर्ष (प्रारंभिक चरण), 14-16 वर्ष (मध्यम चरण) और 16-18 वर्ष (माध्यमिक चरण) के आयु समूहों के अनुरूप औपचारिक स्कूली शिक्षा के लिये "5+3+3+4" की रूपरेखा पर जोर देती है।

3. यह प्रारंभिक बचपन की शिक्षा (जिसे 3 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों के लिये प्रीस्कूल शिक्षा के रूप में भी जाना जाता है) को औपचारिक स्कूली शिक्षा के दायरे में लाती है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं ?

- A. केवल एक
B. केवल दो
C. सभी तीन
D. इनमें से कोई भी नहीं

उत्तर: B

व्याख्या:

नई शिक्षा नीति, 2020 :

- मार्च 2022 तक 14 राज्य तथा केंद्रशासित प्रदेश ऐसे थे, जो छह वर्ष से कम आयु के बच्चों को कक्षा 1 में प्रवेश की अनुमति देते थे।
- ◆ हालाँकि केंद्र सरकार ने हाल ही में नई शिक्षा नीति (NEP), 2020 के तहत सभी राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों में कक्षा 1 के लिये प्रवेश की न्यूनतम आयु छह वर्ष करने का आदेश दिया है। अतः कथन 1 सही है।
- नई नई शिक्षा नीति 3-8 वर्ष (मूलभूत चरण), 8-11 वर्ष (प्रारंभिक चरण), 11-14 वर्ष (मध्यम चरण) और 14-18 वर्ष (माध्यमिक चरण) के आयु समूहों के अनुरूप औपचारिक स्कूली शिक्षा के लिये "5+3+3+4" की रूपरेखा पर जोर देती है। अतः कथन 2 सही नहीं है।
- यह प्रारंभिक बचपन की शिक्षा (जिसे 3 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों के लिये प्रीस्कूल शिक्षा के रूप में भी जाना जाता है) को औपचारिक स्कूली शिक्षा के दायरे में लाती है। अतः कथन 3 सही है।
- ◆ इसका अर्थ यह है कि तीन वर्ष की प्रारंभिक बचपन की शिक्षा पूरी करने के बाद कक्षा 1 में प्रवेश के लिये बच्चे की उम्र 6 वर्ष होनी चाहिये।

95. 'भारत में डेटा गवर्नेंस' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. अज्ञात डेटा सेट में व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी के साथ एकत्रित जानकारी शामिल होती है।
2. डिजिटल इंडिया बिल के तहत बड़ी तकनीकी कंपनियों को उनके पास मौजूद सभी गैर-व्यक्तिगत डेटा को सरकार समर्थित

डेटाबेस में जमा करने के लिये बाध्य करने का प्रावधान है, जिसे भारत डेटासेट प्लेटफॉर्म के रूप में जाना जाता है।

3. डिजिटल इंडिया बिल के तहत भारत डेटासेट प्लेटफॉर्म द्वारा रखे गए गैर-व्यक्तिगत डेटा का मुद्राकरण किया जा सकता है, जो आर्थिक लाभ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं ?

- A. केवल एक
B. केवल दो
C. सभी तीन
D. इनमें से कोई भी नहीं

उत्तर: B

व्याख्या:

- अज्ञात डेटा सेट ऐसा डेटा सेट है जिसमें व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी नहीं होती है। इसमें किसी विशेष जनसांख्यिकी का समग्र स्वास्थ्य डेटा, किसी क्षेत्र का मौसम और जलवायु डेटा, ट्रैफिक डेटा, अन्य जैसी समग्र जानकारी शामिल हो सकती है।
- ◆ यह व्यक्तिगत डेटा से अलग है, यह वह डेटा है जो किसी पहचाने गए या पहचाने जाने योग्य व्यक्ति से संबंधित होता है, जैसे- ईमेल, बायोमेट्रिक्स इत्यादि। अतः कथन 1 सही नहीं है।
- डिजिटल इंडिया बिल के तहत बड़ी तकनीकी कंपनियों को उनके पास मौजूद सभी गैर-व्यक्तिगत डेटा को सरकार समर्थित डेटाबेस में जमा करने के लिये बाध्य करने का प्रावधान है, जिसे भारत डेटासेट प्लेटफॉर्म के रूप में जाना जाता है। अतः कथन 2 सही है।
- डिजिटल इंडिया बिल के तहत भारत डेटासेट प्लेटफॉर्म द्वारा रखे गए गैर-व्यक्तिगत डेटा का मुद्राकरण किया जा सकता है, जो आर्थिक लाभ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अतः कथन 3 सही है।

96. शहरों के लिये AAINA डैशबोर्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. यह शहरों को दूसरों के सापेक्ष उनके प्रदर्शन का आकलन करने में मदद करने के लिये आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की एक पहल है।
2. डैशबोर्ड डेटा को दो श्रेणियों में विभाजित करता है: राजनीतिक और प्रशासनिक संरचना।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?

- A. केवल 1
B. केवल 2
C. 1 और 2 दोनों
D. न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (a)

व्याख्या:

शहरों के लिये AAINA डैशबोर्ड:

आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) ने 'AAINA डैशबोर्ड फॉर सिटीज़' पोर्टल लॉन्च किया, जो शहरी स्थानीय निकायों (ULB) को स्वेच्छा से प्रमुख डेटा प्रस्तुत करने के लिये एक मंच प्रदान करता है।

- AAINA का लक्ष्य शहरों को दूसरों के सापेक्ष उनके प्रदर्शन का आकलन करने में सहायता करना है। संभावनाओं और वृद्धि के क्षेत्रों को उजागर करके शहरों को प्रेरित करना है। अतः कथन 1 सही है।
- डैशबोर्ड डेटा को पाँच स्तंभों में वर्गीकृत करता है: राजनीतिक एवं प्रशासनिक संरचना, वित्त, योजना, नागरिक-केंद्रित शासन और बुनियादी सेवाओं की डिलीवरी। अतः कथन 2 सही नहीं है।
- ◆ ULB एक उपयोगकर्ता-अनुकूल पोर्टल के माध्यम से नियमित रूप से ऑडिट किये गए खातों और स्व-रिपोर्ट किये गए प्रदर्शन मेट्रिक्स सहित डेटा जमा करेंगे।
- ◆ AAINA की कल्पना ULB-संबंधित डेटा के लिये एक स्थायी मंच के रूप में की गई है, जो प्रमुख प्रदर्शन मेट्रिक्स का एक व्यापक डेटाबेस है। सक्रिय ULB सहयोग के साथ डैशबोर्ड का लक्ष्य एक सार्वजनिक संसाधन सुनिश्चित करना है, जो हितधारकों को एकत्रित डेटा तक पहुँचने और उसका उपयोग करने की अनुमति देता है।

97. वर्ष 1971 के मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी (MTP) अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. यह लाइसेंस प्राप्त चिकित्सा पेशेवरों को कानून के तहत प्रदान की गई विशिष्ट पूर्व निर्धारित स्थितियों में गर्भपात करने की अनुमति देता है।
2. MTP अधिनियम में 2021 में संशोधन किया गया था ताकि कुछ श्रेणियों की महिलाओं को गर्भधारण के 22 सप्ताह तक गर्भपात कराने की अनुमति दी जा सके, इसे विगत वर्ष की तुलना में 20 सप्ताह से अधिक बढ़ाया गया था।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?

- A. केवल 1
- B. केवल 2
- C. 1 तथा 2 दोनों
- D. न तो 1 और न ही 2

उत्तर: A

व्याख्या:

भारत में गर्भपात से संबंधित कानूनी प्रावधान:

- 1960 के दशक तक भारत में गर्भपात अवैध था। विनियमों की आवश्यकता की जाँच करने के लिये वर्ष 1960 के दशक के मध्य में शांतिलाल शाह समिति का गठन किया गया था। परिणामस्वरूप, वर्ष 1971 का मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी (MTP) अधिनियम पारित किया गया, जिससे सुरक्षित गर्भपात को वैध बनाया गया और महिलाओं के स्वास्थ्य की रक्षा की गई।
 - ◆ वर्ष 1971 का MTP अधिनियम, लाइसेंस प्राप्त चिकित्सा पेशेवरों को कानून के तहत प्रदान की गई विशिष्ट पूर्व निर्धारित स्थितियों में गर्भपात करने की अनुमति देता है। अतः कथन 1 सही है।
 - ◆ MTP अधिनियम में वर्ष 2021 में संशोधन किया गया था ताकि कुछ श्रेणियों की महिलाओं, जैसे कि बलात्कार पीड़िताओं, नाबालिगों, मानसिक रूप से बीमार महिलाओं आदि को गर्भधारण के 24 सप्ताह तक गर्भपात कराने की अनुमति दी जा सके, इसे पूर्व की तुलना में 20 सप्ताह से अधिक बढ़ाया गया था। अतः कथन 2 सही नहीं है।
 - यह राज्य-स्तरीय मेडिकल बोर्ड का गठन करता है जो यह तय करता कि भ्रूण में पर्याप्त असामान्यताओं के मामलों में 24 सप्ताह के बाद गर्भावस्था को समाप्त किया जा सकता है या नहीं।
 - MTP अधिनियम सुरक्षित गर्भपात सेवाओं तक पहुँचने में महिलाओं की गोपनीयता, निजता और गरिमा की सुरक्षा भी प्रदान करता है।
98. विमान नियमावली, 1937 में संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
1. ये संशोधन विमानन सुरक्षा को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
 2. संशोधित लाइसेंसिंग प्रक्रिया और अनावश्यक नियमावलियों को हटाने से अधिक व्यापार-अनुकूल वातावरण के निर्माण में योगदान मिल सकता है।
 3. संशोधन भारत के विमानन नियमों को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के मानकों के साथ संरेखित करते हैं।
- उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं ?
- A. केवल एक
 - B. केवल दो
 - C. सभी तीन
 - D. इनमें से कोई भी नहीं

उत्तर: C

व्याख्या:

विमान नियमावली, 1937 में प्रमुख संशोधन:

- ये संशोधन हवाई अड्डों के आसपास "फॉल्स लाइट्स" के प्रदर्शन से संबंधित चिंताओं का समाधान करके विमानन सुरक्षा को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अतः कथन 1 सही है।
- सुव्यवस्थित लाइसेंसिंग प्रक्रिया और अनावश्यक नियमावलियों को हटाने से अधिक व्यापार-अनुकूल वातावरण में योगदान मिल सकता है, निवेश आकर्षित हो सकता है तथा विमानन उद्योग में विकास को बढ़ावा मिल सकता है। अतः कथन 2 सही है।
- ये संशोधन भारत के विमानन नियमों को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (International Civil Aviation Organization- ICAO) के मानकों और अनुशंसित प्रथाओं (SARP) तथा अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ संरेखित करते हैं। अतः कथन 3 सही है।

99. आपराधिक प्रक्रिया पहचान अधिनियम (CrPI), 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. आपराधिक प्रक्रिया पहचान अधिनियम (CrPI), 2022 केंद्रीय जाँच एजेंसियों को गिरफ्तार व्यक्तियों के रेटिना और आईरिस स्कैन जैसे भौतिक एवं जैविक नमूने एकत्र करने, संग्रहीत करने तथा उनका विश्लेषण करने का अधिकार देता है।
2. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) को अधिनियम को लागू करने तथा मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) स्थापित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
3. CrPI अधिनियम में सीधे तौर पर जाँच के उद्देश्य से DNA नमूनों और फेस मैचिंग प्रक्रियाओं के उपयोग का उल्लेख किया गया है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं ?

- A. केवल एक
- B. केवल दो
- C. सभी तीन
- D. इनमें से कोई भी नहीं

उत्तर: B

व्याख्या:

- आपराधिक प्रक्रिया पहचान अधिनियम (CrPI), 2022 पुलिस और केंद्रीय जाँच एजेंसियों को गिरफ्तार व्यक्तियों के

भौतिक एवं जैविक नमूनों को इकट्ठा करने, उन्हें संग्रहीत करने तथा विश्लेषण करने का अधिकार देता है, जिसमें रेटिना व आईरिस स्कैन भी शामिल हैं। अतः कथन 1 सही है।

- इस विधायी कदम का उद्देश्य कानून प्रवर्तन क्षमताओं को बढ़ाना और आपराधिक पहचान तथा डेटा प्रबंधन में एक नए युग की शुरुआत करना है।
- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) को अधिनियम को लागू करने तथा मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) स्थापित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अतः कथन 2 सही है।
- NCRB ने इन मामलों को रिकॉर्ड करने के लिये उचित प्रोटोकॉल पर पुलिस अधिकारियों का मार्गदर्शन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- CrPI अधिनियम में सीधे तौर पर DNA नमूना संग्रह और फेस मैचिंग प्रक्रियाओं का उल्लेख नहीं किया गया था, लेकिन NCRB ने राज्य पुलिस अधिकारियों के साथ चर्चा में इन उपायों को लागू करने की योजना बनाई। अतः कथन 3 सही नहीं है।

100. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के अनुसार निम्नलिखित में से किसे कारागार में अप्राकृतिक मृत्यु के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा ?

1. हृदय रोग के कारण मृत्यु
2. एच.आई.वी. बीमारी से मृत्यु
3. भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा से मृत्यु

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिये:

- A. केवल 1 और 2
- B. केवल 3
- C. 1, 2 और 3
- D. उपर्युक्त में से कोई नहीं

उत्तर: B

व्याख्या:

- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (National Crime Records Bureau- NCRB) द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रकाशित की जाने वाली प्रिज़न स्टैटिस्टिक्स इंडिया रिपोर्ट के अनुसार कारागार में होने वाली मौतों को प्राकृतिक अथवा अप्राकृतिक के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

- बढ़ती उम्र और बीमारियाँ प्राकृतिक मृत्यु का प्रमुख कारण हैं। इन बीमारियों को हृदय रोग, एच.आई.वी., तपेदिक और कैंसर जैसी अन्य बीमारियों में उप-वर्गीकृत किया गया है।
- ◆ कारागारों में कैदियों की संख्या में वृद्धि के साथ-साथ, दर्ज की गई प्राकृतिक मौतों की संख्या वर्ष 2016 में 1,424 से बढ़कर 2021 में 1,879 हो गई।
- अप्राकृतिक मौतों का उप-वर्गीकरण इस प्रकार है:
 - ◆ आत्महत्या (फाँसी लगाने, जहर देने, खुद को चोट पहुँचाने, नशीली दवाओं की अधिक मात्रा लेने, विद्युत का झटका लगने आदि के कारण)
 - ◆ सह-कैदियों के कारण
 - ◆ गोली लगने से मौत
 - ◆ लापरवाही अथवा ज्यादती के कारण मौत
 - ◆ आकस्मिक मौतें (भूकंप जैसे प्राकृतिक आपदा, सर्पदंश, डूबना, दुर्घटनावश गिरना, जलने से चोट, दवा/शराब का सेवन आदि)।
- दिये गए विकल्पों में से केवल भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा से हुई मौत को कारागार में अप्राकृतिक मृत्यु के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। अतः विकल्प B सही है।

101. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (NADA) की स्थापना भारत में डोप मुक्त खेलों के लिये सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में की गई थी।
2. NADA का प्राथमिक उद्देश्य WADA (विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी) कोड के अनुसार डोपिंग रोधी नियमों को लागू करना है।
3. WADA को खेल में डोपिंग के विरुद्ध यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन द्वारा मान्यता प्राप्त है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं ?

- A. केवल एक
- B. केवल दो
- C. सभी तीन
- D. कोई नहीं

उत्तर: C

व्याख्या:

- राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (NADA)
- ◆ राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (NADA) को भारत में डोप मुक्त खेलों के लिये एक जनादेश के साथ 24 नवंबर, 2005 को

सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में स्थापित किया गया था। अतः कथन 1 सही है।

- ◆ इसका प्राथमिक उद्देश्य विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (WADA) कोड के अनुसार डोपिंग रोधी नियमों को लागू करना, डोप नियंत्रण कार्यक्रम को विनियमित करना, शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देना तथा डोपिंग एवं इसके दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करना है। अतः कथन 2 सही है।
- ◆ NADA के पास इसके लिये आवश्यक अधिकार और जिम्मेदारी है:
 - डोपिंग रोधी गतिविधियों की योजना बनाना, उन्हें लागू करना और उनकी निगरानी करना।
 - अन्य प्रासंगिक राष्ट्रीय संगठनों, एजेंसियों और अन्य डोपिंग रोधी संगठनों आदि के साथ सहयोग करना।

● विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (WADA)

- ◆ नवंबर 1999 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के तहत विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (WADA) की स्थापना की गई थी।
- ◆ खेल में डोपिंग के खिलाफ यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (2005) द्वारा WADA को मान्यता दी गई है। अतः कथन 3 सही है।
- ◆ WADA की प्राथमिक भूमिका सभी खेलों और देशों में एंटी-डोपिंग नियमों को विकसित करना, सामंजस्य तथा समन्वय स्थापित करना है।

102. भारत में गठित निम्नलिखित में से कौन-सी समिति पुलिस सुधार से संबंधित है ?

1. पद्मनाभैया समिति (2000)
2. मल्लिमथ समिति (2000)
3. न्यायमूर्ति जे एस वर्मा समिति (2012)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- A. केवल 1 और 2
- B. केवल 2
- C. केवल 2 और 3
- D. 1, 2 और 3

उत्तर: D

व्याख्या:

- नीचे दिये गए इन्फोग्राफिक से समझा जा सकता है कि उपर्युक्त तीनों समितियाँ पुलिस सुधार से संबंधित हैं:

Police Reforms in India



CONSTITUTIONAL STATUS

- Police and Public Order: State subjects (7th Schedule)



NEED FOR REFORM

- Colonial Law
- Custodial Death
- Lack of Accountability
- Political Interference
- Poor Gender Sensitivity
- Communal/Caste Bias
- No Anti-Torture Law



RELATED DATA

- Police-People Ratio:** 153 police/100,000 people (Global benchmark: 222 police/100,000 people)
- Custodial Deaths:** 175 in 2021-2022 (as per MHA)
- Women's Share:** 10.5% of entire force (India Justice Report 2021)
- Infrastructure:** 1 in 3 police stations is equipped with CCTV (India Justice Report 2021)



IMPORTANT COMMITTEES/COMMISSION



RELATED INITIATIVES

- SMART Policing** (pan-India)
- Automated Multimodal Biometric Identification System (**AMBIS**) (Maharashtra)
- Real Time Visitor Monitoring System** (uses **AI and blockchain**) (Andhra Pradesh)
- CyberDome** (Tech R&D Centre) (Kerala)



CHALLENGES WITH POLICING

- Low Police-Population Ratio
- Political Superimposition
- Unsatisfactory Police-Public Relations
- Infra Deficit
- Corruption
- Understaffed/Overburdened

WAY FORWARD

- ↑ Police Budget, Resources
- ↑ Recruitment Process
- Implement Measures to Reduce Corruption
- ↑ Skills of Policemen
- Better Representation (Women, Minorities)



103. दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण (Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal- TDSAT) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

- यह ट्राई के किसी भी निर्देश, निर्णय अथवा आदेश के विरुद्ध अपील की सुनवाई कर सकता है किंतु सेवा प्रदाताओं और उपभोक्ताओं के बीच विवादों पर फैसला नहीं कर सकता।
- केंद्रीय संचार मंत्री TDSAT का पदेन अध्यक्ष होता है।

3. TDSAT के पास सिविल कोर्ट के समान सभी शक्तियाँ हैं किंतु सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा निर्धारित प्रक्रियाएँ इसके लिये बाध्यकारी नहीं हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं ?

- केवल एक
- केवल दो
- सभी तीन
- उपर्युक्त में से कोई भी नहीं

उत्तर: A

व्याख्या:

दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण (Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal- TDSAT):

- TRAI अधिनियम, 1997 में संशोधन: TRAI अधिनियम को वर्ष 2000 में संशोधित किया गया, जिसने TRAI के न्यायिक और विवादपूर्ण कार्यों को संभालने के लिये एक दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपीलीय न्यायाधिकरण (TDSAT) की स्थापना की।
- TDSAT की स्थापना निम्नलिखित के बीच किसी भी विवाद का निपटारा करने हेतु की गई थी:
 - ◆ एक लाइसेंस प्रदानकर्ता और एक लाइसेंसधारी।
 - ◆ दो या दो से अधिक सेवा प्रदाता।
 - ◆ एक सेवा प्रदाता और उपभोक्ताओं का समूह।
 - ◆ इसकी स्थापना TRAI के किसी भी निर्देश, निर्णय या आदेश के विरुद्ध अपील सुनने और निपटाने के लिये भी की गई थी। अतः कथन 1 सही नहीं है।
- TDSAT में एक अध्यक्ष और दो अन्य सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। अतः कथन 2 सही नहीं है।
 - ◆ इसके सदस्यों का चयन भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है।
- TDSAT की शक्तियाँ और अधिकार क्षेत्र:
 - ◆ कोई भी मामला जिसमें TDSAT को निर्णय लेने का अधिकार है, सिविल कोर्ट को उस मामले पर विचार करने का अधिकार नहीं है।
 - ◆ TDSAT द्वारा पारित आदेश सिविल कोर्ट की डिक्री (किसी सक्षम न्यायालय के निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति) के रूप में निष्पादन योग्य है, ट्रिब्यूनल के पास सिविल कोर्ट की सभी शक्तियाँ होती हैं।
 - ◆ यह सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से बंधा नहीं है बल्कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित है। अतः कथन 3 सही है।

104. संसद द्वारा पारित खान और खनिज (विकास तथा विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. यह निजी क्षेत्र द्वारा लिथियम खनन को प्रतिबंधित करता है क्योंकि लिथियम एक परमाणु खनिज के रूप में सूचीबद्ध है।
2. केंद्र सरकार के पास सोना, चांदी, ताम्र, जस्ता, सीसा, निकल जैसे महत्वपूर्ण खनिजों के लिये खनन पट्टे और मिश्रित लाइसेंस की नीलामी करने की शक्ति है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?

- केवल 1
- केवल 2
- 1 और 2 दोनों
- न तो 1 और न ही 2

उत्तर: B

व्याख्या:

संसद द्वारा पारित खान और खनिज (विकास तथा विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2023 को 17 अगस्त, 2023 को लागू किया गया।

- इस संशोधन ने लिथियम और नाइओबियम सहित छह खनिजों को परमाणु खनिजों की सूची से हटा दिया, जिससे नीलामी के माध्यम से निजी क्षेत्र को इन खनिजों के लिये रियायतें देने की अनुमति मिल गई। अतः कथन 1 सही नहीं है।
- केंद्र सरकार के पास सोना, चांदी, ताम्र, जस्ता, सीसा, निकल जैसे महत्वपूर्ण खनिजों के लिये खनन पट्टे और मिश्रित लाइसेंस की नीलामी करने की शक्ति है। अतः कथन 2 सही है।

105. पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. यह अधिनियम पशुओं से संबंधित क्रूरता, अनावश्यक कष्ट, अत्यधिक श्रम, यातना, दुर्व्यवहार की रोकथाम और सुरक्षा का प्रावधान करता है।
2. यह अधिनियम भारतीय पशु कल्याण बोर्ड और पशुओं पर प्रयोगों के नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण के लिये समिति (CCSEA) की भी स्थापना का प्रावधान करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?

- केवल 1
- केवल 2
- 1 और 2 दोनों
- न तो 1 और न ही 2

उत्तर: C

व्याख्या:

पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960

- यह भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जो पशुओं को अनावश्यक कष्ट अथवा पीड़ा पहुँचाने से रोकने का प्रावधान करता है।
 - ◆ इस अधिनियम को मूलतः वर्ष 1890 में पारित किया गया था, इसे बाद में वर्ष 1960 के अधिनियम से प्रतिस्थापित कर दिया गया।
- यह अधिनियम पशुओं से संबंधित क्रूरता, अनावश्यक कष्ट, अत्यधिक श्रम, यातना, दुर्व्यवहार की रोकथाम और सुरक्षा का प्रावधान करता है। अतः कथन 1 सही है।
 - ◆ भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना भी इस अधिनियम के तहत की गई थी।
- CCSEA पशु क्रूरता निवारण (PCA) अधिनियम, 1960 के तहत गठित पशुपालन और डेयरी विभाग (DAHD), मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय (MoFAH) की एक वैधानिक समिति है।
- मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय का गठन पशु क्रूरता निवारण (PCA) अधिनियम, 1960 के तहत किया गया। अतः कथन 2 सही है।

106. राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. DRI भारत की प्रमुख तस्करी विरोधी एजेंसी के रूप में कार्य करती है, जो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, वित्त मंत्रालय के तहत काम करती है।
 2. यह अवैध वन्यजीव व्यापार सहित तस्करी के विभिन्न रूपों का पता लगाने और उन्हें रोकने के लिये जिम्मेदार है।
- उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही नहीं है/हैं?

- A. केवल 1
- B. केवल 2
- C. 1 और 2 दोनों
- D. न तो 1 और न ही 2

उत्तर: D

व्याख्या:

- "कच्छप" नामक एक हालिया ऑपरेशन में राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने अवैध वन्यजीव व्यापार के खिलाफ चल रही लड़ाई और इन अद्वितीय प्राणियों की सुरक्षा पर प्रकाश डालते हुए लगभग एक हजार जीवित शिशु कछुओं को सफलतापूर्वक बचाया है।

- DRI भारत की प्रमुख तस्करी विरोधी एजेंसी के रूप में कार्य करती है, जो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, वित्त मंत्रालय के तहत कार्य करती है। अतः कथन 1 सही है।
- यह अवैध वन्यजीव व्यापार सहित तस्करी के विभिन्न रूपों का पता लगाने और उन्हें रोकने के लिये जिम्मेदार है। अतः कथन 2 सही है।

107. "उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के कार्यान्वयन" पर रिपोर्ट के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. रिपोर्ट में इस बात पर बल दिया गया है कि भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली का एक बड़ा हिस्सा केंद्रीय अधिनियमों के तहत संचालित होता है।
2. 94% छात्र केंद्रीय संस्थानों में नामांकित हैं, राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों में केवल 6% छात्र बचे हैं।
3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति का लक्ष्य वर्ष 2035 तक उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 50% तक बढ़ाना है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं ?

- A. केवल एक
- B. केवल दो
- C. सभी तीन
- D. इनमें से कोई भी नहीं

उत्तर: A

व्याख्या:

संसद के एक विशेष सत्र में शिक्षा पर संसद की स्थायी समिति ने "उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन" को लेकर एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत की।

- रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली का एक बड़ा भाग राज्य अधिनियमों के तहत संचालित होता है, जिसमें 70% विश्वविद्यालय इस श्रेणी में आते हैं। अतः कथन 1 सही नहीं है।
- इसके अतिरिक्त, 94% छात्र राज्य या निजी संस्थानों में नामांकित हैं, केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों में नामांकित छात्रों का अनुपात मात्र 6% है। अतः कथन 2 सही नहीं है।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 भारत की उभरती विकास आवश्यकताओं से निपटने का एक प्रयास है। इसका लक्ष्य वर्ष 2035 तक उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 26.3% से बढ़ाकर 50% करना है, जिसमें 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ना शामिल हैं। अतः कथन 3 सही है।

108. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) अधिनियम, 1985 "कैनबिस पौधे" के किसी भी हिस्से- फूल, रेसिन, बीज या पत्तियों की खपत को पूरी तरह से अवैध बनाता है।
2. हिमाचल प्रदेश कैनबिस की खेती को वैध बनाने वाला भारत का एकमात्र राज्य है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?

- A. केवल 1
- B. केवल 2
- C. 1 और 2 दोनों
- D. न तो 1 और न ही 2

उत्तर: D

व्याख्या:

- हिमाचल प्रदेश सरकार कैनबिस की खेती पर प्रतिबंध हटाने की किसानों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को देखते हुए इसकी (गाँजा) खेती को वैध बनाने की संभावना पर विचार कर रही है।
- नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) अधिनियम, 1985 राज्यों को धारा 10 (a) (iii) के तहत फाइबर, बीज या बागवानी उद्देश्यों के लिये कैनबिस की खेती के संबंध में नियम बनाने की अनुमति देता है।
 - ◆ हिमाचल प्रदेश का पड़ोसी राज्य उत्तराखंड वर्ष 2017 में कैनबिस की खेती को वैध बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। अतः कथन 2 सही नहीं है।
- NDPS अधिनियम के अनुसार, "कैनबिस प्लांट" को कैनबिस जीनस (Genus) के किसी पौधे के रूप में परिभाषित किया गया है।
 - ◆ 'चरस' कैनबिस के पौधे से निकाला गया या अलग किया हुआ रेसिन है। NDPS अधिनियम इसमें कैनबिस के पौधे से किसी भी रूप में प्राप्त कच्चा माल या शुद्ध, पृथक रेसिन को शामिल करता है, इसमें कैनबिस के तेल या तरल हैश के रूप में केंद्रित सामग्री एवं राल भी शामिल है।
 - अधिनियम 'गाँजा' को कैनबिस के पौधे के फूल या फलने वाले शीर्ष के रूप में परिभाषित करता है लेकिन इसमें बीज और पत्तियों को स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया है।
 - यह अधिनियम कैनबिस, चरस और गाँजे के दो रूपों में से किसी भी तटस्थ सामग्री के साथ या उसके बिना या उससे तैयार किसी भी पेय के मिश्रण को अवैध बनाता है।

- ◆ विधायिका ने कैनबिस के पौधे के बीज और पत्तियों को अधिनियम के दायरे से बाहर कर दिया, क्योंकि पौधे की दाँतेदार पत्तियों में THC की मात्रा नगण्य होती है। अतः कथन 1 सही नहीं है।

109. केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. यह औषधियों के आयात पर विनियामक नियंत्रण रखने के लिये जिम्मेदार है।
2. ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के तहत इसे घटिया दवाओं के पूरे बैच को वापस लेने का अधिकार है।
3. CDSCO मुख्यालय केंद्रीय लाइसेंस अनुमोदन प्राधिकरण के रूप में कुछ लाइसेंसों को भी मंजूरी देता है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं ?

- A. केवल एक
- B. केवल दो
- C. सभी तीन
- D. कोई भी नहीं

उत्तर: B

व्याख्या:

- केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (Central Drugs Standard Control Organization-CDSCO) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के तहत केंद्र सरकार को सौंपे गए कार्यों के निर्वहन के लिये केंद्रीय औषधि प्राधिकरण है।
- CDSCO के प्रमुख कार्य:
 - ◆ औषधियों के आयात पर विनियामक नियंत्रण। अतः कथन 1 सही है।
 - ◆ नई दवाओं और क्लिनिकल परीक्षणों को मंजूरी।
 - ◆ औषधि सलाहकार समिति (DCC) और औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड (DTAB) की बैठकें करना।
 - ◆ केंद्रीय लाइसेंस अनुमोदन प्राधिकारी के रूप में कुछ लाइसेंसों को मंजूरी देने का कार्य CDSCO मुख्यालय द्वारा किया जाता है। अतः कथन 3 सही है।
 - DCGI भारत में रक्त और रक्त उत्पाद, IV तरल पदार्थ, टीके और सीरा जैसी दवाओं की निर्दिष्ट श्रेणियों के लाइसेंस की स्वीकृति देने के लिये जिम्मेदार है।
- डाइजीन जेल को स्वाद और गंध के संबंध में ग्राहकों की अलग-अलग शिकायतों के कारण स्वेच्छा से वापस लिया जा रहा है।

- ड्रग रिकॉल एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक फार्मास्यूटिकल कंपनी या नियामक प्राधिकरण सुरक्षा चिंताओं, दोषों या अन्य मुद्दों के कारण बाज़ार से उस विशिष्ट दवा को हटा देता है जो रोगियों या उपभोक्ताओं को हानि पहुँचा सकती है।
- ◆ वर्तमान में भारत के पास ऐसा कोई कानून नहीं है जो घटिया दवाओं के पूरे बैच को वापस लेने का अधिकार देता हो। अतः कथन 2 सही नहीं है।

110. 'गैर-वापसी के सिद्धांत' के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. गैर-वापसी का सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि किसी को भी ऐसे देश में वापस नहीं भेजा जाना चाहिये जहाँ उन्हें यातना, क्रूर, अमानवीय, या अपमानजनक स्थिति या अन्य अपूरणीय क्षति का सामना करना पड़ेगा।
2. भारत 1951 के शरणार्थी अभिसमय और इसके 1967 प्रोटोकॉल का सदस्य नहीं है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- A. केवल 1
- B. केवल 2
- C. 1 और 2 दोनों
- D. न तो 1 और न ही 2

उत्तर: C

व्याख्या:

- गैर-वापसी का सिद्धांत (1951 शरणार्थी अभिसमय एवं इसका 1967 प्रोटोकॉल) अंतर्राष्ट्रीय कानून और विशेष रूप से शरणार्थी कानून के संदर्भ में एक सुस्थापित अवधारणा है।
- अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के तहत, गैर-वापसी का सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि किसी को भी ऐसे देश में वापस नहीं भेजा जाना चाहिये जहाँ उन्हें यातना, क्रूर, अमानवीय, या अपमानजनक स्थिति या सज़ा और अन्य अपूरणीय क्षति का सामना करना पड़ेगा। अतः कथन 1 सही है।
- भारत 1951 शरणार्थी कन्वेंशन और उसके 1967 प्रोटोकॉल का एक सदस्य नहीं है, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत शरणार्थी संरक्षण से संबंधित प्रमुख कानूनी दस्तावेज़ हैं। अतः कथन 2 सही है।

111. डीम्ड विश्वविद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. इसे संसद अथवा राज्य विधानमंडल के एक अधिनियम द्वारा स्थापित या निगमित किया जाता है।
2. एक डीम्ड विश्वविद्यालय को अकादमिक स्वायत्तता प्राप्त होती है, लेकिन वह अपने स्वयं के पाठ्यक्रम, प्रवेश मानदंड, संकाय भर्ती तथा परीक्षा प्रणाली अभिकल्पित नहीं कर सकता है।

3. NCERT को 'डे नोवो' श्रेणी के तहत डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं ?

- A. केवल एक
- B. केवल दो
- C. सभी तीन
- D. कोई भी नहीं

उत्तर: A

व्याख्या:

- राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद को डीम्ड-टू-बी-यूनिवर्सिटी का दर्जा:
 - ◆ डीम्ड यूनिवर्सिटी उच्च शिक्षा हेतु एक संस्थान है जिसे UGC अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है।
 - यह संसद या राज्य विधानमंडल के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित या निगमित नहीं है, बल्कि UGC की सिफारिश पर केंद्र सरकार द्वारा इसे विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया है। अतः कथन 1 सही नहीं है।
 - ◆ एक डीम्ड यूनिवर्सिटी को शैक्षणिक स्वायत्तता प्राप्त है तथा वह अपने स्वयं के पाठ्यक्रम, प्रवेश मानदंड, शुल्क संरचना, संकाय भर्ती तथा परीक्षा प्रणाली डिजाइन कर सकती है। अतः कथन 2 सही नहीं है।
 - डे-नोवो श्रेणी:
 - ◆ NCERT को 'डे-नोवो' श्रेणी के तहत डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है, जिसका अर्थ है कि इसे ज्ञान के नए या उभरते क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिये मान्यता दी गई है। अतः कथन 3 सही है।
 - डे-नोवो इंस्टीट्यूशन अद्वितीय और "ज्ञान के उभरते क्षेत्रों" (Emerging Areas of Knowledge) जैसे- जैव प्रौद्योगिकी, नैनो टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष विज्ञान इत्यादि में शिक्षण एवं अनुसंधान में नवाचारों के लिये समर्पित एक संस्थान है।
112. 'इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशन फॉर लीगल मेट्रोलाजी (OIML)' के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
- i. इसका मुख्यालय बीजिंग, चीन में स्थित है।
 - ii. भारत ने न तो सदस्यता स्वीकार की है और न ही मेट्रोलाजी से संबंधित मीट्रिक कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किये हैं।

iii. OIML-CS, OIML प्रमाणपत्र जारी करने, पंजीकरण करने और जारी करने की एक प्रणाली है।

iv. भारत OIML प्रमाणपत्र जारी करने वाले देशों में से एक है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?

- A. केवल i और ii
- B. केवल ii और iii
- C. केवल i, ii और iii
- D. केवल iii और iv

उत्तर: D:

व्याख्या:

- OIML की स्थापना वर्ष 1955 में हुई थी और इसका मुख्यालय पेरिस में है। अतः कथन (i) सही नहीं है।
- यह एक अंतर्राष्ट्रीय मानक-निर्धारण निकाय है जो कानूनी मेट्रोलाजी अधिकारियों और उद्योग द्वारा उपयोग के लिये मॉडल नियमों, मानकों तथा संबंधित दस्तावेजों को विकसित करता है।
- भारत वर्ष 1956 में OIML का सदस्य बना। उसी वर्ष भारत ने मीटर अभिसमय पर हस्ताक्षर किये। अतः कथन (ii) सही नहीं है।
- OIML-CS डिजिटल बैलेंस, क्लिनिकल थर्मामीटर इत्यादि जैसे उपकरणों के लिये OIML प्रमाणपत्र और उनके संबंधित OIML प्रकार के मूल्यांकन/परीक्षण रिपोर्ट जारी करने, पंजीकृत एवं उपयोग करने की एक प्रणाली है। अतः कथन (iii) सही है।
- वे देश जो OIML प्रमाणपत्र जारी कर सकते हैं: ऑस्ट्रेलिया, स्विट्ज़रलैंड, चीन, चेक गणराज्य, जर्मनी, डेनमार्क, फ्रांस, यूके, जापान, नीदरलैंड, स्वीडन और स्लोवाकिया (और अब भारत भी)। अतः कथन (iv) सही है।

113. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. व्यक्तिगत अनुकूली शिक्षण (PAL) छात्रों को उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं और क्षमताओं के अनुरूप व्यक्तिगत शिक्षण अनुभव प्रदान करने के लिये AI का उपयोग करता है।
2. डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग (DIKSHA) एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो स्कूलों के लिये शैक्षिक सामग्री के भंडार के रूप में कार्य करता है, जिसकी देख-रेख शिक्षा मंत्रालय करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?

- A. केवल 1
- B. केवल 2
- C. 1 और 2 दोनों
- D. न तो 1 और न ही 2

उत्तर: C

व्याख्या:

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Electronics and Information Technology- MeitY) की एक शाखा, नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीज़न (National eGovernance Division- NeGD), पर्सनलाइज़्ड एडेप्टिव लर्निंग (Personalised Adaptive Learning- PAL) को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग (Digital Infrastructure for Knowledge Sharing- DIKSHA) प्लेटफॉर्म में एकीकृत करने के मिशन पर काम कर रही है।

- शिक्षा मंत्रालय की देख-रेख में दीक्षा, स्कूलों के लिये शैक्षिक सामग्री के एक ऑनलाइन भंडार के रूप में कार्य करती है, लेकिन यह वर्तमान में स्थिर है। अतः कथन 2 सही है।
- ◆ दूसरी ओर, PAL छात्रों को उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं तथा क्षमताओं के अनुरूप व्यक्तिगत सीखने के अनुभव प्रदान करने के लिये AI का उपयोग करता है। अतः कथन 1 सही है।

114. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. UIDAI इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र के तहत स्थापित एक वैधानिक प्राधिकरण है।
2. आधार संख्या, UIDAI द्वारा जारी 12 अंकों की व्यक्तिगत पहचान संख्या है जो भारत में कहीं भी पहचान और पते के प्रमाण के रूप में कार्य करती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?

- A. केवल 1
- B. केवल 2
- C. 1 और 2 दोनों
- D. न तो 1 और न ही 2

उत्तर: C

व्याख्या:

● मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने इन-हाउस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग प्रौद्योगिकियों का उपयोग कर "आधार प्रमाणीकरण की पुनर्कल्पना" विषय को मूर्त रूप देने हुए अपने उन्नत फेस ऑर्थेंटिकेशन फीचर का अनावरण किया।

- ◆ स्वयंसेवी दिशा-निर्देश 2022 पहल के तहत UIDAI ने प्रौद्योगिकी अपनाने में तेज़ी लाने और निवासियों के लिये नवीन समाधान विकसित करने हेतु उद्योग तथा फिनटेक भागीदारों के साथ सहयोग को बढ़ावा दिया है।

- ◆ एयरटेल पेमेंट्स बैंक के साथ सहयोगात्मक प्रयासों ने फेस ऑथेंटिकेशन को बढ़ाया है, कम रोशनी की स्थिति को अनुकूलित कर धोखाधड़ी की रोकथाम के उपायों को मज़बूत किया है।
- UIDAI (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) आधार अधिनियम 2016 के प्रावधानों का पालन करते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र के तहत भारत सरकार द्वारा 12 जुलाई 2016 को स्थापित एक वैधानिक प्राधिकरण है। अतः कथन 1 सही है।
- 2. आधार संख्या, UIDAI द्वारा जारी 12 अंकों की व्यक्तिगत पहचान संख्या है जो भारत में कहीं भी पहचान और पते के प्रमाण के रूप में कार्य करती है। अतः कथन 2 सही है।

115. रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. इस अधिनियम के तहत 1000 वर्ग मीटर अथवा आठ अपार्टमेंट के न्यूनतम प्लॉट आकार वाली सभी रियल एस्टेट परियोजनाओं को लॉन्च से पहले RERA के साथ पंजीकृत होना अनिवार्य है।
2. प्रमोटरों को विशिष्ट परियोजना के निर्माण और भूमि लागत के लिये एकत्रित धन का 70% एक अलग एस्करो खाते में जमा करना आवश्यक है।
3. अपीलीय न्यायाधिकरणों को 90 दिनों के भीतर मामलों का निपटारा करना अनिवार्य है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं ?

- A. केवल एक
- B. केवल दो
- C. सभी तीन
- D. कोई नहीं

उत्तर: A

व्याख्या:

रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016:

- रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (RERA):
 - ◆ अधिनियम प्रत्येक राज्य में RERA की स्थापना का प्रावधान करता है, जो नियामक निकायों और विवाद समाधान मंचों के रूप में कार्य करता है।
- अनिवार्य पंजीकरण:
 - ◆ न्यूनतम 500 वर्ग मीटर के प्लॉट या आठ अपार्टमेंट वाली सभी रियल एस्टेट परियोजनाओं को लॉन्च करने से पहले RERA के साथ पंजीकृत होना चाहिये। इसका उद्देश्य परियोजना विपणन और निष्पादन में पारदर्शिता बढ़ाना है। अतः कथन 1 सही नहीं है।

● पारदर्शिता और डेटाबेस:

- ◆ RERA अपनी वेबसाइट्स पर पंजीकृत परियोजनाओं का एक सार्वजनिक डेटाबेस बनाए रखता है। इसमें परियोजना विवरण, पंजीकरण स्थिति और चल रही प्रगति, खरीदारों हेतु पारदर्शिता प्रदान करना शामिल है।

● निधि प्रबंधन:

- ◆ फंड डायवर्जन को रोकने हेतु प्रमोटरों को विशिष्ट परियोजना के निर्माण और भूमि लागत के लिये एकत्रित धन का 70% एक अलग एस्करो खाते में जमा करना आवश्यक है। अतः कथन 2 सही है।

● समयबद्ध निर्णय:

- ◆ अपीलीय न्यायाधिकरणों को 60 दिनों के भीतर मामलों का निपटारा करने का आदेश दिया गया है, जबकि नियामक अधिकारियों को उसी समय सीमा में शिकायतों का समाधान करना चाहिये, ताकि विवाद का तेज़ी से समाधान सुनिश्चित हो सके। अतः कथन 3 सही नहीं है।

116. सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. इसने सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 को प्रतिस्थापित किया।
2. यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) से लिया गया है, जो वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है।
3. यह प्रावधान करता है कि यदि सूचना किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है तो उसे 24 घंटे के भीतर प्रदान किया जाना चाहिये।
4. यह सार्वजनिक हित के मामले में आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1923 को खत्म करने का प्रावधान करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं ?

- A. केवल 1 और 2
- B. केवल 1, 2 और 4
- C. केवल 2, 3 और 4
- D. उपरोक्त सभी

उत्तर: B

व्याख्या:

सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम

● परिचय:

- ◆ सूचना का अधिकार अधिनियम एक विधायी ढाँचा है जो भारतीय नागरिकों को सार्वजनिक अधिकारियों के पास उपलब्ध जानकारी को प्राप्त करने का अधिकार प्रदान

करता है। वर्ष 2005 में अधिनियमित इस अधिनियम का उद्देश्य सरकारी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही और भागीदारी को बढ़ावा देना है।

■ इसने सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 को प्रतिस्थापित किया है। अतः कथन 1 सही है।

◆ RTI अधिनियम की धारा 22 के अनुसार, इस अधिनियम के प्रावधान वर्ष 1923 के आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, मौजूदा कानूनों अथवा इस अधिनियम के अलावा अन्य कानूनों के माध्यम से स्थापित किसी भी समझौते के साथ किसी भी विरोधाभास के बावजूद प्रभावी होंगे। अतः कथन 4 सही है।

● संवैधानिक समर्थन:

◆ RTI अधिनियम भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1) (a) से लिया गया है, यह भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है।

■ राज नारायण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि सूचना का अधिकार अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार माना जाएगा।

● समय-सीमा:

◆ सामान्य तौर पर किसी आवेदक को सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर सूचना प्रदान की जानी होती है।

◆ यदि मांगी गई जानकारी किसी व्यक्ति के जीवन अथवा स्वतंत्रता से संबंधित है, तो उससे संबंधित जानकारी आवेदक को 48 घंटों के भीतर प्रदान किये जाने का प्रावधान है। अतः कथन 3 सही नहीं है।

■ यदि आवेदन सहायक लोक सूचना अधिकारी के माध्यम से भेजा गया है या यह किसी गलत लोक प्राधिकारी को भेजा गया है, तो तीस दिन या 48 घंटे की अवधि में मामले के अनुरूप उसकी कार्यवाही में अतिरिक्त पाँच दिन जोड़ दिये जाएंगे।

117. राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. NJDG 18,735 ज़िला तथा अधीनस्थ न्यायालयों और उच्च न्यायालयों के आदेशों, निर्णयों एवं मामलों के विवरण का एक डेटाबेस है जिसे ई-न्यायालय प्रोजेक्ट के तहत एक ऑनलाइन मंच के रूप में स्थापित किया गया है।
2. डेटा को कनेक्टेड ज़िला और तालुका न्यायालयों द्वारा लगभग वास्तविक समय के आधार पर अपडेट किया जाता है।

3. सभी उच्च न्यायालय भी वेब सेवाओं के माध्यम से NJDG में शामिल हो गए हैं, जिससे सार्वजनिक प्रतिवादियों को आसान पहुँच की सुविधा मिल रही है।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही नहीं है/हैं ?

- A. केवल 1
- B. केवल 2
- C. केवल 3
- D. उपरोक्त सभी

उत्तर: b

व्याख्या:

● NJDG 18,735 ज़िला तथा अधीनस्थ न्यायालयों और उच्च न्यायालयों के आदेशों, निर्णयों एवं मामलों के विवरण का एक डेटाबेस है जिसे ई-न्यायालय प्रोजेक्ट के तहत एक ऑनलाइन मंच के रूप में स्थापित किया गया है।

◆ अतः कथन 1 सही है।

● डेटा को कनेक्टेड ज़िला और तालुका न्यायालयों द्वारा लगभग वास्तविक समय के आधार पर अपडेट किया जाता है। यह देश के सभी कंप्यूटरीकृत ज़िला और अधीनस्थ न्यायालयों की न्यायिक कार्यवाही/निर्णयों से संबंधित डेटा प्रदान करता है।

◆ अतः कथन 2 सही नहीं है।

● सभी उच्च न्यायालय भी वेब सेवाओं के माध्यम से NJDG में शामिल हो गए हैं, जिससे सार्वजनिक प्रतिवादियों को आसान पहुँच की सुविधा मिल रही है।

◆ अतः कथन 3 सही है।

● इलास्टिक सर्च तकनीक का उपयोग करते हुए ई-कोर्ट सेवा मंच के माध्यम से, वर्तमान में 23.58 करोड़ से अधिक मामलों और इन कंप्यूटरीकृत न्यायालयों से संबंधित 22.56 करोड़ से अधिक आदेशों/निर्णयों के संबंध में मामले की स्थिति की जानकारी तक पहुँच सकते हैं। NJDG पर नागरिक और आपराधिक दोनों मामलों के केस डेटा उपलब्ध है, जिसमें मामले की उम्र के साथ-साथ राज्य तथा ज़िले के आधार पर ड्रिल-डाउन विश्लेषण करने की क्षमता है।

118. जल जीवन मिशन (ग्रामीण) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. इसका लक्ष्य 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति दिन 55 लीटर पानी उपलब्ध कराना है।
2. इस मिशन के तहत हर घर जल की स्थिति प्रस्तावित तिथि सीमा से पहले सभी भारतीय राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा हासिल कर लिया गया है।

3. यह मिशन ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं ?

- A. केवल एक
- B. केवल दो
- C. सभी तीन
- D. कोई भी नहीं

उत्तर : D

व्याख्या:

जल जीवन मिशन (ग्रामीण): इस मिशन का लक्ष्य वर्ष 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (Functional Household Tap Connections FHTC) के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण व्यक्ति (न कि परिवार) को 55 लीटर पानी उपलब्ध कराना है।
अतः कथन 1 सही नहीं है।

- यह जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अतः कथन 3 सही नहीं है।
- वर्तमान स्थिति:
 - ◆ 3 जनवरी, 2023 तक नल के पानी के कनेक्शन तक पहुँच रखने वाले ग्रामीण परिवारों की संख्या बढ़कर 108.7 मिलियन हो गई, जो 56.14% के बराबर है।
 - ◆ नतीजतन, मिशन को आगामी दो वर्षों के भीतर अतिरिक्त 76.3 मिलियन ग्रामीण परिवारों (47.3%) तक कवरेज को बढ़ाना पड़ सकता है।
- जैसा कि कार्यक्रम के डैशबोर्ड द्वारा बताया गया है कि अब तक हर घर जल मिशन की स्थिति, जिसमें सभी ग्रामीण घरों में नल के पानी की आपूर्ति का प्रावधान शामिल है, 9 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों तक पहुँच गया है जो कि हरियाणा, गोवा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पुदुचेरी, दमन और दीव तथा दादर नागर हवेली, तेलंगाना, गुजरात, पंजाब और हिमाचल प्रदेश हैं। अतः कथन 2 सही नहीं है।

119. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिये:

जमानत के प्रकार शर्तें

1. नियमित जमानत न्यायालय द्वारा ऐसे व्यक्ति को रिहा करने का आदेश जो पहले से ही गिरफ्तार है और पुलिस हिरासत में रखा गया हो।
2. अग्रिम जमानत यह तब दिया जाता है जब पुलिस अथवा जाँच एजेंसी एक निश्चित समय सीमा के भीतर अपनी रिपोर्ट/शिकायत दर्ज करने में विफल रहती है।
3. वैधानिक जमानत नियमित अथवा अग्रिम जमानत हेतु आवेदन न्यायालय के समक्ष लंबित होने की स्थिति में यह जमानत न्यायालय द्वारा अस्थायी और अल्प अवधि हेतु दी जाती है।

उपर्युक्त युग्मों में से कौन-सा/से सही सुमेलित है/हैं ?

- A. केवल 1
- B. केवल 1 और 2
- C. केवल 2
- D. 1, 2 और 3

उत्तर: A

व्याख्या:

- जमानत कानूनी हिरासत के तहत रखे गए (उन मामलों में जिन पर न्यायालय द्वारा अभी फैसला सुनाया जाना है) व्यक्ति की सशर्त/अनंतिम रिहाई है, जो आवश्यकता पड़ने पर न्यायालय में उपस्थित होने का वादा करता है।
- भारत में जमानत के प्रकार:
 - ◆ नियमित जमानत: यह न्यायालय (देश के भीतर किसी भी न्यायालय) द्वारा दिया गया एक निर्देश है जो पहले से ही गिरफ्तार और पुलिस हिरासत में रखे गए व्यक्ति को रिहा करने हेतु उपलब्ध है। ऐसी जमानत के लिये व्यक्ति CrPC, 1973 की धारा 437 तथा 439 के तहत आवेदन दाखिल कर सकता है। अतः युग्म 1 सही सुमेलित है।
 - ◆ अंतरिम जमानत: नियमित अथवा अग्रिम जमानत हेतु आवेदन न्यायालय के समक्ष लंबित होने की स्थिति में यह जमानत न्यायालय द्वारा अस्थायी और अल्प अवधि हेतु दी जाती है।
 - ◆ अग्रिम जमानत या पूर्व-गिरफ्तारी जमानत: यह एक कानूनी प्रावधान है जो आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार होने से पहले जमानत हेतु आवेदन करने की अनुमति देता है। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 438 में भारत में पूर्व-गिरफ्तारी जमानत का प्रावधान किया गया है। इसे केवल सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा दिया जाता है। अतः युग्म 2 सही सुमेलित नहीं है।
 - अग्रिम जमानत का प्रावधान विवेकाधीन है तथा न्यायालय अपराध की प्रकृति और गंभीरता, आरोपी के पूर्ववृत्त एवं अन्य प्रासंगिक कारकों पर विचार करने के बाद जमानत दे सकता है।
 - न्यायालय जमानत देते समय कुछ शर्तें भी लगा सकता है, जिसमें पासपोर्ट जप्त करना, देश छोड़ने पर प्रतिबंध या पुलिस स्टेशन में नियमित रूप से रिपोर्ट करना आदि शामिल हैं।
 - ◆ वैधानिक जमानत: वैधानिक जमानत, जिसे डिफ्रॉल्ट जमानत के रूप में भी जाना जाता है, CrPC की धारा 437, 438 और 439 के तहत सामान्य प्रक्रिया से प्राप्त जमानत से अलग है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, वैधानिक जमानत तब दी जाती है जब पुलिस अथवा जाँच एजेंसी निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर अपनी रिपोर्ट/शिकायत दर्ज करने विफल हो जाती है। अतः युग्म 3 सही सुमेलित नहीं है।

120. इंटरपोल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. इसकी स्थापना वर्ष 1923 में की गई थी और भारत इसके संस्थापक सदस्यों में से एक है।
2. इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है।
3. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) इंटरपोल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क के दस सदस्यों में से एक है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं ?

- A. केवल एक
- B. केवल दो
- C. सभी तीन
- D. उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर: A

- इंटरपोल की स्थापना वर्ष 1923 में हुई थी और भारत वर्ष 1956 में इसमें शामिल हुआ। अतः कथन 1 सही नहीं है।
- इंटरपोल का मुख्यालय लियॉन, फ्रांस में है। अतः कथन 2 सही नहीं है।
- केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) एकेडमी, अपराध जाँच और कानून प्रवर्तन प्रशिक्षण हेतु इंटरपोल ग्लोबल एकेडमी नेटवर्क में 10वें सदस्य के रूप में शामिल हुई। यह महत्वपूर्ण कदम एकेडमी के वैश्विक प्रभाव को बढ़ाता है, साथ ही प्रभावशाली संयुक्त पहल एवं क्षमता निर्माण का मार्ग भी प्रशस्त करता है। अतः कथन 3 सही नहीं है।



इंटरपोल

परिचय

- ◆ **आधिकारिक नाम:** अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन (International Criminal Police Organization-ICPO: INTERPOL)
- ◆ **स्थापना:** वर्ष 1923
- ◆ **सदस्य राज्य:** 195
 - ➔ भारत वर्ष 1956 से इसका सदस्य है।
- ◆ **मुख्यालय:** लियॉन, फ्रांस
- ◆ यह एक **अंतर-सरकारी संगठन** है।

उद्देश्य

- ◆ यह विभिन्न पुलिस बलों से प्राप्त सूचनाओं के संग्रह और प्रसार के माध्यम से दुनिया भर में पुलिस बलों की आपराधिक जाँच की सुविधा प्रदान करता है।
- ➔ इसके पास गिरफ्तारी जैसी कानून प्रवर्तन शक्तियाँ नहीं हैं।

संरचना

- ◆ **अध्यक्ष** (इंटरपोल का प्रमुख) - 4 वर्ष के लिये चुना जाता है।
- ◆ **महासचिव** (दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों की देखरेख करता है) - 5 वर्ष के लिये चुना जाता है।
- ◆ **विशेष निदेशालय** - साइबर अपराध, आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी, वित्तीय अपराध, पर्यावरण अपराध, मानव तस्करी आदि जैसे विशिष्ट मुद्दों से संबंधित है।
- ◆ **महासभा:** सर्वोच्च शासी निकाय (वर्ष में एक बार बैठक)।
 - ➔ भारत ने वर्ष 2022 में इंटरपोल महासभा की मेजबानी की।


इंटरपोल के नोटिस

- ◆ इंटरपोल द्वारा जारी किया जाने वाला नोटिस सदस्य देशों में पुलिस को अपराध से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने में सहयोग या अलर्ट (Alert) के लिये अंतर्राष्ट्रीय अनुरोध होता है।

इंटरपोल नेशनल सेंट्रल ब्यूरो (NCB)

- ◆ NCB, इंटरपोल के लिये नामित संपर्क बिंदु होते हैं।
- ◆ भारत का इंटरपोल NCB - **केंद्रीय अन्वेषण जाँच ब्यूरो (CBI)**

इंटरपोल नोटिस

 लाल वांछित अपराधी	 हरा घेतावनी
 पीला लापता व्यक्ति	 नाटंगी बम की सूचना
 नीला अतिरिक्त जानकारी	 बैंगनी अपराधी का तरीका
 काला अज्ञात लाल/शिलास्त	

121. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. यह एक गैर-वैधानिक निकाय है।
2. इसका मुख्य कार्य दूरसंचार सेवाओं को विनियमित करना है, जिसमें दूरसंचार सेवाओं के लिये टैरिफ का निर्धारण/संशोधन भी शामिल है।
3. TRAI की सिफारिशें केंद्र सरकार के लिये बाध्यकारी होती हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?

- A. केवल 2
- B. केवल 3
- C. केवल 2 और 3
- D. केवल 1 और 3

उत्तर: A

व्याख्या:

- भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (Telecom Regulatory Authority of India- TRAI) की स्थापना 20 फरवरी, 1997 को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 द्वारा की गई थी।

◆ अतः कथन 1 सही नहीं है।

- TRAI की संरचना:

◆ TRAI में एक अध्यक्ष, दो पूर्णकालिक सदस्य और दो अंशकालिक सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है।

- TRAI के कार्य:

◆ दूरसंचार सेवाओं को विनियमित करना, जिसमें दूरसंचार सेवाओं के लिए टैरिफ का निर्धारण/संशोधन शामिल है, जो पहले केंद्र सरकार में निहित थे।

◆ सेवा की गुणवत्ता और टैरिफ में पारदर्शिता सुनिश्चित करना।

◆ नीतिगत मामलों और लाइसेंसिंग मुद्दों पर सरकार को सलाह देना

◆ अतः कथन 2 सही है।

- TRAI की सिफारिशें केंद्र सरकार के लिये बाध्यकारी नहीं हैं।

◆ अतः कथन 3 सही नहीं है।

122. भारत में विभिन्न प्रकार की जमानत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. अग्रिम जमानत या गिरफ्तारी-पूर्व जमानत केवल उच्च न्यायालय द्वारा दी जाती है।
2. वैधानिक जमानत तब दी जाती है जब पुलिस या जाँच एजेंसी एक निश्चित समय-सीमा के भीतर रिपोर्ट/शिकायत दर्ज करने में विफल रहती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं ?

- A. केवल 1
- B. केवल 2
- C. 1 और 2 दोनों
- D. न तो 1 और न ही 2

उत्तर: B

व्याख्या:

- भारत में जमानत के प्रकार:

◆ नियमित जमानत: यह न्यायालय (देश के भीतर किसी भी न्यायालय) द्वारा उस व्यक्ति को रिहा करने का निर्देश है जो पहले से ही गिरफ्तार है और पुलिस हिरासत में रखा गया है। ऐसी जमानत के लिये कोई व्यक्ति आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC), 1973 की धारा 437 और 439 के तहत आवेदन दायर कर सकता है।

◆ अंतरिम जमानत: अग्रिम जमानत या नियमित जमानत की मांग वाले आवेदन के न्यायालय के समक्ष लंबित होने तक न्यायालय द्वारा अस्थायी और छोटी अवधि के लिये जमानत दी जाती है।

◆ अग्रिम जमानत या गिरफ्तारी से पहले जमानत: यह एक कानूनी प्रावधान है जो किसी आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार होने से पहले जमानत के लिये आवेदन करने की अनुमति देता है। भारत में CrPC 1973 की धारा 438 के तहत गिरफ्तारी से पहले जमानत केवल सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा दी जाती है। अतः कथन 1 सही नहीं है।

■ गिरफ्तारी पूर्व जमानत का प्रावधान विवेकाधीन है और न्यायालय अपराध की प्रकृति तथा गंभीरता, आरोपी के पूर्ववृत्त एवं अन्य प्रासंगिक कारकों पर विचार करने के बाद जमानत दे सकता है।

■ जमानत देते समय न्यायालय कुछ शर्तें भी लगा सकता है, जैसे पासपोर्ट सरेंडर करना, देश छोड़ने से बचना या नियमित रूप से पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करना।

◆ वैधानिक जमानत: वैधानिक जमानत, जिसे डिफॉल्ट जमानत के रूप में भी जाना जाता है, CrPC की धारा 437, 438 और 439 के तहत सामान्य प्रक्रिया में प्राप्त जमानत से अलग है। जैसा कि नाम से पता चलता है, वैधानिक जमानत तब दी जाती है जब पुलिस या जाँच एजेंसी एक निश्चित समय-सीमा के भीतर रिपोर्ट/शिकायत दर्ज करने में विफल हो जाती है। अतः कथन 2 सही है।

123. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

- हत्या के साथ डकैती का अपराध भारतीय दंड संहिता (IPC) के अंतर्गत कुछ निश्चित अपराधों में से एक है जिसके लिये अपराधियों को मृत्युदंड दिया जा सकता है।
- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 भारत के राष्ट्रपति को क्षमा आदि देने और कुछ मामलों में सजा को निलंबित करने, माफ करने या कम करने का अधिकार देता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?

- केवल 1
- केवल 2
- 1 और 2 दोनों
- न तो 1 और न ही 2

उत्तर: C

व्याख्या:

- मृत्युदंड का अर्थ, दंड का सबसे गंभीर रूप है। यह वह दंड है जो मानवता के खिलाफ सबसे जघन्य एवं गंभीर अपराधों के लिये है।
- ◆ भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कुछ अपराध, जिनके लिये अपराधियों को मृत्युदंड दिया जा सकता है:
 - हत्या (धारा 302)
 - हत्या के साथ डकैती (धारा 396)
 - आपराधिक षडयंत्र (धारा 120 B)
 - भारत सरकार के वरिष्ठ युद्ध छेड़ना या ऐसा करने का प्रयास करना (धारा 121)
 - सेना के किसी भी अंग में सैनिक वद्रोह (धारा 132) एवं अन्य।
- ◆ अतः कथन 1 सही है।
- मृत्युदंड शब्द का उपयोग फ्राँसी के संदर्भ में किया जाता है, हालांकि जुर्माना लगाने के बाद हमेशा फ्राँसी नहीं दी जाती है, इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा आजीवन कारावास में बदला जा सकता है या माफ किया जा सकता है। अतः कथन 2 सही है।

प्रश्न.3 शहरी स्थानीय निकायों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

- अधिसूचित क्षेत्र समिति के सभी सदस्यों को राज्य सरकार द्वारा नामांकित किया जाता है।
- छावनी बोर्ड का गठन और संचालन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही नहीं है/हैं ?

- केवल 1
- केवल 2
- 1 और 2 दोनों
- न तो 1 और न ही 2

उत्तर: D

व्याख्या:

भारत में शहरी स्थानीय सरकार की संरचना:

शहरी स्थानीय सरकार में आठ प्रकार के शहरी स्थानीय निकाय शामिल हैं।

● नगर निगम:

- ◆ नगर निगम आमतौर पर बड़े शहरों जैसे- बंगलूरू, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता आदि में हैं।

● नगर पालिका:

- ◆ छोटे शहरों में नगर पालिकाओं का प्रावधान होता है।

● अधिसूचित क्षेत्र समिति:

- ◆ तेजी से विकसित हो रहे कस्बों और मूलभूत सुविधाओं की कमी वाले कस्बों के लिये अधिसूचित क्षेत्र समितियाँ स्थापित की जाती हैं।

■ अधिसूचित क्षेत्र समिति के सभी सदस्यों को राज्य सरकार द्वारा नामांकित किया जाता है। अतः कथन 1 सही है।

● नगर क्षेत्र समिति:

- ◆ नगर क्षेत्र समिति छोटे शहरों में होती है।

● छावनी बोर्ड (Cantonment Board):

- ◆ यह आमतौर पर छावनी क्षेत्र में रहने वाली नागरिक आबादी के लिये स्थापित किया गया है।

■ इसका गठन और संचालन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। अतः कथन 2 सही है।

● बस्ती:

- ◆ प्लांट के पास स्थापित कॉलोनियों में रहने वाले कर्मचारियों और श्रमिकों को मूलभूत सुविधाएँ प्रदान करने के लिये टाउनशिप/ बस्ती (Township) शहरी सरकार का दूसरा रूप है।

● पोर्ट ट्रस्ट:

- ◆ पोर्ट ट्रस्ट मुंबई, चेन्नई, कोलकाता आदि बंदरगाह क्षेत्रों में स्थापित किये गए हैं।

● विशेष प्रयोजन एजेंसी:

- ◆ ये एजेंसियाँ नगर निगमों या नगर पालिकाओं से संबंधित निर्दिष्ट गतिविधियाँ या विशिष्ट कार्य करती हैं।

124. 'ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP)' के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. GRAP आपातकालीन उपायों का एक समूह है जो दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में एक निश्चित सीमा तक पहुँचने के बाद वायु की गुणवत्ता में और गिरावट को रोकने के लिये लागू होता है।
2. इसे एम. सी. मेहता बनाम भारत संघ (2016) के मामले में अपने आदेश के बाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित किया गया था।
3. इसे पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम एवं नियंत्रण) प्राधिकरण (EPCA) द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं ?

- A. केवल एक
- B. केवल दो
- C. सभी तीन
- D. कोई भी नहीं

उत्तर: B

व्याख्या:

ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP):

- GRAP आपातकालीन उपायों का एक समूह है जो दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में एक निश्चित सीमा तक पहुँचने के बाद वायु की गुणवत्ता को और अधिक खराब होने से रोकने के लिये लागू किया जाता है। अतः कथन 1 सही है।
- इसे एम. सी. मेहता बनाम भारत संघ (2016) के मामले में अपने आदेश के बाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित किया गया था। अतः कथन 2 सही है।
- वर्ष 2021 से वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) द्वारा GRAP को लागू किया जा रहा है।
- ◆ वर्ष 2020 तक, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम और नियंत्रण) प्राधिकरण (EPCA) राज्यों को GRAP उपायों को लागू करने का आदेश देता था। अतः कथन 3 सही नहीं है।

125. अंतरिम जमानत के संबंध में निम्नलिखित विकल्पों पर विचार कीजिये:

1. यह न्यायालय द्वारा एक ऐसे व्यक्ति को रिहा करने का निर्देश है जो पहले से ही गिरफ्तार है और पुलिस हिरासत में रखा गया है।
2. न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत या नियमित जमानत की मांग करने वाला आवेदन न्यायालय के समक्ष लंबित होने तक अस्थायी और छोटी अवधि के लिये जमानत दी जाती है।

3. यह एक कानूनी प्रावधान है जो किसी आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार होने से पहले जमानत के लिये आवेदन करने की अनुमति देता है।
4. अंतरिम जमानत का उद्देश्य उन व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करना है, जिन्हें किसी आपराधिक मामले के सिलसिले में गिरफ्तारी की आशंका हो सकती है, लेकिन अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं:

- A. केवल एक
- B. केवल दो
- C. केवल तीन
- D. सभी

उत्तर : B

भारत में जमानत के प्रकार:

- **नियमित जमानत:** यह न्यायालय (देश के भीतर किसी भी न्यायालय) द्वारा दिया गया एक निर्देश है जो पहले से ही गिरफ्तार और पुलिस हिरासत में रखे गए व्यक्ति को रिहा करने हेतु उपलब्ध है। ऐसी जमानत के लिये व्यक्ति CrPC की धारा 437 तथा 439 के तहत आवेदन दाखिल कर सकता है। अतः कथन 1 सही नहीं है।
- **अंतरिम जमानत:** न्यायालय द्वारा अस्थायी और अल्प अवधि हेतु जमानत दी जाती है, यह जमानत तब तक दी जा सकती है जब तक कि नियमित या अग्रिम जमानत हेतु आवेदन न्यायालय के समक्ष लंबित नहीं होता है। अतः कथन 2 सही है।
- **अग्रिम जमानत या पूर्व-गिरफ्तारी जमानत:** यह एक कानूनी प्रावधान है जो आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार होने से पहले जमानत हेतु आवेदन करने की अनुमति देता है। भारत में पूर्व-गिरफ्तारी जमानत का प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 438 में किया गया है। इसे केवल सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा दिया जाता है। अतः कथन 3 सही नहीं है।
- अंतरिम जमानत का उद्देश्य उन व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करना है, जिन्हें किसी आपराधिक मामले में गिरफ्तारी की आशंका हो सकती है, लेकिन अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। अतः कथन 4 सही है।

126. उपासना स्थल अधिनियम, 1991 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. सभी धार्मिक समुदाय तथा उनके उपासना स्थल उपासना स्थल अधिनियम, 1991 के अंतर्गत आते हैं।
2. उपासना स्थल अधिनियम, 1991 धार्मिक उपासना स्थलों के रूपांतरण पर रोक लगाता है।

3. यह अधिनियम यह सुनिश्चित करता है कि उपासना स्थल की धार्मिक पहचान वही रहेगी जो 15 अगस्त, 1947 को थी।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?

- A. केवल 1 और 2
- B. केवल 2
- C. केवल 3
- D. केवल 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

व्याख्या:

- उपासना स्थल अधिनियम, 1991 सभी धार्मिक समुदायों तथा उनके उपासना स्थलों पर लागू होता है। अतः कथन 1 सही है।
- उपासना स्थल अधिनियम 15 अगस्त, 1947 को मौजूद धार्मिक स्थलों की स्थिति को स्थिर करने के लिये अधिनियमित किया गया था तथा किसी भी उपासना स्थल के रूपांतरण पर रोक लगाता है और उनके धार्मिक स्वरूप के रख-रखाव को सुनिश्चित करता है। अतः कथन 2 सही है।
- धार्मिक स्वरूप का रखरखाव (धारा 4(1)):
 - ◆ यह सुनिश्चित करता है कि उपासना स्थल की धार्मिक प्रकृति वही बनी रहे जो 15 अगस्त, 1947 को थी। अतः कथन 3 सही है।

127. जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA), 1951 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. रिश्वतखोरी, अनुचित प्रभाव, झूठी जानकारी को RPA, 1951 के तहत भ्रष्ट आचरण के रूप में परिभाषित किया गया है।
2. इसके तहत एक उम्मेदवार निदेशक या प्रबंध एजेंट नहीं होना चाहिये और न ही उसे किसी ऐसे निगम में लाभ का पद धारण करना चाहिये जिसमें सरकार की कम से कम 25% हिस्सेदारी हो।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?

- A. केवल 1
- B. केवल 2
- C. 1 और 2 दोनों
- D. न तो 1 और न ही 2

उत्तर: C

व्याख्या:

संसद सदस्य की सदस्यता समाप्ति:

- चुनाव आचरण नियम, 1961 भारत में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत स्थापित नियमों का एक समूह है। इनमें

देश में चुनावों के संचालन को नियंत्रित करते हैं और प्रत्याशी, राजनीतिक दलों, चुनाव अधिकारियों तथा मतदाताओं द्वारा पालन किये जाने वाले दिशा-निर्देश तथा प्रक्रियाओं का वर्णन है।

- इन नियमों में चुनावी प्रक्रिया के विभिन्न पहलु शामिल हैं, जिनमें नामांकन पत्र दाखिल करना, नामांकन की जाँच, चुनाव अभियान नियम, मतदान प्रक्रियाएँ, वोटों की गणना और चुनाव विवाद समाधान शामिल हैं।

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत भ्रष्ट आचरण:

● अधिनियम की धारा 123:

- ◆ RPA अधिनियम की धारा 123 के अनुसार, "भ्रष्ट आचरण" वह है जिसमें एक प्रत्याशी चुनाव जीतने की अपनी संभावनाओं को बेहतर बनाने के लिये कुछ इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं, जिसके अंतर्गत रिश्वत, अनुचित प्रभाव, झूठी जानकारी, और धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर भारतीय नागरिकों के विभिन्न वर्गों के बीच घृणा, "दुश्मनी की भावनाओं को बढ़ावा देना अथवा ऐसा प्रयास करना शामिल है।" अतः कथन 1 सही है।

● धारा 123(4):

- ◆ यह चुनाव परिणामों को प्रभावित करने वाली भ्रामक जानकारी के प्रकाशन पर प्रतिबंध लगाने हेतु "भ्रष्ट आचरण" की परिभाषा को और व्यापक बनाता है।
- ◆ इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक निर्वाचित प्रतिनिधि को कुछ अपराधों हेतु जैसे- भ्रष्ट आचरण के आधार पर, चुनाव खर्च घोषित करने में विफल रहने पर और सरकारी अनुबंधों या कार्यों में संलग्न होने का दोषी ठहराए जाने पर अयोग्य घोषित किया जा सकता है।

RPA, 1951 के अंतर्गत सांसद की अयोग्यता के प्रावधान:

- वह निदेशक या प्रबंध एजेंट नहीं होना चाहिये और न ही उसे किसी ऐसे निगम में लाभ का पद धारण करना चाहिये जिसमें सरकार की कम से कम 25% हिस्सेदारी हो। अतः कथन 2 सही है।

128. कार्यकारी मजिस्ट्रेट (EM) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. EM कार्यकारी शाखा का एक अधिकारी होता है जिसके पास भारतीय दंड संहिता (IPC) और आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) दोनों के अंतर्गत शक्तियाँ प्राप्त हैं।
2. इनकी नियुक्ति राज्य सरकारों द्वारा की जाती है।
3. जब वे शांति और व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में जाँच करते समय न्यायिक प्रकृति के कार्य करते हैं तब वे कभी-कभी अदालतों की तरह कार्य करते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं ?

- A. केवल एक
- B. केवल दो
- C. सभी तीन
- D. कोई भी नहीं

उत्तर : C

व्याख्या :

कार्यकारी मजिस्ट्रेट:

- CRPC, मजिस्ट्रेट को 2 प्रकारों में वर्गीकृत करता है- कार्यकारी मजिस्ट्रेट और न्यायिक मजिस्ट्रेट। CRPC की धारा 3(4) दोनों के बीच बेहतर संबंधों को लागू करती है।
- एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट (EM), कार्यकारी शाखा का एक अधिकारी होता है जिसके पास भारतीय दंड संहिता (IPC) और आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CRPC) दोनों के अंतर्गत शक्तियाँ होती हैं।
- ◆ अतः कथन 1 सही है।
- EM की नियुक्ति राज्य सरकारों द्वारा की जाती है, और वे मुख्य रूप से कानून तथा व्यवस्था बनाए रखने एवं पुलिस और प्रशासनिक कार्य करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
- ◆ अतः कथन 2 सही है।
- दूसरी ओर, न्यायिक मजिस्ट्रेट सज़ा/जुर्माना/हिरासत का फैसला सुनाते हैं और जाँच की प्रक्रिया में साक्ष्यों की जाँच करते हैं।
- साथ ही, न्यायिक मजिस्ट्रेट उच्च न्यायालयों के सीधे नियंत्रण में होते हैं।
- ◆ EM कभी-कभी न्यायालयों के रूप में कार्य करते हैं जब वे शांति और व्यवस्था बनाए रखने (CRPC धारा.107) के संबंध में जाँच (CRPC धारा.116) करते समय न्यायिक प्रकृति के अनुरूप कार्य करते हैं।
- ◆ अतः कथन 3 सही है।

129. एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज (A-वेब) के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है ?

- A. A-वेब दुनिया भर में चुनाव प्रबंधन निकायों (EMB) का सबसे बड़ा संघ है।
- B. A-WEB का स्थायी सचिवालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है।
- C. इसकी स्थापना दुनिया भर में स्थायी लोकतंत्र प्राप्त करने के अपने सदस्यों के बीच साझा दृष्टिकोण के साथ की गई थी।

D. A-वेब विभिन्न चुनाव प्रबंधन प्रथाओं का अध्ययन करने और EMB के अन्य सदस्यों के साथ ज्ञान साझा करने के लिए विभिन्न देशों में चुनाव आगंतुक और अवलोकन कार्यक्रम भी चलाता है।

उत्तर : b

व्याख्या :

विश्व चुनाव निकायों का संघ (A-वेब)

- एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज (A-वेब) दुनिया भर में चुनाव प्रबंधन निकायों (EMB) का सबसे बड़ा संघ है।
- इसकी स्थापना 14 अक्टूबर 2013 को दक्षिण कोरिया में हुई थी।
- A-WEB का स्थायी सचिवालय सियोल, दक्षिण कोरिया में स्थित है। अतः कथन b सही नहीं है।
- इसकी स्थापना दुनिया भर में स्थायी लोकतंत्र प्राप्त करने के अपने सदस्यों के बीच साझा दृष्टिकोण के साथ की गई थी।
- A-वेब विभिन्न चुनाव प्रबंधन प्रथाओं का अध्ययन करने और EMB के अन्य सदस्यों के साथ ज्ञान साझा करने के लिये विभिन्न देशों में चुनाव आगंतुक और अवलोकन कार्यक्रम भी चलाता है।

130. प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 (ITPA) देह व्यापार के लिये तस्करी की रोकथाम हेतु प्रमुख कानून है।
2. भारत अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UNCTOC) का सदस्य है।
3. वेश्यावृत्ति के लिये महिलाओं और बच्चों की तस्करी को रोकने और मुकाबला करने पर SAARC अभिसमय का भारत हस्ताक्षरकर्ता है।

उपर्युक्त कथनों में कितने सही हैं ?

- A. केवल एक
- B. केवल दो
- C. सभी तीन
- D. उपर्युक्त में से कोई नहीं

उत्तर : C

व्याख्या :

भारत में प्रासंगिक कानून और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन:

- अन्य कानून:
 - ◆ अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 (ITPA) देह व्यापार के लिये तस्करी की रोकथाम हेतु प्रमुख कानून है। अतः कथन 1 सही है।
 - ◆ महिलाओं और बच्चों की तस्करी से संबंधित अन्य विशिष्ट कानून बनाए गए हैं- बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006; बंधुआ श्रम प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976; बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986; मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994।

- ◆ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012 बच्चों को यौन दुर्व्यवहार और शोषण से बचाने के लिये एक विशेष कानून है।
- अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन:
 - ◆ अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNCTOC) महिलाओं और बच्चों की तस्करी को रोकने, शोषणकारियों और अपराधियों को दंडित करने के लिये एक प्रोटोकॉल है (भारत इसका हस्ताक्षरकर्ता है)। अतः कथन 2 सही है।
 - ◆ वेश्यावृत्ति के लिये महिलाओं और बच्चों की तस्करी को रोकने तथा मुकाबला करने पर SSARC अभिसमय (भारत इसका हस्ताक्षरकर्ता है)। अतः कथन 3 सही है।

131. छावनी बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. बोर्ड में निर्वाचित और नामांकित सदस्यों का समान प्रतिनिधित्व होता है।
 2. छावनी का स्टेशन कमांडर बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है।
- उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?
- A. केवल 1
 - B. केवल 2
 - C. 1 तथा 2 दोनों
 - D. न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (C)

व्याख्या:

- छावनियाँ और उनकी संरचना:
 - ◆ क्षेत्र और जनसंख्या के आकार के आधार पर छावनियों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है- श्रेणी- I से श्रेणी- IV तक।
 - ◆ श्रेणी- I छावनी में आठ निर्वाचित नागरिक और बोर्ड में आठ सरकारी/सैन्य सदस्य होते हैं, वहीं श्रेणी- IV छावनी में दो निर्वाचित नागरिक और दो सरकारी/सैन्य सदस्य होते हैं।
 - ◆ यह बोर्ड छावनी के प्रशासन के विभिन्न पहलुओं के लिये जिम्मेदार है।
 - छावनी का स्टेशन कमांडर बोर्ड का पदेन (Ex-officio) अध्यक्ष होता है और रक्षा संपदा संगठन का एक अधिकारी मुख्य कार्यकारी एवं सदस्य-सचिव होता है। अतः कथन 2 सही है।
 - आधिकारिक प्रतिनिधित्व को संतुलित करने के लिये बोर्ड में निर्वाचित और नामांकित/पदेन सदस्यों का समान प्रतिनिधित्व है। अतः कथन 1 सही है।

132. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

कथन-I: ज़ीरो FIR, एक FIR है जिसे किसी भी पुलिस स्टेशन द्वारा क्षेत्राधिकार की परवाह किये बिना, तब दर्ज किया जा सकता है जब उसे किसी संज्ञेय अपराध के संबंध में शिकायत प्राप्त होती है।

कथन-II: ज़ीरो FIR दर्ज होने पर नियमित FIR नंबर निर्दिष्ट किया जाता है।

उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा सही है ?

- A. कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं तथा कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या है।
- B. कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं तथा कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है।
- C. कथन-I सही है लेकिन कथन-II गलत है।
- D. कथन-I गलत है लेकिन कथन-II सही है।

उत्तर: (C)

व्याख्या:

ज़ीरो FIR:

- परिचय:

- ◆ ज़ीरो FIR, एक FIR है जिसे किसी भी पुलिस स्टेशन द्वारा क्षेत्राधिकार की परवाह किये बिना, तब दर्ज किया जा सकता है जब उसे किसी संज्ञेय अपराध के संबंध में शिकायत मिलती है। अतः कथन-I सही है।

- ◆ इस स्तर पर कोई नियमित FIR नंबर निर्दिष्ट नहीं किया जाता है। अतः कथन-II सही नहीं है।

- ◆ ज़ीरो FIR मिलने के बाद रेवेन्यू पुलिस स्टेशन नई FIR दर्ज करता है और जाँच शुरू करता है।

- ◆ इसका उद्देश्य गंभीर अपराधों के पीड़ितों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों को एक पुलिस स्टेशन से दूसरे पुलिस स्टेशन तक गए बिना, जल्दी एवं आसानी से शिकायत दर्ज कराने में सहायता प्रदान करना है।

- ◆ इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना भी है कि शिकायत दर्ज करने में देरी के कारण सबूत और गवाह खो न जाएँ या उनके साथ छेड़छाड़ न हो।

133. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

कथन I: CrPC की धारा 151 एक पुलिस अधिकारी को बिना वारंट या मजिस्ट्रेट के आदेश के व्यक्तियों को गिरफ्तार करने में सक्षम बनाती है यदि उनके पास संज्ञेय अपराध करने की योजना बना रहे व्यक्तियों के बारे में जानकारी है।

कथन II: सीआरपीसी की धारा 107 मजिस्ट्रेटों को शांति बनाए रखने और सार्वजनिक व्यवस्था के किसी भी संभावित उल्लंघन को रोकने के लिये व्यक्तियों को जमानतदारों के साथ या बिना जमानत के बाँड निष्पादित करने की शक्ति प्रदान करती है।

उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा सही है ?

- कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं तथा कथन-II कथन-I की सही व्याख्या है
- कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं तथा कथन-II कथन-I की सही व्याख्या नहीं है
- कथन-I सही है लेकिन कथन-II गलत है
- कथन-I गलत है लेकिन कथन-II सही है

उत्तर: b

व्याख्या:

CrPC की धारा 107 और धारा 151

- धारा 107: धारा 107 के अनुसार, एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट यह अनुरोध कर सकता है कि कोई व्यक्ति यह कारण प्रदर्शित करे कि उन्हें अधिकतम एक वर्ष के लिये शांति बनाए रखने हेतु बांड पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता क्यों नहीं होनी चाहिये, यदि EM को जानकारी है कि व्यक्ति ने अशांति फैलाई है (या इसकी संभावना है) या सार्वजनिक शांति को भंग किया है।

◆ अतः कथन II सही है।

- धारा 151: यह संज्ञेय अपराधों को घटित होने से रोकने के लिये गिरफ्तारी का प्रावधान करती है।

◆ यह एक पुलिस अधिकारी को अधिकृत करती है जिसे ऐसे किसी अपराध को करने की योजना बना रहे कुछ व्यक्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, तब उन्हें वारंट या मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना ही गिरफ्तार करने का अधिकार प्राप्त है। अतः कथन I सही है।

◆ हालाँकि उन्हें 24 घंटे से अधिक समय तक के लिये हिरासत में नहीं रखा जा सकता जब तक कि अगले आदेश (या किसी अन्य कानून) में ऐसा प्रावधान न किया गया हो।

- अतः दोनों कथन सही हैं, लेकिन कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है।

134. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. भारत में ओटीटी प्लेटफॉर्मों को सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के माध्यम से विनियमित किया जाता है।

2. नियमों के अनुसार, प्रत्येक प्रसारक को 15 दिनों में शिकायतें प्राप्त करने और उनका निवारण करने के लिये भारत में एक शिकायत अधिकारी नियुक्त करना अनिवार्य है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही नहीं है/हैं ?

- A. केवल 1
- B. केवल 2
- C. 1 और 2 दोनों
- D. न तो 1 और न ही 2

उत्तर: D

व्याख्या:

ओटीटी प्लेटफॉर्मों को विनियमित करने वाले कानून:

- सरकार ने OTT प्लेटफॉर्मों को विनियमित करने के लिये फरवरी 2022 में सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया नैतिकता संहिता) नियम, 2021 को अधिसूचित किया था। अतः कथन 1 सही है।
- यह नियम OTT प्लेटफॉर्म के लिये आचार संहिता और त्रि-स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र के साथ एक सॉफ्ट-टच स्व-नियामक आर्किटेक्चर स्थापित करते हैं।
- ◆ प्रत्येक प्रसारक को 15 दिनों के भीतर शिकायतें प्राप्त करने और उनके निवारण के लिये भारत में स्थित एक शिकायत अधिकारी नियुक्त करना चाहिये। अतः कथन 2 सही है।
- ◆ साथ ही प्रत्येक प्रकाशक को एक स्व-नियामक निकाय का सदस्य बनने की आवश्यकता है। ऐसे निकाय को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में पंजीकरण कराना होगा और उन शिकायतों का समाधान करना होगा जिनका समाधान प्रकाशक द्वारा 15 दिनों के भीतर नहीं किया गया है।

135. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के अंतर्गत किसी भी नागरिक को धर्म की परवाह किये बिना विवाह करने की अनुमति है।
2. सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने सरला मुद्गल केस, 1995 में समान नागरिक संहिता (UCC) की आवश्यकता की सिफारिश की थी।
3. विवाह, तलाक, विरासत जैसे पर्सनल लॉ विषय समवर्ती सूची (संविधान की 7वीं अनुसूची) के अंतर्गत आते हैं।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं ??

- A. केवल एक
- B. केवल दो
- C. सभी तीन
- D. कोई भी नहीं

उत्तर: C

व्याख्या:

भारत में समान नागरिक संहिता (UCC) की दिशा में प्रयास:

- सांविधिक प्रावधान:
 - ◆ विशेष विवाह अधिनियम, 1954: विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के अंतर्गत किसी भी नागरिक को धर्म की परवाह किये बिना विवाह करने की अनुमति है। अतः कथन 1 सही है।
 - भारत में विवाह, तलाक, विरासत जैसे पर्सनल लॉ विषय समवर्ती सूची (संविधान की 7वीं अनुसूची) के अंतर्गत आते हैं। अतः कथन 3 सही है।
- UCC की सिफारिश करने वाले सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय:
 - शाहबानो केस, 1985
 - सरला मुदगल केस, 1995
 - ◆ अतः कथन 2 सही है।
- पाउलो कॉटिन्हो बनाम मारिया लुइज़ा वेलेंटीना परेरा (2019)

136. सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (ART) विनियम अधिनियम, 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. अंडाणु दाता एक विवाहित महिला होनी चाहिये और उसका अपना कम-से-कम एक जीवित बच्चा होना चाहिये।
2. ART सेवाओं को विनियमित करने का कार्य सरोगेसी अधिनियम, 2021 के तहत गठित राष्ट्रीय और राज्य बोर्ड द्वारा किया जाएगा।
3. एक अंडाणु दाता अपने जीवनकाल में केवल एक बार दान कर सकती है।

उपर्युक्त कथनों में कितने सही हैं ?

- A. केवल एक
- B. केवल दो
- C. तीनों
- D. कोई भी नहीं

उत्तर: C

व्याख्या:

ART नियमन अधिनियम, 2021 की मुख्य विशेषताएँ:

- पंजीकरण: प्रत्येक ART क्लिनिक तथा बैंक को एक केंद्रीय डेटाबेस बनाए रखते हुए भारत के बैंकों और क्लिनिकों की राष्ट्रीय रजिस्ट्री के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिये।
- ◆ पंजीकरण पाँच वर्षों के लिये वैध है और इसे अगले पाँच वर्षों के लिये नवीनीकृत भी किया जा सकता है।

◆ अधिनियम के उल्लंघन के परिणामस्वरूप पंजीकरण रद्द या निलंबित किया जा सकता है।

- शुक्राणुओं और अंडाणुओं को दान करने की शर्तें: पंजीकृत ART बैंक, 21-55 वर्ष की आयु के पुरुषों के शुक्राणुओं की स्क्रीनिंग, संग्रह और भंडारण कर सकते हैं। इसके साथ ही 23-35 वर्ष की आयु की महिलाएँ अंडाणुओं का भंडारण कर सकती हैं।
- दाता की सीमाएँ: एक अंडाणु (Oocyte) दाता को विवाहित महिला होना चाहिये, इसके साथ ही उनका अपना कम-से-कम एक जीवित बच्चा (न्यूनतम तीन वर्ष की आयु) होना चाहिये। अतः कथन 1 सही है।
- ◆ एक अंडाणु दाता अपने जीवनकाल में केवल एक बार दान कर सकती है, इसके साथ ही अधिकतम सात अंडाणु पुनः प्राप्त किये जा सकते हैं। अतः कथन 3 सही है।
- युग्मक आपूर्ति: एक ART बैंक एकल दाता से एक से अधिक कमीशनिंग दंपति (सेवाएँ चाहने वाले दंपति) को युग्मक की आपूर्ति नहीं कर सकता है।
- माता-पिता के अधिकार: ART के माध्यम से पैदा हुए बच्चों को दंपति का जैविक शिशु माना जाता है और दाता के पास माता-पिता का कोई अधिकार नहीं होता है।
- सहमति: ART प्रक्रियाओं के लिये दंपति और दाता दोनों की लिखित सूचित सहमति आवश्यक है।
- ART प्रक्रियाओं का नियमन: ART सेवाओं को विनियमित करने का कार्य सरोगेसी अधिनियम, 2021 के तहत गठित राष्ट्रीय और राज्य बोर्ड द्वारा किया जाएगा। अतः कथन 2 सही है।

137. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत CSR प्रावधान 1,000 करोड़ या उससे अधिक के वार्षिक कारोबार वाली कंपनियों पर लागू होते हैं।
2. एक्वायर्ड इम्यून डेफिशियेंसी सिंड्रोम (AIDS) से लड़ना, कुपोषण और विरासत स्थलों की सुरक्षा उन गतिविधियों में से हैं जो CSR के अंतर्गत शामिल हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?

- A. केवल 1
- B. केवल 2
- C. 1 और 2 दोनों
- D. ना तो 1 और न ही 2

उत्तर: C

व्याख्या:

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR):

● परिचय:

◆ कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा में यह दृष्टिकोण निहित है कि कंपनियों को पर्यावरण एवं सामाजिक कल्याण पर उनके प्रभावों का आकलन करना चाहिये और ज़िम्मेदारी लेनी चाहिये, साथ ही सकारात्मक सामाजिक तथा पर्यावरणीय परिवर्तन को बढ़ावा देना चाहिये।

◆ कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के चार मुख्य प्रकार हैं:

- पर्यावरणीय उत्तरदायित्व
- नैतिक उत्तरदायित्व
- परोपकारी उत्तरदायित्व
- आर्थिक उत्तरदायित्व

◆ कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व प्रावधान उन कंपनियों पर लागू होते हैं जिनका वार्षिक कारोबार 1,000 करोड़ रुपए एवं उससे अधिक है, या जिनकी कुल संपत्ति 500 करोड़ रुपए एवं उससे अधिक है, या उनका शुद्ध लाभ 5 करोड़ रुपए एवं उससे अधिक है। अतः कथन 1 सही है।

- इस अधिनियम में कंपनियों द्वारा एक CSR समिति गठित करना आवश्यक है जो निदेशक मंडल को एक कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति की सिफारिश करेगी और समय-समय पर उसकी निगरानी भी करेगी।

● CSR के अंतर्गत गतिविधियाँ :

◆ कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट कुछ प्रमुख गतिविधियों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- भुखमरी, गरीबी एवं कुपोषण का उन्मूलन करना और शिक्षा, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना।
- एक्वायर्ड इम्यून डेफिसिएंसी सिंड्रोम (एड्स), ह्यूमन इम्यूनोडेफिसिएंसी वायरस और अन्य विकारों से लड़ना।
- पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना।
- इमारतों और ऐतिहासिक महत्त्व के स्थलों तथा कला के कार्यों की बहाली सहित राष्ट्रीय धरोहर, कला एवं संस्कृति का संरक्षण।
- सशस्त्र बलों के शहीदों, युद्ध विधवाओं और उनके आश्रितों के लाभ के लिये उपाय करना।

■ ग्रामीण खेलों, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेलों, पैरालंपिक खेलों तथा ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिये प्रशिक्षण देना।

■ प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष या सामाजिक-आर्थिक विकास और राहत के लिये केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किसी अन्य कोष में योगदान देना।

■ अतः कथन 2 सही है।

138. राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण दिशा-निर्देशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. दिशा-निर्देश राज्यों को उन रोगियों से पंजीकरण शुल्क लेने की अनुमति देते हैं जो अंग प्राप्तकर्ता प्रतीक्षा सूची में पंजीकृत होना चाहते हैं।
2. दिशा-निर्देशों ने अंग प्राप्तकर्ता के रूप में पंजीकरण करने के लिये अधिवास की आवश्यकता को हटा दिया है।
3. उन्होंने ऊपरी आयु सीमा हटा दी है क्योंकि लोग अब अधिक समय तक जीवित रह रहे हैं।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं ??

- A. केवल एक
- B. केवल दो
- C. सभी तीन
- D. उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर: C

व्याख्या:

राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण दिशा-निर्देश:

● आयु सीमा हटा दी गई:

◆ ऊपरी आयु सीमा हटा दी गई है क्योंकि लोग अब अधिक समय तक जीवित रह रहे हैं। अतः कथन 3 सही है।

■ इससे पहले NOTTO (राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन) दिशा-निर्देशों के अनुसार, 65 वर्ष से अधिक उम्र के अंतिम चरण के अंग विफलता वाले रोगी को अंग प्राप्त करने के लिये पंजीकरण करने से प्रतिबंधित किया गया था।

● अधिवास की आवश्यकता नहीं:

◆ मंत्रालय ने 'एक राष्ट्र, एक नीति' कदम के तहत किसी विशेष राज्य में अंग प्राप्तकर्ता के रूप में पंजीकरण करने के लिये अधिवास की आवश्यकता को हटा दिया है। अतः कथन 2 सही है।

◆ अब कोई भी जरूरतमंद मरीज़ अपनी पसंद के किसी भी राज्य में अंग प्राप्त करने के लिये पंजीकरण करा सकेगा और साथ ही वहीं सर्जरी भी करा सकेगा।

- पंजीकरण के लिये कोई शुल्क नहीं:
 - ◆ कोई पंजीकरण शुल्क नहीं होगा, जो राज्य पहले इस उद्देश्य के लिये शुल्क लेते थे, केंद्र ने उन राज्यों से ऐसा नहीं करने को कहा है। अतः कथन 1 सही है।
 - ◆ पंजीकरण के लिये शुल्क लेने वाले राज्यों में गुजरात, तेलंगाना, महाराष्ट्र और केरल शामिल थे।
 - कुछ राज्यों में अंग प्राप्तकर्ता प्रतीक्षा सूची में मरीज को पंजीकृत करने के लिये शुल्क 5,000 रुपए से 10,000 रुपए के बीच है।

139. "भारत में सबमरीन केबल लैंडिंग के लिये लाइसेंसिंग ढाँचा और नियामक तंत्र" के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. "भारत में सबमरीन केबल लैंडिंग के लिये लाइसेंसिंग ढाँचा और नियामक तंत्र" भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया है।
2. केबल लैंडिंग स्टेशन (CLS) 'उपस्थिति बिंदु' को वैध अवरोधन की अनुमति एवं अपेक्षित सुरक्षा अभ्यास को पूरा करने की आवश्यकता है।
3. TRAI ने भारतीय दूरसंचार विधेयक, 2022 में "सबमरीन केबल" और "केबल लैंडिंग स्टेशन" से संबंधित एक अनुच्छेद को शामिल करने की सिफारिश की है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं ?

- A. केवल एक
- B. केवल दो
- C. सभी तीन
- D. कोई भी नहीं

उत्तर: B

व्याख्या:

- "भारत में सबमरीन केबल लैंडिंग के लिये लाइसेंसिंग ढाँचा और नियामक तंत्र" भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) द्वारा जारी किया जाता है। अंतः कथन 1 सही नहीं है।
- केबल लैंडिंग स्टेशन (CLS) 'उपस्थिति बिंदु' को वैध अवरोधन की अनुमति एवं अपेक्षित सुरक्षा अभ्यास को पूरा करने की आवश्यकता है। अंतः कथन 2 सही है।
- TRAI ने भारतीय दूरसंचार विधेयक, 2022 में "सबमरीन केबल" और "केबल लैंडिंग स्टेशन" से संबंधित एक अनुच्छेद को शामिल करने की सिफारिश की है। अंतः कथन 3 सही है।

140. प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम, 2002 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (CCI) को प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम, 2002 के तहत कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) के आचरण की जाँच करने का अधिकार है।
2. प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम, 2002, भारतीय बाजार में प्रतिस्पर्द्धा को नियंत्रित करता है और प्रतिस्पर्द्धा-विरोधी प्रथाओं पर रोक लगाता है।
3. प्रतिस्पर्द्धा अपीलीय न्यायाधिकरण भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग के किसी भी नियम, निर्णय या आदेश के खिलाफ अपील सुनने और विनियमित करने के लिये प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम, 2002 के अनुसार बनाई गई एक वैधानिक संस्था है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही नहीं हैं ?

- A. केवल एक
- B. केवल दो
- C. सभी तीन
- D. इनमें से कोई नहीं

उत्तर: D

व्याख्या:

- कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग के दायरे में आती है।
- भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (CCI) को प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम, 2002 के तहत कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) के आचरण की जाँच करने का अधिकार है। अतः कथन 1 सही है।
- प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम, 2002, भारतीय बाजार में प्रतिस्पर्द्धा को नियंत्रित करता है और प्रतिस्पर्द्धा-विरोधी प्रथाओं पर रोक लगाता है। अतः कथन 2 सही है।
- प्रतिस्पर्द्धा अपीलीय न्यायाधिकरण भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग के किसी भी नियम, निर्णय या आदेश के खिलाफ अपील सुनने और विनियमित करने के लिये प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम, 2002 के अनुसार बनाई गई एक वैधानिक संस्था है। अतः कथन 3 सही है।

141. भारत में बलात्कार से संबंधित कानूनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. POCSO अधिनियम के तहत सहमति की आयु को बढ़ाकर 18 वर्ष कर दिया गया और 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों के लिये किसी भी प्रकार के यौन गतिविधियों को आपराध की श्रेणी में सूचीबद्ध कर दिया गया, भले ही दो नाबालिगों के बीच सहमति हो।

2. इस अधिनियम के तहत बलात्कार की न्यूनतम सजा को सात वर्ष से बढ़ाकर दस वर्ष कर दिया गया।
3. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 357A के रूप में एक नया प्रावधान पेश किया गया है, यह पीड़ित के लिये मुआवजे से संबंधित है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं ?

- A. केवल एक
- B. केवल दो
- C. तीनों
- D. कोई भी नहीं

उत्तर: C

व्याख्या:

भारत में यौन शोषण/बलात्कार से संबंधित कानून:

- **आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 2013:**
 - ◆ इस अधिनियम के तहत बलात्कार की न्यूनतम सजा को सात वर्ष से बढ़ाकर दस वर्ष कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त पीड़ित की मृत्यु के मामले में न्यूनतम सजा को विधिवत बढ़ाकर बीस वर्ष कर दिया गया है। अतः कथन 1 सही है।
- **यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (पाँक्सो):**
 - ◆ इस अधिनियम को बच्चों को यौन अत्याचार, यौन उत्पीड़न और अश्लील साहित्य से बचाने के लिये लाया गया था।
 - ◆ POC SO अधिनियम के तहत सहमति की आयु बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी गई (जो वर्ष 2012 तक 16 वर्ष थी) और 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों के लिये सभी यौन गतिविधियों को अपराध की श्रेणी में सूचीबद्ध कर दिया गया, भले ही दो नाबालिगों के बीच तथ्यात्मक रूप से सहमति हो। अतः कथन 2 सही है।
 - बच्चे की रक्षा, सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न अपराधों के लिये सजा बढ़ाने के प्रावधान करने के लिये इस अधिनियम में वर्ष 2019 में भी संशोधन किया गया था।
- **बलात्कार पीड़िता के अधिकार:**
 - ◆ **ज़ीरो FIR का अधिकार:** इसका अर्थ है कि एक व्यक्ति किसी भी पुलिस स्टेशन में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा सकता है, भले ही घटना का अधिकार क्षेत्र कोई भी हो।
 - ◆ **मुफ्त चिकित्सा उपचार:** आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 357C के अनुसार, कोई भी निजी अथवा सरकारी अस्पताल बलात्कार पीड़ितों के इलाज के लिये शुल्क नहीं ले सकता है।

- ◆ **टू-फिंगर टेस्ट का प्रावधान खत्म:** चिकित्सीय जाँच करते समय किसी भी चिकित्सक को टू फिंगर टेस्ट करने का अधिकार नहीं होगा।
- ◆ **मुआवजे का अधिकार:** CrPC की धारा 357A के रूप में एक नया प्रावधान पेश किया गया है, यह पीड़ित के लिये मुआवजे से संबंधित है। अतः कथन 3 सही है।

142. निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा सही नहीं है ?

- A. भारत में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की उन्नति हेतु विशेष प्रावधान करने की राज्य की शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4) द्वारा समर्थित है।
- B. 103वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है।
- C. वर्ष 1953 में स्थापित काका कालेलकर आयोग को प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के नाम से भी जाना जाता है।
- D. उपर्युक्त में से कोई भी नहीं।

उत्तर: B

व्याख्या:

- अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) शब्द में नागरिकों के वे सभी वर्ग शामिल हैं जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं।
- ◆ संविधान के अनुच्छेद 15(4) के तहत राज्य के पास किसी भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग यानी OBC की उन्नति के लिये विशेष प्रावधान करने की शक्ति है। अतः कथन A सही है।
 - यह शब्द "उन्नति के लिये विशेष प्रावधान" में शैक्षणिक संस्थानों में सीटों का आरक्षण, वित्तीय सहायता, छात्रवृत्ति, मुफ्त आवास आदि जैसे कई पहलू शामिल हैं।
- ◆ अनुच्छेद 16(4) के तहत राज्य को OBC के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिये कानून बनाने का अधिकार है।
- वर्ष 1950 और 1970 के दशक में काका कालेलकर और बी.पी. मंडल की अध्यक्षता में क्रमशः दो पिछड़ा वर्ग आयोगों की नियुक्ति की गई।
 - ◆ काका कालेलकर आयोग को प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में भी जाना जाता है। अतः कथन C सही है।
 - ◆ इन निर्देशों के अनुपालन में संसद ने वर्ष 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम पारित किया और NCBC का गठन किया।
- 102वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2018 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। अतः कथन B सही नहीं है।

- ◆ इसे सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के बारे में शिकायतों तथा कल्याणकारी उपायों की जाँच करने का अधिकार प्राप्त है।
- ◆ इससे पहले NCBC सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निकाय था।

143. आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (ECA) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. वर्ष 1955 का ECA केंद्र सरकार हेतु एक तंत्र के रूप में कार्य करता है जो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं से जुड़ी व्यापार गतिविधियों पर नियंत्रण प्रदान करके राज्य सरकारों को मुद्रास्फीति को रोकने में सशक्त बनाता है।
2. यह अधिनियम केंद्र सरकार को अधिनियम की अनुसूची से किसी वस्तु को जोड़ने या हटाने की शक्ति देता है।
3. किसी वस्तु को आवश्यक घोषित करने के बाद भी सरकार उस वस्तु के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को नियंत्रित नहीं कर सकती है एवं न ही स्टॉक सीमा लगा सकती है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं ?

- A. केवल एक
- B. केवल दो
- C. सभी तीन
- D. कोई भी नहीं

उत्तर: B

व्याख्या:

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955:

- राज्य सरकारों को वस्तुओं की एक विस्तृत श्रृंखला से जुड़ी व्यापार गतिविधियों पर अधिकार प्रदान करके आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 केंद्र सरकार हेतु एक उपकरण के रूप में कार्य करता है ताकि उन्हें मुद्रास्फीति से निपटने के प्रयासों में सशक्त और सक्षम बनाया जा सके। अतः कथन 1 सही है।
- आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 केंद्र सरकार को अधिनियम की अनुसूची से वस्तुओं को शामिल करने या बाहर करने का अधिकार देता है, जिससे उनकी व्यापार गतिविधियों को विनियमित करने की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं। अतः कथन 2 सही है।
- आवश्यक वस्तु की घोषणा के माध्यम से सरकार इसके उत्पादन, आपूर्ति और वितरण पर नियंत्रण रखने की क्षमता प्राप्त करती है, साथ ही इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने एवं जमाखोरी को रोकने हेतु स्टॉक सीमा लागू करती है। अतः कथन 3 सही नहीं है।

144. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. CBI, DSPE अधिनियम, 1946 के अंतर्गत कार्य करती है। यह न तो संवैधानिक है और न ही वैधानिक निकाय है।

2. CBI की स्थापना कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के एक संकल्प द्वारा की गई थी और बाद में इसे गृह मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया था।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं ?

- A. केवल 1
- B. केवल 2
- C. 1 और 2 दोनों
- D. न तो 1 और न ही 2

उत्तर: A

व्याख्या:

- केंद्र सरकार और उसके प्राधिकरणों के भीतर संयुक्त सचिव या उच्चतर पद धारण करने वाले अधिकारियों द्वारा किये गए किसी अपराध की जाँच या जाँच प्रारंभ करने से पहले केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य है। यह पूर्वापेक्षा सुनिश्चित करती है कि CBI केंद्र सरकार और उससे संबंधित संस्थाओं के भीतर वरिष्ठ-रैंकिंग के अधिकारियों को शामिल करने वाली किसी भी तरह की पूछताछ या जाँच करने से पहले सर्वोच्च शासी निकाय से आधिकारिक सहमति प्राप्त करती है। अतः कथन 1 सही है।
- CBI की स्थापना गृह मंत्रालय द्वारा एक प्रस्ताव के माध्यम से प्रारंभ की गई थी और बाद में इसे कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया, जहाँ यह वर्तमान में एक संलग्न कार्यालय के रूप में कार्य करता है। अतः कथन 2 सही नहीं है।

145. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. प्रतिकूल कब्जा शत्रुतापूर्ण, निरंतर, निर्बाध और शांतिपूर्ण कब्जे के माध्यम से संपत्ति के अधिग्रहण को संदर्भित करता है।
2. 12 वर्ष से अधिक समय से निजी अथवा सरकारी जमीन पर कब्जा रखने वाला कोई भी व्यक्ति उस संपत्ति का मालिक बन सकता है।

उपर्युक्त कथनों में कितने सही हैं ?

- A. केवल 1
- B. केवल 2
- C. 1 और 2 दोनों
- D. न तो 1 और न ही 2

उत्तर: A

व्याख्या:

- प्रतिकूल कब्जा शत्रुतापूर्ण, निरंतर, निर्बाध और शांतिपूर्ण कब्जे के माध्यम से संपत्ति के अधिग्रहण को संदर्भित करता है। अतः कथन 1 सही है।

- इस अवधारणा का उद्देश्य भूमि के स्वामित्व को लेकर लंबे समय से चली आ रही शंकाओं को रोकना है और किसी भू-मालिक द्वारा छोड़ी गई बेकार भूमि का उपयोग करने की अनुमति देकर समाज को लाभान्वित करना है।
- ◆ यह उन व्यक्तियों को भी सुरक्षा प्रदान करता है जिन्होंने कब्जा करने वाले को संपत्ति का वास्तविक स्वामी माना है।
- परिसीमा अधिनियम, 1963 के प्रमुख प्रावधान:
 - ◆ बर्डन ऑफ प्रूफ: 1963 के अधिनियम ने प्रतिकूल कब्जे के बर्डन ऑफ प्रूफ को दावेदार पर स्थानांतरित कर दिया, जिससे वास्तविक मालिक की स्थिति मजबूत हो गई।
 - ◆ स्वामित्व का अधिग्रहण: लिमिटेड एक्ट, 1963 के तहत कोई भी व्यक्ति जिसके पास 12 वर्ष से अधिक समय से निजी ज़मीन या 30 वर्ष से अधिक समय से सरकारी ज़मीन है, वह उस संपत्ति का मालिक बन सकता है। अतः कथन 2 सही नहीं है।
 - प्रतिकूल कब्जे का दावा करने हेतु कब्जे को आवश्यक वैधानिक अवधि के लिये खुला, निरंतर और वास्तविक मालिक के अधिकारों के प्रतिकूल होना चाहिये।

146. निम्नलिखित कथनों में से कौन सा/से सही नहीं है/हैं ?

1. दूसरी अंतर-सरकारी वार्ता समिति (INC) की बैठक ने भूजल संदूषण से निपटने और इसके उन्मूलन हेतु एक विश्वव्यापी समझौते पर ठोस चर्चा के लिये रूपरेखा तैयार करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
2. अंतर सरकारी वार्ता समिति (INC) की स्थापना वर्ष 2022 में संयुक्त राष्ट्र विकास सभा के 5वें सत्र में की गई थी।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- A. केवल 1
- B. केवल 2
- C. 1 और 2 दोनों
- D. न तो 1 और न ही 2

उत्तर: A

व्याख्या:

- दूसरी अंतर-सरकारी वार्ता समिति (INC-2) का उद्देश्य प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिये वैश्विक समझौते पर वार्ता के लिये मंच प्रदान करना है ताकि पारिस्थितिकी तंत्र, प्रजातियों और मानवता को रैखिक प्लास्टिक अर्थव्यवस्था के गंभीर प्रभावों से बचाया जा सके। अतः कथन 1 सही नहीं है।

- INC-2 का प्राथमिक एजेंडा प्रक्रिया के नियमों को अपनाना था। ये नियम विभिन्न पहलुओं जैसे कि बातचीत की प्रक्रिया, निर्णय लेने की प्रक्रिया (सर्वसम्मति या मतदान) और निर्णय लेने के लिये अधिकृत संस्थाओं को नियंत्रित करते हैं।
- INC की स्थापना फरवरी 2022 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा (UNEA-5.2) के 5वें सत्र में हुई थी। अतः कथन 2 सही है।

147. अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. इसने शांतिपूर्ण वैश्विक हवाई नेविगेशन के लिये मानकों और प्रक्रियाओं की नींव रखी।
2. ICA कन्वेंशन पर शिकागो कन्वेंशन (1944) के दौरान हस्ताक्षर किये गए थे।
3. भारत इसके 193 सदस्यों में से एक है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं ?

- A. केवल एक
- B. केवल दो
- C. केवल तीन
- D. कोई नहीं

उत्तर: C

व्याख्या:

अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन:

- यह संयुक्त राष्ट्र (United Nations-UN) की एक विशिष्ट एजेंसी है, जिसकी स्थापना वर्ष 1944 में राज्यों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन अभिसमय (शिकागो कन्वेंशन) के संचालन तथा प्रशासन के प्रबंधन हेतु की गई थी। अतः कथन 1 सही है।
- ◆ अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संबंधी अभिसमय/कन्वेंशन पर 7 दिसंबर, 1944 को शिकागो में हस्ताक्षर किये गए। इसलिये इसे शिकागो कन्वेंशन भी कहते हैं। अतः कथन 2 सही है।
- ◆ शिकागो कन्वेंशन ने वायु मार्ग के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय परिवहन की अनुमति देने वाले प्रमुख सिद्धांतों की स्थापना की और ICAO के निर्माण का भी नेतृत्व किया।
- इसका एक उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन की योजना एवं विकास को बढ़ावा देना है ताकि विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन की सुरक्षित तथा व्यवस्थित वृद्धि सुनिश्चित हो सके।
- भारत इसके 193 सदस्यों में से है। अतः कथन 3 सही है।
- इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल, कनाडा में है।

148. राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (National Institution Ranking Framework- NIRF) द्वारा जारी विश्वविद्यालयों की निम्नलिखित राष्ट्रीय रैंकिंग पर विचार कीजिये:

1. शिक्षण, शिक्षा और संसाधन
2. अनुसंधान और व्यावसायिक अभ्यास
3. स्नातक परिणाम
4. पहुँच और समावेशिता
5. अनुभूति

विश्वविद्यालयों हेतु राष्ट्रीय रैंकिंग तैयार करते समय उपर्युक्त में से कितने संकेतकों को ध्यान में रखा जाता है ?

- A. केवल दो
- B. केवल तीन
- C. केवल चार
- D. सभी पाँच

उत्तर: D

व्याख्या:

- शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्थापित राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (National Institution Ranking Framework- NIRF) ने हाल ही में विश्वविद्यालयों की राष्ट्रीय रैंकिंग की घोषणा की, जिसे विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा त्रुटिपूर्ण बताया गया है।
- NIRF विभिन्न श्रेणियों में रैंकिंग जारी करता है, जैसे- 'समग्र' (Overall), 'अनुसंधान संस्थान' (Research Institutions), 'विश्वविद्यालय' और 'कॉलेज' (Universities and Colleges), तथा इंजीनियरिंग, प्रबंधन, फार्मैसी, कानून आदि जैसे विशिष्ट विषय।
- NIRF द्वारा संस्थानों की रैंकिंग उनके कुल अंकों के आधार पर की जाती है, इस स्कोर/अंक को निर्धारित करने के लिये निम्नलिखित पाँच संकेतकों का उपयोग किया जाता है:
 - ◆ शिक्षण, शिक्षा और संसाधन (Teaching, Learning and Resources- TLR)- भारांक 30 फीसदी।
 - ◆ अनुसंधान और व्यावसायिक अभ्यास (Research and Professional Practices- RP)- भारांक 30 फीसदी।
 - ◆ स्नातक परिणाम (Graduation Outcomes- GO)- भारांक 20 फीसदी।
 - ◆ पहुँच और समावेशिता (Outreach and Inclusivity- OI)- भारांक 10 फीसदी।
 - ◆ समकक्ष अनुभूति (Peer Perception)- भारांक 10 फीसदी।

149. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. भारत में दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया की निगरानी और विनियमन मानव संसाधन मंत्रालय के तहत केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण द्वारा किया जाता है।
2. किशोर न्याय अधिनियम, 2021 ने ज़िला मजिस्ट्रेट और सिविल कोर्ट दोनों को बच्चे को दत्तक ग्रहण पर आदेश जारी करने के लिये अधिकृत किया।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?

- A. केवल 1
- B. केवल 2
- C. 1 और 2 दोनों
- D. न तो 1 और न ही 2

उत्तर: D

व्याख्या:

भारत में दत्तक ग्रहण:

- यह एक कानूनी और भावनात्मक प्रक्रिया है जिसमें ऐसे बच्चे की देखभाल की ज़िम्मेदारी स्वीकार करना शामिल है जो दत्तक ग्रहण वाले माता-पिता से जैविक रूप से संबंधित नहीं है।
- भारत में दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया की निगरानी और विनियमन केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (Central Adoption Resource Authority- CARA) द्वारा किया जाता है, जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का हिस्सा है। अतः कथन 1 सही नहीं है।
- CARA भारतीय बच्चों को दत्तक ग्रहण के लिये नोडल निकाय है और इसे देश में दत्तक ग्रहण की निगरानी करने एवं विनियमन का अधिकार है।
- CARA को वर्ष 2003 में भारत सरकार द्वारा अनुसमर्थित हेग कन्वेंशन ऑन इंटरकंट्री एडॉप्शन, 1993 के प्रावधानों के अनुसार अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण (Adoptions) की गतिविधियों से निपटने के लिये केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में भी नामित किया गया है।

हालिया बदलाव:

- संसद ने किशोर न्याय अधिनियम, 2015 में संशोधन करने के लिये किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2021 पारित किया।
- मुख्य बदलावों में किशोर न्याय अधिनियम की धारा 61 के तहत दत्तक ग्रहण (दत्तक ग्रहण) के आदेश जारी करने के लिये ज़िला मजिस्ट्रेट और अतिरिक्त ज़िला मजिस्ट्रेट की सहमति अनिवार्य कर दी गई है।
- इससे पहले किशोर न्याय अधिनियम, 2015 में किसी बच्चे को दत्तक ग्रहण के मामले में सिविल कोर्ट द्वारा दत्तक ग्रहण का आदेश जारी करना अंतिम निर्णय हुआ करता था। अतः कथन 2 सही नहीं है।

150. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

कथन-I: रेलवे सुरक्षा आयोग (CRS) एक सरकारी निकाय है जो देश में रेलवे सुरक्षा प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है।
कथन-II: CRS का प्रशासनिक नियंत्रण रेल मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा सही है ?

- कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं तथा कथन-II कथन-I की सही व्याख्या है।
- कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं तथा कथन-II कथन-I की सही व्याख्या नहीं है।
- कथन-I सही है, किंतु कथन-II सही नहीं है।
- कथन-I गलत है, किंतु कथन-II सही है।

उत्तर: (C)

व्याख्या:

- यह एक सरकारी निकाय है जो देश में रेलवे सुरक्षा प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है। अतः कथन 1 सही है।
- यह रेलवे अधिनियम, 1989 में निर्दिष्ट निरीक्षणत्मक, जाँच और सलाहकारी कार्यों के साथ-साथ रेल यात्रा एवं संचालन जैसे सुरक्षा मामलों से संबंधित है।
- इसका मुख्यालय लखनऊ, उत्तर प्रदेश में है।
- यह रेल मंत्रालय के बजाय नागरिक उड्डयन मंत्रालय (Ministry of Civil Aviation- MoCA) के प्रशासनिक नियंत्रण में है। अतः कथन II सही नहीं है।
- इसका कारण CRS को देश के रेलवे प्रतिष्ठान के प्रभाव से अलग रखना और हितों के टकराव को रोकना है।

151. राजद्रोह के अपराध के लिये दंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. यह एक गैर जमानती अपराध है। इसमें धारा 124A के अंतर्गत तीन वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है, साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
2. इस कानून के अंतर्गत आरोपित व्यक्ति को सरकारी नौकरी से प्रतिबंधित कर दिया जाता है।
3. आरोपित व्यक्ति के पासपोर्ट को जब्त कर लिया जाता है, साथ ही आवश्यकता पड़ने पर उसे न्यायालय में पेश होना अनिवार्य होता है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं ?

- केवल एक
- केवल दो
- सभी तीन
- कोई भी नहीं

उत्तर: C

व्याख्या:

राजद्रोह:

● आईपीसी की धारा 124A:

- ◆ भारतीय दंड संहिता की धारा 124 A के अनुसार, "बोले या लिखे गए शब्दों या संकेतों द्वारा या दृश्य प्रस्तुति द्वारा, जो कोई भी भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमान पैदा करेगा या पैदा करने का प्रयत्न करेगा, असंतोष (Disaffection) उत्पन्न करेगा या करने का प्रयत्न करेगा, उसे आजीवन कारावास या तीन वर्ष तक की कैद और जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जाएगा।"
- ◆ प्रावधान के अनुसार, असंतोष (Disaffection) शब्द में निष्ठाहीनता और शत्रुता की भावनाएँ शामिल हैं। हालाँकि घृणा, अवमानना या असंतोष उत्पन्न करने का प्रयास किये बिना की गई टिप्पणी इस धारा के तहत अपराध नहीं होगी।

■ देशद्रोह के अपराध के लिये दंड:

- राजद्रोह गैर-जमानती अपराध है। राजद्रोह के अपराध में तीन वर्ष से लेकर उन्नकैद तक की सजा हो सकती है और इसके साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अतः कथन 1 सही है।
- इस कानून के तहत आरोपित व्यक्ति को सरकारी नौकरी प्राप्त करने से रोका जा सकता है। अतः कथन 2 सही है।
- आरोपित व्यक्ति के पासपोर्ट को जब्त कर लिया जाता है, साथ ही आवश्यकता पड़ने पर उसे न्यायालय में पेश होना अनिवार्य होता है। अतः कथन 3 सही है।

152. छत्रपति शिवाजी महाराज के अधीन केंद्रीय प्रशासन सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. यह प्रशासन की दक्कन शैली से अत्यधिक प्रेरित था।
2. राजा राज्य का सर्वोच्च प्रमुख होता था जिसे आठ मंत्रियों के एक समूह द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी जिन्हें 'अष्टप्रधान' के रूप में जाना जाता था।
3. पेशवा, जिसे मुख्य प्रधान के रूप में भी जाना जाता था, मूल रूप से राजा शिवाजी की सलाहकार परिषद का नेतृत्व करता था।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं ?

- केवल एक
- केवल दो
- सभी तीन
- कोई भी नहीं

उत्तर: C

व्याख्या:

शिवाजी के अधीन प्रशासन:

- केंद्रीय प्रशासन:
 - ◆ इसकी स्थापना शिवाजी द्वारा प्रशासन की सुदृढ़ प्रणाली हेतु की गई थी जो प्रशासन की दक्कन शैली से बहुत प्रेरित थी। अतः कथन 1 सही है।
 - ◆ अधिकांश प्रशासनिक सुधार अहमदनगर में मलिक अंबर सुधारों से प्रेरित थे।
 - ◆ राजा राज्य का सर्वोच्च प्रमुख होता था जिसे आठ मंत्रियों के एक समूह द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी जिन्हें 'अष्टप्रधान' के रूप में जाना जाता था। अतः कथन 2 सही है।
 - ◆ पेशवा, जिसे मुख्य प्रधान के रूप में भी जाना जाता है, मूल रूप से राजा शिवाजी की सलाहकार परिषद का नेतृत्व करता था। अतः कथन 3 सही है।

153. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) जनगणना अधिनियम, 1948 के तहत तैयार किया जाता है और इसमें देश के सभी सामान्य निवासियों की सूची होती है।
2. NPR के प्रयोजन के लिये एक सामान्य निवासी वह व्यक्ति है जो कम-से-कम 6 महीने के लिये एक स्थान पर रहता है और वहाँ (कम से कम) 6 महीने तक रहने का इरादा रखता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?

- A. केवल 1
- B. केवल 2
- C. 1 और 2 दोनों
- D. न तो 1 और न ही 2

उत्तर: B

व्याख्या:

- राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) एक डेटाबेस है जिसमें देश के सभी सामान्य निवासियों की सूची होती है।
- ◆ NPR के प्रयोजन के लिये सामान्य निवासी वह व्यक्ति है जो किसी स्थान पर 6 महीने या उससे अधिक समय से रह रहा है और वहाँ 6 महीने या उससे अधिक समय तक रहने का इरादा रखता है। अतः कथन 2 सही है।
- इसका उद्देश्य देश में रहने वाले लोगों का एक व्यापक पहचान डेटाबेस तैयार करना है।
- ◆ यह जनगणना के "मकान सूचीकरण" चरण के दौरान घर-घर जाकर गणना के माध्यम से उत्पन्न होता है।

- ◆ NPR पहली बार वर्ष 2010 में शुरू किया गया था। इसे वर्ष 2015 में अपडेट किया गया था और इसमें पहले से ही 119 करोड़ निवासियों का विवरण है।

- NPR नागरिकता अधिनियम 1955 और नागरिकता नियम, 2003 (नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना) के प्रावधानों के तहत तैयार किया गया है। अतः कथन 1 सही नहीं है।

- ◆ प्रत्येक "भारत के सामान्य निवासी" के लिये NPR में पंजीकरण कराना अनिवार्य है।

154. भारत में हिरासत में यातना की रोकथाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. पिछले पाँच वर्षों में हिरासत में सबसे अधिक मौतें गुजरात में होने की सूचना मिली है, इसके बाद महाराष्ट्र का स्थान है।
2. भारतीय साक्ष्य अधिनियम-1872 की धारा 2 घोषित करती है कि धमकियों, वादों या प्रलोभनों के माध्यम से प्राप्त इकबालिया बयान अदालत में स्वीकार्य नहीं हैं।
3. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, जिसमें यातना और अन्य क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक उपचार या दंड से मुक्त होने का अधिकार भी समाहित है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?

- A. केवल 1 और 3
- B. केवल 2
- C. केवल 3
- D. 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

व्याख्या:

- पिछले पाँच वर्षों में हिरासत में सबसे अधिक मौतें (80) गुजरात में दर्ज की गई हैं, इसके बाद महाराष्ट्र (76), उत्तर प्रदेश (41), तमिलनाडु (40) और बिहार (38) का स्थान है। अतः कथन 1 सही है।
- भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 24 में यह घोषित किया गया है कि अभियुक्त द्वारा जाँच एजेंसियों की धमकी, वादे या प्रलोभन के कारण दिये गए सभी इकबालिया बयान कानून की अदालत में स्वीकार्य नहीं होंगे। यह धारा मुख्य रूप से अभियुक्त को उसकी इच्छा के विरुद्ध संस्वीकृति देने से रोकने का काम करती है। अतः कथन 2 सही है।
- भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, जिसमें यातना तथा अन्य क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या सजा से मुक्त होने का अधिकार शामिल है। अतः कथन 3 सही है।

155. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. परयांकंडियाल बनाम के. देवी और अन्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि धर्म के प्रभाव के कारण बहुविवाह को हिंदू संस्कृति का अंग बनने की अनुमति नहीं थी।
2. जावेद और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मुस्लिम कानून बहुविवाह की अनुमति प्रदान करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?

- A. केवल 1
- B. केवल 2
- C. 1 और 2 दोनों
- D. न तो 1 और न ही 2

उत्तर: C

व्याख्या:

बहुविवाह से संबंधित न्यायिक दृष्टिकोण:

- परयांकंडियाल बनाम के. देवी और अन्य (1996) :
 - ◆ सर्वोच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि एक विवाह वाले रिश्ते हिंदू समाज के मानक और विचारधारा थे, जो दूसरे विवाह की निंदा और उसका तिरस्कार करते थे।
 - ◆ धर्म के प्रभाव के कारण बहुविवाह को हिंदू संस्कृति का अंग नहीं बनने दिया गया। अतः कथन 1 सही है।
- बॉम्बे राज्य बनाम नरसु अप्पा माली (1951) :
 - ◆ बॉम्बे उच्च न्यायालय ने निर्णय सुनाया कि बॉम्बे (हिंदू द्विविवाह रोकथाम) अधिनियम, 1946 भेदभावपूर्ण नहीं था।
 - ◆ सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय सुनाया कि एक राज्य विधायिका के पास लोक कल्याण और सुधार उपायों को लागू करने का अधिकार है, भले ही वह हिंदू धर्म या रीति-रिवाजों का उल्लंघन करता हो।
- जावेद और अन्य बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य (2003) :
 - ◆ सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया कि स्वतंत्रता, सामाजिक सद्भाव, गरिमा और कल्याण अनुच्छेद 25 के अंतर्गत आते हैं।
 - ◆ मुस्लिम कानून चार महिलाओं से विवाह की अनुमति प्रदान करता है, लेकिन यह अनिवार्य नहीं है।
 - ◆ यह चार महिलाओं से शादी नहीं करने के लिये धार्मिक प्रथा का उल्लंघन नहीं होगा। अतः कथन 2 सही है।

156. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. केंद्र सरकार प्रवर्तन निदेशालय (ED) के प्रमुख के कार्यकाल को दो साल की अवधि से आगे नहीं बढ़ा सकती है।
2. प्रवर्तन निदेशालय (ED) को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002 (PMLA) के प्रावधानों को क्रियान्वित करने की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?

- A. केवल 1
- B. केवल 2
- C. 1 और 2 दोनों
- D. न तो 1 और न ही 2

उत्तर: B

व्याख्या:

प्रवर्तन निदेशालय

- हाल ही में केंद्र ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया है कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) के प्रमुख का कार्यकाल नवंबर 2023 से आगे जारी नहीं रहेगा।
- नवंबर 2021 में भारत के राष्ट्रपति ने दो अध्यादेश जारी किये, जिसमें तीन वर्ष के विस्तार की संभावना के साथ ED के निदेशक के कार्यकाल को दो साल से बढ़ाकर पाँच साल करने की अनुमति दी गई।
- इस कदम को सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा, जिसने ED प्रमुख के विस्तार की अनुमति दी लेकिन केवल दुर्लभ और असाधारण मामलों में छोटी अवधि के लिये।
 - ◆ सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि दो साल की अवधि के बाद ED को नियुक्त करने की केंद्र सरकार की शक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं है। अतः कथन 1 सही नहीं है।
- ED एक बहु-अनुशासनात्मक संगठन है जो मनी लॉन्ड्रिंग के अपराधों और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन की जाँच करता है।
 - ◆ यह वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन कार्य करता है।
- प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002 (PMLA) : FATF इंडिया की सिफारिशों के बाद PMLA अधिनियमित किया गया।
 - ◆ ED को अपराध की आय से प्राप्त संपत्ति का पता लगाने एवं जाँच करने, संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क करने और विशेष अदालत द्वारा अपराधियों के खिलाफ मुकदमा चलाने तथा संपत्ति की जब्ती सुनिश्चित करने हेतु PMLA के प्रावधानों को क्रियान्वित करने की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है। अतः कथन 2 सही है।

157. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

- राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन (National e-Governance Division- NeGD) ने CISO डीप-डाइव प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया।
- यह प्रशिक्षण कार्यक्रम साइबर सुरक्षित भारत पहल (Cyber Surakshit Bharat initiative- CSBI) के तहत आयोजित कार्यशाला का हिस्सा है।
- CSBI को NeGD के सहयोग से इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा लॉन्च किया गया था।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?

- केवल 1
- केवल 2
- 1, 2 और 3
- केवल 1 और 3

उत्तर: C

व्याख्या:

- नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीजन (NeGD) ने अपनी क्षमताओं में बढ़ोतरी के उद्देश्य से एक विशेष परियोजना के तहत 36वें मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (Chief Information Security Officers- CISO) विस्तृत विश्लेषण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। नई दिल्ली के भारतीय लोक प्रशासन संस्थान में आयोजित इस अभ्यास सत्र में केंद्रीय मंत्रालयों और राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के 24 प्रतिभागियों ने भाग लिया। अतः कथन 1 सही है।
- यह प्रशिक्षण कार्यक्रम साइबर सुरक्षित भारत पहल के तहत आयोजित कार्यशालाओं की शृंखला का एक हिस्सा है। अतः कथन 2 सही है।
- साइबर सुरक्षित भारत पहल: साइबर सुरक्षित भारत पहल की संकल्पना साइबर अपराध के बारे में जागरूकता फैलाने और सभी सरकारी विभागों में मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों (CISOs) एवं अग्रिम पंक्ति के सूचना प्रौद्योगिकी अधिकारियों की क्षमता निर्माण के मिशन के साथ की गई थी।
- इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Electronics and Information Technology- MeitY) द्वारा वर्ष 2018 में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन (NeGD) तथा भारत में विभिन्न उद्योग भागीदारों के सहयोग से लॉन्च किया गया था। अतः कथन 3 सही है।

मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी विस्तृत विश्लेषण प्रशिक्षण कार्यक्रम: यह प्रशिक्षण सार्वजनिक निजी भागीदारी (Public Private Partnership- PPP) मॉडल के तहत सरकार और उद्योग संघों के बीच अपनी तरह की पहली साझेदारी है।

उद्देश्य:

- साइबर खतरों के उभरते परिदृश्य को लेकर जागरूकता उत्पन्न करना।
- साइबर संबंधित समाधानों की गहन समझ प्रदान करना।
- साइबर सुरक्षा से संबंधित रूपरेखा, दिशा-निर्देश और नीतियों का निर्माण करना।
- सफलता और असफलताओं से सीखने के लिये सर्वोत्तम अभ्यासों को साझा करना।
- साइबर सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर उनके संबंधित कार्यात्मक क्षेत्र में सूचित निर्णय लेने के लिये महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करना।

158. गैर-संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिये राष्ट्रीय कार्यक्रम (National Programme for Prevention & Control of Non-Communicable Diseases- NP-NCD) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

- राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर कार्यक्रम की निगरानी और प्रबंधन के लिये एकल राष्ट्रीय NCD इकाइयाँ स्थापित की गई हैं।
- सामान्य NCD के शुरुआती निदान, उपचार और अनुवर्ती कार्रवाई हेतु सेवाएँ प्रदान करने के लिये जिला स्तर पर NCD क्लीनिक स्थापित किये जा रहे हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?

- केवल 1
- केवल 2
- 1 और 2 दोनों
- न तो 1 और न ही 2

उत्तर: A

व्याख्या:

- NPDCS के तहत कार्यक्रम प्रबंधन और निगरानी के लिये राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर NCD इकाइयाँ स्थापित की जा रही हैं। अतः कथन 1 सही है।
- इस कार्यक्रम के तहत NCD क्लीनिकों में आने वाले रोगियों के लिये मुफ्त नैदानिक सुविधाएँ और दवाएँ उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है।
- सामान्य गैर-संचारी रोगों के शीघ्र निदान, उपचार और अनुवर्ती कार्रवाई के लिये सेवाएँ प्रदान करने हेतु जिला और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) स्तरों पर गैर-संचारी रोग क्लीनिक स्थापित किये जा रहे हैं। अतः कथन 2 सही नहीं है।

159. विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (FCRA), 2010 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. विदेशी दान प्राप्त करने के इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति या NGO को अधिनियम के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता है।
2. अधिनियम चुनावों, पत्रकारों और उम्मीदवारों के लिये विदेशी धन प्राप्त करने पर रोक लगाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?

- A. केवल 1
- B. केवल 2
- C. 1 और 2 दोनों
- D. न तो 1 और न ही 2

उत्तर: C

व्याख्या:

विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (FCRA), 2010:

● परिचय:

◆ FCRA को वर्ष 1976 में आपातकाल के दौरान इस आशंका के माहौल में अधिनियमित किया गया था कि विदेशी शक्तियाँ स्वतंत्र संगठनों के वित्त पोषण के माध्यम से भारत के मामलों में हस्तक्षेप कर रही थीं।

■ ये चिंताएँ वर्ष 1969 में ही संसद में व्यक्त की जा चुकी थीं।

◆ कानून ने व्यक्तियों और संघों से विदेशी दान को विनियमित करने की मांग की ताकि वह "एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के मूल्यों के अनुरूप" कार्य कर सकें।

● उद्देश्य:

◆ विदेशी दान प्राप्त करने के इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति या NGO को अधिनियम के तहत पंजीकृत होने, विदेशी धन की प्राप्ति के लिये एक बैंक खाता खोलने और उस धन का उपयोग केवल उसी उद्देश्य के लिये करने की आवश्यकता है जिसके लिये प्राप्त किया गया है और जैसा कि अधिनियम में निर्धारित किया गया है। अतः कथन 1 सही है।

◆ यह अधिनियम चुनाव के लिये उम्मीदवारों, पत्रकारों या अखबारों और मीडिया प्रसारण कंपनियों, न्यायाधीशों तथा सरकारी कर्मचारियों, विधायिका एवं राजनीतिक दलों के सदस्यों या उनके पदाधिकारियों और राजनीतिक प्रकृति के संगठनों द्वारा विदेशी धन प्राप्त करने पर रोक लगाता है। अतः कथन 2 सही है।

160. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. एकाधिकार और अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम, 1969 (MRTP अधिनियम) को निरस्त कर दिया गया और प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।
2. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) एक अर्द्ध-न्यायिक निकाय है जो संबंधित अधिकारियों को सलाह देता है और अन्य मामलों से भी निपटता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?

- A. केवल 1
- B. केवल 2
- C. 1 और 2 दोनों
- D. न तो 1 और न ही 2

उत्तर: C

व्याख्या:

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI):

● परिचय:

◆ यह प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 को कार्यान्वित करने के लिये उत्तरदायी भारत सरकार का एक वैधानिक निकाय है। इसका विधिवत गठन मार्च 2009 में किया गया था।

◆ राघवन समिति की सिफारिशों के आधार पर एकाधिकार और अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम, 1969 (MRTP अधिनियम) को निरस्त कर दिया गया तथा इसे प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। अतः कथन 1 सही है।

● संरचना:

◆ आयोग में एक अध्यक्ष और छह सदस्य होते हैं जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है।

◆ भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) एक अर्द्ध-न्यायिक निकाय है जो संबंधित अधिकारियों को सलाह देता है और अन्य मामलों से भी निपटता है। अतः कथन 2 सही है।

161. निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा "ब्लूवाँशिंग" की सही व्याख्या करता है ?

- A. इस प्रक्रिया में भ्रामक तरीके से उपभोक्ताओं को यह विश्वास दिलाने का प्रयास किया जाता है कि कोई कंपनी किस प्रकार से वास्तव में डिजिटल रूप से अधिक नैतिक और सुरक्षित है।
- B. यह कंपनियों द्वारा नीले रंग का उपयोग करके अपने उत्पादों को बढ़ावा देने के लिये उपयोग की जाने वाली मार्केटिंग रणनीति है।

- C. यह प्रौद्योगिकी उद्योग में साइबर सुरक्षा को प्राथमिकता देने वाली कंपनियों का वर्णन करने के लिये उपयोग की जाती है।
- D. यह शब्द नीले रंग के कपड़े को धोने की प्रक्रिया का वर्णन करने के लिये प्रयोग किया जाता है।

उत्तर: A

व्याख्या:

ब्लूवॉशिंग:

- ब्लूवॉशिंग प्रक्रिया में भ्रामक तरीके से उपभोक्ताओं को यह विश्वास दिलाने का प्रयास किया जाता है कि कोई कंपनी किस प्रकार से वास्तव में डिजिटल रूप से अधिक नैतिक और सुरक्षित है। अतः विकल्प A सही है।
- ◆ यह बिल्कुल ग्रीनवाशिंग की तरह है लेकिन यह पर्यावरण के बजाय सामाजिक और आर्थिक जिम्मेदारी पर अधिक केंद्रित है।
- ◆ ग्रीनवाशिंग भ्रामक विपणन का एक रूप है जिसमें एक कंपनी झूठा दावा करती है कि उसके उत्पाद, नीतियाँ या कार्यक्रम पर्यावरण के अनुकूल या लाभकारी हैं, जबकि ये व्यवहार में पर्यावरण की सहायता हेतु बहुत कम या कुछ भी नहीं करते हैं।
- 'ब्लूवॉशिंग' शब्द का इस्तेमाल पहली बार उन कंपनियों हेतु किया गया था जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट एवं इसके सिद्धांतों पर हस्ताक्षर किये थे लेकिन कोई वास्तविक नीतिगत सुधार नहीं किया था।
- ◆ यह कार्य प्रायः कंपनियों द्वारा अपने डेटा गोपनीयता और सुरक्षा के बारे में अस्पष्ट या निराधार दावा या कृत्रिम बुद्धिमत्ता की रक्षा एवं सुरक्षा के बारे में दावा कर किया जाता है।

162. 'हेट स्पीच' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. भारत का संविधान केवल धर्म के आधार पर हेट स्पीच पर प्रतिबंध लगाता है, किसी अन्य आधार पर नहीं।
2. राज्य हेट स्पीच की घटना पर स्वतः संज्ञान से प्राथमिकी दर्ज कर सकते हैं एवं अपराधी के खिलाफ मामला दर्ज करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?

- A. केवल 1
- B. केवल 2
- C. 1 और 2 दोनों
- D. न तो 1 और न ही 2

उत्तर: B

व्याख्या:

हेट स्पीच:

- भारत में हेट स्पीच से तात्पर्य ऐसी अभिव्यक्तियों से है जिसका उद्देश्य व्यक्तियों के बीच घृणा, शत्रुता या वैमनस्य को बढ़ावा देना है।
- भारत का संविधान धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान सहित विभिन्न आधारों पर हेट स्पीच का निषेध करता है। अतः कथन 1 सही नहीं है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों को हेट स्पीच की घटनाओं पर स्वतः संज्ञान लेते हुए प्राथमिकी दर्ज करने और शिकायत दर्ज होने की प्रतीक्षा किये बिना अपराधियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया है। अतः कथन 2 सही है।

163. नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सबस्टेंस एक्ट 1985 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?

1. अधिनियम के लागू होने के बाद से इसमें एक बार भी संशोधन नहीं किया गया है।
2. अधिनियम के तहत भाँग प्रतिबंधित नहीं है।
3. अधिनियम चिकित्सा और वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिये अफीम की खेती और बिक्री की अनुमति प्रदान करता है।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- A. केवल 2 और 3
- B. केवल 3
- C. केवल 1 और 2
- D. केवल 1 और 3

उत्तर: a

व्याख्या:

नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सबस्टेंस एक्ट 1985:

- यह वर्ष 1985 में अधिनियमित किया गया था और देश में ड्रग्स और उनकी तस्करी से संबंधित है।
- ◆ अधिनियम के बाद से वर्ष 1988, 2001 और 2014 में तीन बार संशोधन किया गया है। अतः कथन 1 सही नहीं है।
- अधिनियम भाँग, हेरोइन, अफीम आदि सहित अनेक मादक दवाओं या मनःप्रभावी पदार्थों के उत्पादन, निर्माण, बिक्री, खरीद, परिवहन और उपभोग पर प्रतिबंध लगाता है।
- ◆ हालाँकि अधिनियम के तहत भाँग प्रतिबंधित नहीं है। अतः कथन 2 सही है।

- NDPS अधिनियम की धारा 20 अधिनियम में परिभाषित भाँग के उत्पादन, निर्माण, बिक्री, खरीद, आयात और अंतर-राज्य निर्यात के लिये दंड का प्रावधान करती है। निर्धारित सजा जब्त दवाओं की संख्या पर आधारित है।
- यह कुछ मामलों में मौत की सजा का भी प्रावधान करती है जहाँ एक व्यक्ति बार-बार अपराध करता है।
- NDPS अधिनियम और वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिये अफीम पोस्ता की खेती की अनुमति और विनियमन करने के लिये केंद्र सरकार को अधिकार देता है। अतः कथन 3 सही है।

164. आभासी डिजिटल परिसंपत्ति (Virtual Digital Assets- VDA) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. उन्हें आयकर अधिनियम, 1961 के तहत नए जोड़े गए खंड के तहत परिभाषित किया गया है।
2. इन्हें अंतर्निहित मूल्य के साथ क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करके बनाया गया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?

- A. केवल 1
- B. केवल 2
- C. 1 और 2 दोनों
- D. न तो 1 और न ही 2

उत्तर: C

व्याख्या:

आभासी डिजिटल परिसंपत्ति (Virtual Digital Assets- VDA):

- सरकार ने केंद्रीय बजट 2022-23 में आभासी डिजिटल परिसंपत्ति (Virtual Digital Assets) पर टैक्स लगाने और उन पर नजर रखने के उद्देश्य से नए प्रावधान पेश किये हैं। करारधान के ढाँचे के साथ बजट ने पहली बार आभासी डिजिटल परिसंपत्ति को परिभाषित किया।
- ◆ इसने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 के तहत नए सम्मिलित खंड (47A) में आभासी डिजिटल संपत्ति को परिभाषित किया है। अतः कथन 1 सही है।
- प्रस्तावित नए खंड के अनुसार, एक आभासी डिजिटल परिसंपत्ति का अर्थ क्रिप्टोग्राफिक माध्यमों से किसी भी जानकारी, कोड, संख्या या टोकन (न तो भारतीय मुद्रा में या न किसी विदेशी मुद्रा में) उत्पन्न करना है। अतः कथन 2 सही है।

- आभासी डिजिटल परिसंपत्ति का अर्थ है क्रिप्टोकॉरेसी, DeFi (विकेंद्रीकृत वित्त) और नॉन-फंजिबल टोकन (NFT)।
- अप्रैल 2022 से भारत में क्रिप्टोकॉरेसी के लेन-देन से होने वाली आय पर 30% आयकर लागू हुआ।
- जुलाई 2022 से क्रिप्टोकॉरेसी से संबंधित स्रोतों पर 1% कर कटौती के नियम लागू हुए।

165. POCSO अधिनियम, 2012 के तहत प्राथमिकी के प्रावधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. किसी भी प्रकार के अपराध होने की आशंका अथवा अपराध संबंधी सूचना वाले व्यक्ति को विशेष किशोर पुलिस इकाई अथवा स्थानीय पुलिस को इसकी जानकारी प्रदान करनी चाहिये।
2. अधिनियम की धारा 21 में यह भी कहा गया है कि किसी अपराध की रिपोर्ट नहीं करने पर छह महीने तक की कैद, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
3. इस अधिनियम के तहत शिकायत प्राप्त होने पर एक रिपोर्ट दर्ज करना अनिवार्य है, भले ही रिपोर्टकर्ता एक बच्चा क्यों न हो।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं ?

- A. केवल 1 और 2
- B. केवल 1 और 3
- C. केवल 2 और 3
- D. 1, 2 और 3

उत्तर: D

व्याख्या:

POCSO अधिनियम, 2012 के तहत प्राथमिकी का प्रावधान:

- अधिनियम की धारा 19 में कहा गया है कि किसी भी प्रकार के अपराध होने की आशंका अथवा अपराध संबंधी सूचना वाले व्यक्ति को विशेष किशोर पुलिस इकाई अथवा स्थानीय पुलिस को इसकी जानकारी प्रदान करनी चाहिये। अतः कथन 1 सही है।
- ◆ इस अनुभाग के तहत लिखित रूप में प्राथमिकी दर्ज करना अनिवार्य है।
- अधिनियम की धारा 21 में यह भी कहा गया है कि किसी अपराध की रिपोर्ट नहीं करने पर छह महीने तक की कैद, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। अतः कथन 2 सही है।
- ◆ इसलिये, इस अधिनियम के तहत शिकायत प्राप्त होने पर एक रिपोर्ट दर्ज करना अनिवार्य है, भले ही रिपोर्टकर्ता एक बच्चा क्यों न हो। अतः कथन 3 सही है।

166. हिमाचल प्रदेश द्वारा पारित सुखाश्रय अधिनियम, 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. यह अधिनियम ऐसे बच्चों जिन्हें देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता है, जिनके माता-पिता नहीं हैं या माता-पिता अक्षम हैं, को अनाथ के रूप में परिभाषित करता है। इसमें ऐसे बच्चे शामिल हैं जिनके पास घर नहीं है या जो जबरन शादी, अपराध या नशीली दवाओं के दुरुपयोग के जोखिम में हैं।
2. प्रत्येक बच्चे और अनाथ का आवर्ती जमा खाता खोला जाएगा एवं राज्य सरकार इन खातों में प्रचलित दरों के अनुसार अंशदान करेगी।
3. अधिनियम के तहत सभी लाभार्थियों को जीवन भर मुफ्त स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध होगी।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?

- A. केवल 1 और 2
- B. केवल 2
- C. 1, 2 और 3
- D. केवल 3

उत्तर: A

व्याख्या:

- यह अधिनियम ऐसे बच्चों जिन्हें देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता है, जिनके माता-पिता नहीं हैं या माता-पिता अक्षम हैं, को अनाथ के रूप में परिभाषित करता है। इसमें ऐसे बच्चे शामिल हैं जिनके पास घर नहीं है या जो जबरन शादी, अपराध या नशीली दवाओं के दुरुपयोग के जोखिम में हैं। अतः कथन 1 सही है।
- प्रत्येक बच्चे और अनाथ का आवर्ती जमा खाता खोला जाएगा एवं राज्य सरकार इन खातों में प्रचलित दरों के अनुसार अंशदान करेगी। अतः कथन 2 सही है।
- अधिनियम में लाभार्थियों के लिये जीवन भर मुफ्त स्वास्थ्य सेवा के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं है। अतः कथन 3 सही नहीं है।

167. गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. अधिनियम के अनुसार, केंद्र सरकार किसी संगठन को आतंकवादी संगठन के रूप में नामित कर सकती है, लेकिन यह व्यक्तियों को आतंकवादी के रूप में नामित नहीं कर सकती है।
2. इसमें अधिकतम सजा के रूप में मृत्युदंड और कारावास शामिल है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?

- A. केवल 1
- B. केवल 2
- C. 1 और 2 दोनों
- D. न तो 1 और न ही 2

उत्तर : B

व्याख्या:

गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (UAPA):

- गैरकानूनी गतिविधियाँ रोकथाम अधिनियम का उद्देश्य भारत में गैरकानूनी गतिविधियों की रोकथाम करना है। इसे वर्ष 1967 में पारित किया गया था।
- अधिनियम के तहत केंद्र सरकार किसी संगठन को आतंकवादी संगठन के रूप में नामित कर सकती है यदि:
 - ◆ आतंकवाद के कृत्यों को करता है या उनमें भाग लेता है,
 - ◆ आतंकवाद के लिये तैयार करता है,
 - ◆ आतंकवाद को बढ़ावा देता है, या
 - ◆ आतंकवाद में शामिल है।
- अधिनियम अतिरिक्त रूप से सरकार को इसी आधार पर व्यक्तियों को आतंकवादी के रूप में नामित करने का अधिकार देता है। अतः कथन 1 सही नहीं है।
- इसमें अधिकतम सजा के रूप में मृत्युदंड और कारावास शामिल है। अतः कथन 2 सही है।
- यह संचालित मामलों की जाँच करने का अधिकार NIA के निरीक्षक या उससे ऊपर के रैंक के उप अधीक्षक या सहायक पुलिस आयुक्त या उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों को देता है।

168. इंटरपोल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया भर में पुलिस बलों की आपराधिक जाँच की सुविधा हेतु स्थापित किया गया था।
2. भारत इंटरपोल के संस्थापक सदस्यों में से एक है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?

- A. केवल 1
- B. केवल 2
- C. 1 और 2 दोनों
- D. न तो 1 और न ही 2

उत्तर: D

व्याख्या:

- इसे वर्ष 1923 में सुरक्षित सूचना-साझाकरण मंच के रूप में स्थापित किया गया था, जो विभिन्न पुलिस बलों से प्राप्त सूचनाओं के संग्रहण और प्रसार के माध्यम से विश्व भर में पुलिस बलों की आपराधिक जाँच की सुविधा प्रदान करता है। अतः कथन 1 सही नहीं है।
 - ◆ इसका मुख्यालय फ्रांस के लियॉन में है।

- इंटरपोल के सदस्य देशों की संख्या 195 है।
- ◆ भारत 15 अक्तूबर, 1949 को इसका सदस्य बना। अतः कथन 2 सही नहीं है।
- यह विभिन्न क्षेत्रों में अपराधियों और पुलिस के रडार के तहत आने वाले लोगों की गतिविधियों पर नजर रखता है और उन पुलिस बलों को सुझाव देता है जिन्होंने या तो इंटरपोल की सहायता मांगी है या जो उसके पास उपलब्ध विवरणों से लाभान्वित हो सकते हैं।
- ◆ इसका उद्देश्य आपराधिक पुलिस बलों के बीच व्यापक संभव पारस्परिक सहायता को बढ़ावा देना है।

169. राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (NAAC) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के तहत एक स्वायत्त निकाय है।
2. यह भारत में उच्च शिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता का आकलन करने के लिये जिम्मेदार है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?

- A. केवल 1
- B. केवल 2
- C. 1 और 2 दोनों
- D. न तो 1 और न ही 2

उत्तर: C

व्याख्या:

- यह भारत में उच्च शिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता का आकलन करने हेतु जिम्मेदार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (University Grants Commission- UGC) के तहत एक स्वायत्त निकाय है। इसकी स्थापना वर्ष 1994 में हुई थी। अतः कथन 1 और 2 सही हैं।
- एक बहुस्तरीय मूल्यांकन प्रक्रिया के माध्यम से, जैसे- पाठ्यक्रम, संकाय, बुनियादी ढाँचे, अनुसंधान और वित्तीय कल्याण आदि मापदंडों के आधार पर A++ से लेकर C तक के ग्रेड प्रदान करता है।

170. विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (FCRA), 1976 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. FCRA के तहत विदेशी दान प्राप्त करने की मांग करने वाले एक NGO को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में बैंक खाता खोलना होगा।
2. NGO के लिये FCRA पंजीकरण 7 वर्ष हेतु वैध है और समाप्ति की तारीख के 3 महीने के भीतर इसे नवीनीकृत किया जाना चाहिये।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?

- A. केवल 1
- B. केवल 2
- C. 1 और 2 दोनों
- D. न तो 1 और न ही 2

उत्तर: D

व्याख्या:

विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (Foreign Contribution Regulation Act- FCRA):

- विदेशी सरकारों द्वारा भारत के आंतरिक मामलों को प्रभावित करने के लिये स्वतंत्र संगठनों की सहायता से किये जाने वाले वित्तपोषण की आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए FCRA को 1976 में आपातकाल के दौरान अधिनियमित किया गया था।
- ◆ इस कानून ने व्यक्तियों और संघों को दिये जाने वाले विदेशी दान को विनियमित करने की मांग की ताकि वे "एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के मूल्यों के अनुरूप" कार्य कर सकें।
- प्रत्येक व्यक्ति या NGO जो विदेशी दान प्राप्त करना चाहता है, के लिये FCRA निम्नलिखित प्रावधान करता है:
 - ◆ अधिनियम के तहत पंजीकृत हो।
 - ◆ भारतीय स्टेट बैंक, दिल्ली में विदेशी धन की प्राप्ति के लिये एक बैंक खाता खोला गया हो। अतः कथन 1 सही नहीं है।
 - ◆ निधियों का उपयोग केवल उसी उद्देश्यों के लिये करना जिसके लिये उन्हें प्राप्त किया गया है और अधिनियम में इनको निर्धारित किया गया है।
- **NGOs** को अपने FCRA पंजीकरण के नवीनीकरण की तिथि समाप्त होने के छह महीने के भीतर आवेदन करना आवश्यक है क्योंकि यह केवल पाँच साल के लिये वैध होता है। अतः कथन 2 सही नहीं है।
 - ◆ सरकार किसी भी NGO का FCRA पंजीकरण रद्द कर सकती है यदि यह पाया जाता है कि NGO, अधिनियम का उल्लंघन कर रहा है या लगातार दो वर्षों तक समाज के लाभ के लिये अपने चुने हुए क्षेत्र में किसी भी उचित गतिविधि में शामिल नहीं हुआ है, या निष्क्रिय रहा हो।
 - ◆ एक बार किसी NGO का पंजीकरण रद्द हो जाने के बाद वह तीन वर्ष हेतु फिर से पंजीकरण के लिये पात्र नहीं होता है।

171. अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (International Criminal Court- ICC) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. ICC 'रोम संविधि' नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संधि द्वारा शासित है।
2. संयुक्त राष्ट्र के तहत अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय मुख्य रूप से राष्ट्रों के बीच विवादों की सुनवाई करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?

- A. केवल 1
- B. केवल 2
- C. 1 और 2 दोनों
- D. न तो 1 और न ही 2

उत्तर: A

व्याख्या:

- रोम संविधि वह संधि है जिसने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) की स्थापना की। इसे 17 जुलाई, 1998 को रोम, इटली में एक राजनयिक सम्मेलन में अपनाया गया था और यह 1 जुलाई, 2002 को लागू हुई। अतः कथन 1 सही है।
- ICC एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ICC अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के विपरीत संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है। यह नरसंहार, युद्ध अपराध, मानवता के खिलाफ अपराध और आक्रामकता के अपराधों सहित विश्व समुदाय हेतु चिंता के सबसे गंभीर अपराधों के आरोपी व्यक्तियों पर कार्यवाही करता है, वारंट जारी करता है एवं उन पर मुकदमा चलाता है। अतः कथन 2 सही नहीं है।

172. भारत में दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?

1. CrPC राज्य सरकार द्वारा लोक अभियोजकों की नियुक्ति और निष्कासन दोनों का प्रावधान करती है।
2. एक आपराधिक न्यायालय का अधिकार क्षेत्र उस स्थान द्वारा निर्धारित किया जा सकता है जहाँ अपराध किया गया था, वह स्थान जहाँ आरोपी व्यक्ति निवास करता है या वह स्थान जहाँ पीड़ित निवास करता है।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- A. केवल 1
- B. केवल 2
- C. 1 और 2 दोनों
- D. न तो 1 और न ही 2

उत्तर: B

व्याख्या:

- CrPC राज्य सरकार द्वारा लोक अभियोजकों की नियुक्ति का प्रावधान करता है, लेकिन CrPC में उनके निष्कासन का उल्लेख नहीं है। अतः कथन 1 सही नहीं है।
- CrPC की धारा 177 में प्रावधान है कि प्रत्येक अपराध की आमतौर पर जाँच की जाएगी और उस पर सुनवाई एक न्यायालय द्वारा की जाएगी, जिसके स्थानीय अधिकार क्षेत्र के भीतर यह अपराध हुआ था।
- ◆ हालाँकि कुछ मामलों में न्यायालय का अधिकार क्षेत्र उस स्थान द्वारा निर्धारित किया जा सकता है जहाँ आरोपी व्यक्ति निवास करता है या वह स्थान जहाँ पीड़ित निवास करता है। अतः कथन 2 सही है।

173. रायसीना डायलॉग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. यह इंडिया फाउंडेशन द्वारा आयोजित "भू-राजनीति और भू-रणनीति" पर एक प्रमुख सम्मेलन है।
2. यह एक बहु-हितधारक कार्यक्रम है, जिसमें क्रॉस-सेक्टरल चर्चाएँ शामिल हैं, इसमें राज्य के प्रमुख और कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं ?

- A. केवल 1
- B. केवल 2
- C. 1 और 2 दोनों
- D. न तो 1 और न ही 2

उत्तर: B

व्याख्या:

- रायसीना डायलॉग के बारे में:
 - ◆ रायसीना डायलॉग भू-राजनीति और भू-अर्थशास्त्र पर भारत का प्रमुख सम्मेलन है जो वैश्विक समुदाय के सामने सबसे चुनौतीपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने के लिये प्रतिबद्ध है।
 - ◆ सम्मेलन की मेज़बानी आब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के साथ साझेदारी में की गई है। अतः कथन 1 सही नहीं है।
 - ◆ वर्ष 2023 में यह "उत्तेजना, अनिश्चितता, अशांति: लाइटहाउस इन द टेम्पेस्ट" विषय के माध्यम से दुनिया की स्थिति पर कब्ज़ा करना चाहता है।

- संवाद को एक बहु-हितधारक, क्रॉस-सेक्टरल चर्चा के रूप में संरचित किया गया है, जिसमें राज्य के प्रमुख, कैबिनेट मंत्री और स्थानीय सरकारी अधिकारी शामिल हैं, जो निजी क्षेत्र, मीडिया तथा शिक्षा जगत के विचारकों को शामिल करता है। **अतः कथन 2 सही है।**

174. आर्मी कोर्ट मार्शल ऑफ इंडिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. कोर्ट मार्शल सामान्यतः सैन्य अधिकारियों से बना होता है जो जज और जूरी दोनों के रूप में काम करते हैं।
2. राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का उपयोग कोर्ट मार्शल द्वारा दिये गए दंड या सजा को क्षमा, परिहार, प्रविलंबन या लघुकरण और विराम हेतु अपनी शक्तियों का उपयोग कर सकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?

- A. केवल 1
- B. केवल 2
- C. 1 और 2 दोनों
- D. न तो 1 और न ही 2

उत्तर: C

व्याख्या:

- कोर्ट मार्शल सामान्यतः सैन्य अधिकारियों से बना होता है जो जज और जूरी दोनों के रूप में काम करते हैं। **अतः कथन 1 सही है।**
- भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत कोर्ट मार्शल द्वारा दिये गए दंड या सजा को क्षमा, परिहार, प्रविलंबन या लघुकरण और विराम हेतु अपनी शक्तियों का उपयोग कर सकता है। **अतः कथन 2 सही है।**
- भारत में कोर्ट मार्शल से संबंधित कानूनी प्रावधान मुख्य रूप से तीन कानूनों द्वारा शासित हैं:
 - ◆ **सेना अधिनियम, 1950:** भारतीय सेना के सदस्यों पर लागू होता है।
 - ◆ **नौसेना अधिनियम, 1957:** भारतीय नौसेना के सदस्यों पर लागू होता है।
 - ◆ **वायु सेना अधिनियम, 1950:** भारतीय वायु सेना के सदस्यों पर लागू होता है।
- **सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिनियम 2007:**
 - ◆ इस अधिनियम ने सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (AFT) की स्थापना की।

- AFT भारत में एक अर्द्ध-न्यायिक निकाय है जो सशस्त्र बलों के कर्मियों की सेवा से के मामलों से संबंधित है।
- कोर्ट मार्शल की कार्यवाही सहित सेवा मामलों से उत्पन्न होने वाले विवादों और अपीलों पर इसका अधिकार क्षेत्र है।

175. आत्म-अभिज्ञान के विरुद्ध सुरक्षा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?

1. आत्म-अभिज्ञान के विरुद्ध संरक्षण मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य दोनों पर लागू होता है।
2. आत्म-अभिज्ञान के विरुद्ध सुरक्षा भौतिक वस्तुओं के अनिवार्य उत्पादन तक विस्तारित नहीं होती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?

- A. केवल 1
- B. केवल 2
- C. 1 और 2 दोनों
- D. न तो 1 और न ही 2

उत्तर: C

व्याख्या:

- **आत्म-अभिज्ञान से संबंधित संवैधानिक प्रावधान:**
 - ◆ अनुच्छेद-20 किसी भी अभियुक्त या दोषी करार दिये गए व्यक्ति, चाहे वह देश का नागरिक हो या विदेशी या कंपनी व परिषद का कानूनी व्यक्ति हो, को मनमाने और अतिरिक्त दंड देने से संरक्षण प्रदान करता है। इस संबंध में तीन प्रावधान हैं:
 - ◆ इसमें कोई पूर्व-कार्योत्तर कानून नहीं, दोहरे दंड का निषेध, कोई आत्म-अभिज्ञान नहीं से संबंधित प्रावधान हैं।
 - ◆ कोई आत्म-अभिज्ञान नहीं (No Self-incrimination): किसी अपराध के लिये अभियुक्त द्वारा किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिये बाध्य नहीं किया जाएगा।
 - ◆ आत्म-अभिज्ञान के विरुद्ध सुरक्षा का मौखिक और लिखित साक्ष्य दोनों रूपों में प्रावधान है। **अतः कथन 1 सही है।**
 - ◆ हालाँकि यह भौतिक वस्तुओं के अनिवार्य उत्पादन पर लागू नहीं होता है, **अतः कथन 2 सही है।**
 - अँगूठे का निशान, हस्ताक्षर अथवा रक्त के नमूने देने की बाध्यता
 - शारीरिक अंगों के प्रदर्शन की बाध्यता
 - इसके अलावा यह केवल आपराधिक कार्यवाही तक ही सीमित है, न कि दीवानी कार्यवाही या गैर-आपराधिक प्रकृति की कार्यवाही तक।